R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 21
01 से 15 अगस्त 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

नई महामारी बना कोचिंग कल्चर...!

कभी न पूरे होने वाले ख्वाब बेच रही हैं कोचिंग इंडस्ट्री

देशभर में मौत के कुएं में गढ़ा जा रहा है देश का भविष्य

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

डायरी

9 | सकते में क्यों है सरकार... ?

अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन सत्ता और संगठन को अनजाना डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि विगत दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र...

राजपथ

10-11 | मप्र में अब एक...

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र में विकास की पंचवर्षीय योजना बनाई है। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश में एक समान और एक साथ विकास होगा। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से कहा है कि...

कर्मचारी हलचल

13 | सीएम मोहन से पदोन्नति...

मप्र के कर्मचारियों का दुर्भाग्य ही है कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस की सरकारों में भी उनकी पदोन्नति का रास्ता नहीं खुल सका है। राजनीतिक नफा नुकसान के फेर में प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार पदोन्नति देने से बच रही है। इसके लिए न्यायालय...

चौसर

18 | अलग भील प्रदेश की मांग

देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गत दिनों बासंवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मप्र, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजस्थान के बांसवाड़ा...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

देश में कोचिंग कल्चर नई महामारी बनकर उभरा है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी शहरी तबका, हर जगह कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। कभी न पूरे होने वाले ख्वाब बेच रही कोचिंग इंडस्ट्री मौत के कुएं में देश का भविष्य गढ़ रही है। नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में घुसा सीवर का पानी भारत में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अभाव के कारण दांव पर लगती जिंदगियों की दर्दनाक कहानी है।

राजनीति

30-31 | कांग्रेस के पास...

लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी दमदारी दिखाई है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि कांग्रेस के पास कई राज्यों में लीडरशिप ही नहीं है। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लगातार 26 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसी ही स्थिति...

महाराष्ट्र

35 | महाराष्ट्र में होगा खेला

महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वहां की राजनीति तेजी से बदल रही है। अभी तक अजित पवार की एकनाथ शिंदे और भाजपा गठबंधन सरकार से खटपट की खबरें आ रही थी। अब शरद पवार के एक कदम ने भी लोगों के कान खड़े कर दिए हैं।

बिहार

38 | मजबूरी या तवज्जो...

लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट...

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

पेरिस तो नहीं... बूचड़खाना बन रहा भोपाल

शायर जलील मानिकपुरी का एक शेर है

दिलचस्प हो गई तिरे चलने से रहगुज़र
उठ-उठ के गर्द-ए-राह लिपटती है राह से ...

शायर की ये पंक्तियां स्मार्ट सिटी भोपाल में इन दिनों सटीक बैठ रही हैं। देश के सबसे सुंदर शहरों में से एक भोपाल को देखने की तमन्ना हर किसी के मन में रहती है। लोगों की मंशा को देखते हुए यहां के माननीयों ने शहर को पेरिस बनाने का खूब दम भरा, लेकिन आज यह शहर किसी बूचड़खाने से कम नहीं है। शहर की सड़कें इस कदर गड्ढायुक्त और जर्जर हो गई हैं कि उनमें मानसून की बारिश से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो जाते हैं। वहीं बारिश रुकते ही शहर में धूल का गुबार इस कदर छा जाता है, जैसे लगता हो यह स्मार्ट सिटी भोपाल नहीं बल्कि कोई गांवखेड़ा हो। भोपाल में नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, बीडीए की करीब 4700 किलोमीटर सड़कें हैं। इनमें से लगभग 50 प्रतिशत से अधिक सड़कें बारिश के कारण जर्जर हो गई हैं। इन्हीं सड़कों को लेकर जहां सियासत गरमा रही है तो वहीं लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर पैदल चलना तक मुश्किल है। सड़कें गड्ढों में गायब हो गई हैं। पिछले दो साल से नगर निगम की खुदाई के कारण सड़कों का रेस्टोरेशन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था। रेस्टोरेशन और मेंटेनेंस दोनों राशि को जोड़ लिया जाए तो शहर में सड़कों पर पिछले साल 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बेमौसम बारिश ने शहर में सड़क निर्माण और उसके मेंटेनेंस में बरती जाने वाली कोताही को उजागर कर दिया है। गर्मी का मौसम आते ही पीडब्ल्यूडी ने अपनी सड़कों के डामरीकरण और रिन्युअल आदि काम शुरू किए। नगर निगम ने भी कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण शुरू किया। लेकिन बारिश होते ही इनकी हकीकत सामने आ गई। किसी सड़क को एक बार बनाने पर कम से कम 3 से 5 साल तक उसकी लाइफ होती है। 3 साल बाद डामरीकरण के एक कोट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन चार इमली, 74 बंगला और शिवाजी नगर जैसे क्षेत्रों में हर साल डामर की परत बिछाते हुए देखा जा सकता है। जब शहर में बारिश होती है तो गड्ढायुक्त सड़कें जानलेवा हो जाती हैं। वहीं जब बारिश थमती है तो सड़कों पर जमी मिट्टी गाड़ियों के पहियों के कारण उड़ने लगती हैं। वर्तमान में धूल इतनी ज्यादा है कि शहर की हर एक सड़क पर दिनभर धूल के गुबार ही नजर आ रहे हैं। इसका नकारात्मक असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंख संबंधी और स्किन इंफेक्शन जैसी दिक्कतें हो रही हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले अस्पतालों में इस तरह की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या डेढ़ गुना से भी ज्यादा हो गई है। हमीदिया अस्पताल में सांस संबंधी परेशानियों के मरीज एक दिन में 90-100 से बढ़कर 140-150 हो गए हैं। जेपी अस्पताल में आंखों की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 50-60 से बढ़कर 70-80 पर पहुंच गई है। स्किन इंफेक्शन के मरीज भी 70-80 से बढ़कर 90-100 पहुंच गए हैं। नगर निगम और पीडब्ल्यूडी सड़कों पर झाड़ू लगवाकर मिट्टी और गिट्टी उठवा रही है। लेकिन किए जा रहे प्रयास वल्लभ भवन रोड, होशंगाबाद रोड और लिंक रोड नंबर एक, दो जैसी वीआईपी मूवमेंट वाली सड़कों तक सीमित हैं। ऐसे में आमजन को बहुत ज्यादा राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर हरियालीयुक्त और प्रदूषणमुक्त इस शहर को पेरिस बनाने का ख्वाब क्या बूचड़खाना ही बनकर रह जाएगा?

– राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 21, पृष्ठ-48, 1 से 15 अगस्त, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स, एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर भोपाल- 462011 (म.प्र.), फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रमुख संवाददाता
भावना सक्सेना-भोपाल, जय मदानी-भोपाल, देवीराम-इंदौर, हर्ष सक्सेना-भोपाल, दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर, विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा, ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन, टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहगढ़, अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई, इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता
पारस सरावगी (इंदौर) 09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर) 09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर) 098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन) 094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम) 089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा) 075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, , फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

लाभदायक होगी योजना

सरकार अटल गृह ज्योति योजना के तहत बिजली कंपनियों को सब्सिडी दे रही है। इसके तहत प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली खपत पर सिर्फ 100 रुपए बिजली बिल देना होगा। यह योजना आमजन के लिए काफी हद तक लाभदायक होगी।

● **प्रखर जैन,** भोपाल (म.प्र.)

ठोस कदम उठाए सरकार

मप्र में बलात्कार की जितनी शिकायतें आती हैं, उनमें शादी का झांसा देकर सालों से गलत काम करने, लिव-इन में सालों तक रहने के बाद दुष्कर्म की एफआईआर सबसे ज्यादा हो रही हैं। प्रदेश की मोहन सरकार को इस मामले में ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **रेखा शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

लोकतंत्र का सम्मान

पिछले दो दशक से मप्र के माननीयों का मन लोकतंत्र के मंदिर यानी विधानसभा में नहीं लग रहा है। शायद यही वजह है कि पिछले दो दशक से मप्र विधानसभा का कोई भी सत्र पूरा नहीं चला। माननीयों को लोकतंत्र की अहमियत को समझते हुए विधानसभा सत्रों में भागीदारी देनी चाहिए।

● **प्रमोद वर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

बेहतर हो शिक्षा व्यवस्था

कोरोना की पाबंदी हटने के बाद आजीविका मिशन के माध्यम से स्कूलों में दो साल पहले ड्रेस नहीं पहुंच सकी। प्रदेश सरकारी स्कूलों में 390 करोड़ खर्च करने के बाद भी पिछले साल की सभी 66 लाख विद्यार्थियों को यूनिफार्म या उसकी राशि नहीं मिल पाई है। स्कूलों में विद्यार्थियों को बीते पांच सालों से यूनिफार्म के लिए परेशान होना पड़ रहा है। स्कूलों में पिछले दो साल से ड्रेस वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। वह भी पूरा नहीं हुआ है। इससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी रंग-बिरंगे कपड़ों में ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। सरकार को सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने की आवश्यकता है, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके और उनका भविष्य बेहतर हो सके।

● **धीरज यादव,** ग्वालियर (म.प्र.)

वायु प्रदूषण की मार

दिल्ली में वायु प्रदूषण से जनित बीमारियों से हर साल 12 हजार लोगों की मौतें हुई हैं, जो देश में हुई कुल मौतों का 11.5 प्रतिशत है। भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को कठोर करने की जरूरत है और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास दोगुने करने की जरूरत है। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा मौतें वाराणसी में हुई हैं, जहां हर साल 830 लोगों की जान गई है, जो कि कुल मौतों की संख्या का 10.2 प्रतिशत है। सरकार को वायु प्रदूषण को लेकर कड़े कदम उठाने चाहिए।

● **ओपी पुरोहित,** जबलपुर (म.प्र.)

आर्थिक विकास को मिलेगी गति

मप्र के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार अब अपना ध्यान औद्योगिक विकास पर लगाएगी। वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए देश के विभिन्न औद्योगिक समूहों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने मुंबई में उद्योगपतियों के साथ बैठक करके की है। इसमें रिलायंस ग्रुप ने शहडोल में रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपए की इच्छा जताई है। बैतूल, शहडोल और दमोह में 17 हजार करोड़ रुपए के निवेश का जेएस डब्ल्यू लिमिटेड ने प्रस्ताव दिया है।

● **संदीप सेन,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

निंदक नियरे राखिए, पर...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में सरकार व प्रतिपक्ष के बीच बढ़ती दूरी पूरे देश के लिए आज चिंता का विषय बनी हुई है और अब तो यह चिंता और भी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सरकार के नीति निर्माण संबंधी मामलों में प्रतिपक्ष से दूरी बनाई जा रही है और हिम्मत करके कोई प्रतिपक्षी दल का प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो भी जाता है तो उसे बोलने नहीं दिया जाता। यह विचार प्रतिपक्षी दलों के नेताओं के हैं। पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक में उपस्थित एकमात्र प्रतिपक्षी प्रतिनिधि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को जिस तरह उनके विचार प्रकट करने से रोका गया, उनका माइक बंद कर दिया गया, यह घटना आखिर सत्तारूढ़ दल की किस मंशा को उजागर करती है, बाकी प्रतिपक्षी दलों ने इस महत्वपूर्ण बैठक का बहिष्कार किया था। आज हर छोटे-बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीति के सही सिद्धांतों की जानकारी होना चाहिए, जिसका अभाव है। आज सत्तारूढ़ दल अपने आपको देश का सबसे बड़ा भाग्यविधाता मानता है और फिर इस गुरूर में वह अपने दायित्व और राजनीति के नियम सिद्धांत भी भुला देता है, इस तरह उस पर तानाशाही सवार होने लगती है। मोदीजी को अपने तीसरे कार्यकाल में ध्यान रखना चाहिए कि उनकी व उनकी सरकार की स्थिति पिछली दो सरकारों जैसी नहीं रही है।

राहुल के इर्द-गिर्द दिखती भाजपा की राजनीति

अब भाजपा उन्हें पप्पू कहेगी या फिर राहुल गांधी यह तो भाजपा ही जाने पर यह जरूर है कि कल तक गलियों की खाक छानने वाले इस कांग्रेस नेता ने भाजपा नेताओं की नाक में दम कर रखा है। पर इसका श्रेय राहुल खुद को नहीं बल्कि भाजपा को देते हैं। राहुल गांधी के बयानों को माना जाए तो भाजपा ने उन्हें पप्पू बनाने के लिए करोड़ों का खर्चा कर डाला पर भाजपा को कोई राजनीतिक फायदा नहीं हुआ। बल्कि भाजपा के लिए ये सौदा घाटे का रहा। या यूं कहिए कि राहुल की मोहब्बत की दुकान इन चुनावों में ऐसी चल निकली कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली भाजपा को अपने बूते नहीं बल्कि गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर होना पड़ गया। वरना तो भाजपाईयों ने गलियों और चौबारों से लेकर शहरों तक राहुल को पप्पू बताने में कमी नहीं रखी। भला राहुल कितने पप्पू बने और कितनी रही उनकी बालक बुद्धि यह अलग बात है पर यह जरूर रहा कि राहुल ने पूरे लोकसभा चुनाव को राहुल बनाम मोदी जरूर बनाकर दिखा दिया। लोग तो मानते हैं कि राहुल की खुली मोहब्बत की दुकान और इंडिया गठबंधन ने भाजपा की राजनीति को कम से कम पांच साल तक तो राहुल के इर्द-गिर्द घूमने को मजबूर कर दिया है।

केजरीवाल की रिहाई के बानक नहीं बन रहे

तिहाड़ में रिहाई के दिन गिन रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता भले रिहाई के लिए इंडिया गठबंधन पर संसद में इस मामले को उठाए जाने के लिए दबाव बना रहे हों। आप नेता राघव चड्ढा तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेता तिहाड़ जाकर केजरीवाल से मिलते रहें। ताकि संदेश जाए कि पूरा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ है। पर दिल्ली के कांग्रेसी केजरीवाल एंड पार्टी को अलग-थलग देखना चाहते हैं। यह अलग बात है कि पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का जिक्र किया था। लेकिन लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद जिस तरह आप पार्टी के नेताओं ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव कांग्रेस से अलग होकर लड़ने का ऐलान किया उससे कांग्रेसी खुश नहीं हैं। यह जरूर है कि कांग्रेस ने भी आप से अलग होकर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। पर आप नेताओं के बयान से दोनों पार्टियों में कटुता तो आई ही है। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने यहां तक कह दिया कि केजरीवाल की सेहत को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संदीप का कहना है कि आप पार्टी के नेता कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं और झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है।

विवाद और गरिमा

पिछले 5 वर्षों से लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष ओम बिरला लगातार विवादों में रहे हैं। उन पर सत्तापक्ष के प्रति अनुचित झुकाव रखने का आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। ओम बिरला को मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचना पंच परमेश्वर को पढ़ना चाहिए जो शायद उन्होंने अपने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ी होगी। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपने सगे-संबंधियों का भी लिहाज नहीं करना चाहिए। लोकसभा की सार्थकता और अपने पद की गरिमा के अनुरूप ओम बिरला को किसी सांसद को ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि उनका व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र की परंपरा काफी सराहनीय रही है। लोकसभा भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है जहां देश के कोने-कोने से आम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि अपने क्षेत्र, प्रांत व राष्ट्र के हित में समस्याओं पर विमर्श करते हैं। लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोक-झोंक का चलना बहुत सामान्य व स्वाभाविक बात है।

शुरू हुई उठा-पटक

हरियाणा विधानसभा चुनाव की आहट हुई तो भाजपा में उठापटक तो कांग्रेस में गुटबाजी से निपटाने की तैयारी। कार्यकर्ताओं का चुनाव में कम दिलचस्पी लेना दोनों पार्टियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चुनाव हरियाणा के होने हैं पर बैठकें दिल्ली में चल रही हैं। नेता से लेकर जिलाध्यक्ष और मंडल तक में भाजपा फेरबदल कर रही है। या यूं मानो कि हरियाणा में जीत के लिए वह दिल्ली की तरह ही नए-नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनावों में मिले झटके के बाद भाजपा एक्शन में है। चुनावी मैदान में जाने से पहले पार्टी ने दावेदारों की पूरी पड़ताल शुरू करा दी है। 6 जिलाध्यक्षों को पद से हटा दिया गया है तो चार जिलों के प्रभारियों पर एक्शन लिया गया है। चर्चा तो है कि इन चारों को पदों से ही हटा दिया जाएगा। अब पार्टी भले इस कार्रवाई को जीत के लिए गुणा-भाग कर रही हो पर जानकार तो इसे लोकसभा चुनाव में मिली हार से जोड़कर ही देख रहे हैं।

साहब का अजब-गजब जवाब...

प्रदेश के सबसे कमाऊ विभागों में शामिल एक विभाग के अधिकारियों की कारोबारियों से कुछ इस कदर सांठगांठ रहती है कि सरकार को भले ही करोड़ों रुपए की चपत लग जाए, लेकिन कारोबारी पर आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा ही एक मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, मामला 2022 का है। महाकाल की नगरी में शराब ठेके के लिए एक कारोबारी द्वारा करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी। इस संदर्भ में सरकार द्वारा विभाग से पूछा गया था कि कारोबारी को कारोबार के लिए कितनी बार टीपी (पारपत्र) जारी की गई थी। सूत्रों का कहना है कि विभाग के आयुक्त महोदय ने ऐसा अजब-गजब जवाब दिया कि उसे पढ़ और सुनकर हर कोई चकरा गया। दरअसल, साहब ने अपने जवाब में कहा कि कारोबारी को कितनी टीपी जारी की गई यह विभागीय जांच में ही पता चल पाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिस अधिकारी ने देश की सर्वोच्च परीक्षा पास कर आईएएस का पद हासिल किया है, वे इस तरह का जवाब दे रहे हैं। वहीं विभाग और साहब को जानने वालों का कहना है कि उनका जवाब सुनकर भले ही आश्चर्य हो रहा है, लेकिन साहब का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर एसी साहब को नोटिस जारी हो गया है। क्योंकि कारोबारियों से मोटी रकम लेने वाले अफसर हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कारोबारियों पर किसी भी तरह की आंच न आए।

चर्चा में साहब का बंगला

मप्र के एक आईपीएस अधिकारी का बन रहा बंगला चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल, साहब भले ही मप्र में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी राज्य में बन रहा उनका बंगला लोगों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। सूत्रों का कहना है कि साहब का बंगला इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि वह किसी महल की तरह बन रहा है। वह भी तब जब साहब अपनी ईमानदारी का बखान कर करके थकते नहीं हैं। गौरतलब है कि साहब के बैचमेट कई आईपीएस अधिकारी ऐसे हैं, जो अभी एक बंगला बने न्यारा... का सपना देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साहब अपने गृह नगर में महलनुमा बंगला बनवा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब भले ही ईमानदारी का चोला ओढ़े हुए हैं, लेकिन वे काफी घाघ किस्म के अधिकारी हैं। वर्तमान में साहब जिस जिले में पुलिस की कप्तानी कर रहे हैं, वह जिला अवैध कारोबार के लिए कुख्यात है। साहब को जानने वालों का दावा है कि साहब ने वर्तमान पदस्थापना के दौरान जमकर कमाई की है। इसलिए साहब पड़ोसी राज्य में स्थित अपने गृह नगर में बंगला बनवा रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि साहब के बंगले में हो रहे अनाप-शनाप खर्च का जिम्मा साहब की वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के कुछ लोग उठा रहे हैं।

साहब की चिट्ठी बनी परेशानी

प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शासन-प्रशासन में बैठे अन्य लोग हथेली पर दूब उगाने में लगे हुए हैं। यानी हर कोई इसी कोशिश में लगा हुआ है कि किस तरह कमाई कर अपना खजाना भरा जाए। सूत्रों का कहना है कि काली कमाई करने में ख्यात एक मंत्रीजी ने तो हद ही कर दी है और उन्होंने एक सटोरिए के लिए पुलिस को चिट्ठी लिख दी है। जिन मंत्रीजी की यहां बात हो रही है, वे मालवांचल से आते हैं। सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी जिस शहर से संबंधित हैं, उस शहर में अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले लोगों से उनकी अच्छी खासी पटती है। मंत्रीजी के ऐसे ही एक करीबी सट्टे के खेल में दांव लगाते हैं। बताया जाता है कि विगत दिनों उन्होंने सट्टे में बड़ा दांव लगा दिया, लेकिन उनका वह दांव दगा दे गया और उनकी बड़ी रकम डूब गई। उन्होंने यह बात मंत्रीजी को बताई। सूत्र बताते हैं कि बिना सोचे-समझे मंत्रीजी ने आव देखा न ताव और संबंधित थाने के टीआई को चिट्ठी लिख डाली कि सट्टे में डूबी हुई इनकी रकम वापस दिलाओ। बताया जाता है कि मंत्रीजी का पत्र मिलने से थानेदार साहब ही नहीं, बल्कि पूरा थाना परेशानी में पड़ गया है। लेकिन ये बेचारे करें भी तो क्या करें। सरकार के मंत्री का आदेश है और उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पुलिस वाले सारा कामधाम छोड़कर सटोरिए की रकम वापस दिलाने में जुटे हुए हैं।

तिकड़ी का जलजला

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों एक तिकड़ी का जलजला देखने को मिल रहा है। इस तिकड़ी की कई विभागों में धमक है। दरअसल, यह तिकड़ी कई मंत्रियों के लिए काम कर रही है। आलम यह है कि यह तिकड़ी ठेकेदारों को धमकाने में भी बाज नहीं आती है। दरअसल, इस तिकड़ी के तीनों लोग अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। कुछ दिन पहले तक इनकी प्रदेश के एक बड़े विभाग में इस कदर तूती बोलती थी कि उनके बिना पत्ता नहीं हिलता था। इसका असर यह हुआ कि विभाग के तत्कालीन मंत्री की हर जगह फजीहत भी होती रही और एक दिन ऐसा आया कि उनसे विभाग ही छीन लिया गया। अब यह तिकड़ी अन्य विभागों में अपनी धौंस जमा रही है। इसी कड़ी में इस तिकड़ी ने विगत दिनों पानी संरक्षण करने वाले विभाग में हुए एक टेंडर के मामले में ठेकेदारों को धमका डाला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंडर डालने की? यह तो इस तिकड़ी का एक ट्रेलर मात्र है। सूत्रों का दावा है कि यह तिकड़ी ठेके दिलवाने का ठेका लेकर लाखों-करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा कर रही है।

काली कमाई में परिवारवाद

परिवारवाद की खिलाफत करने वाली पार्टी में इन दिनों अजब-गजब तरीके का परिवारवाद देखने को मिल रहा है। पार्टी ने टिकट वितरण और सत्ता संगठन में पद देने के मामले में भले ही परिवारवाद को दरकिनार कर दिया है, लेकिन सत्ता में बैठे कुछ माननीयों के यहां काली कमाई करने में पारिवारिक एकता और परिवारवाद देखने को मिल रहा है। वैसे तो कई मंत्रियों के भाई-भतीजे, नाते-रिश्तेदार कमाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन ग्वालियर-चंबल अंचल से आने वाले एक मंत्रीजी के बेटे और बीवी की चर्चा खूब हो रही है। वह इसलिए कि मंत्रीजी विभागीय कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे में उनके बेटे और बीवी ने व्यापारियों और ठेकेदारों अर्जी सुनने का ठेका ले लिया है। गौरतलब है कि जिन मंत्रीजी की यहां बात हो रही है, वे उस विभाग के मंत्री हैं, जिसके नाम और काम से प्रदेश को जाना जाता है। खाद, बीज और कीटनाशकों के उपयोग वाले इस विभाग में कारोबारियों से जमकर कमाई होती है। ऐसे में सारे कारोबारियों को मैनेज करने का भार मंत्रीजी के बेटे और बीवी ने अपने ऊपर लेकर माननीय को राहत पहुंचाई है।

निष्ठावान वरिष्ठों को मिलेगी निगम-मंडलों की कुर्सी

मप्र में करीब 6 माह से निगम-मंडल-प्राधिकरणों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की नियुक्ति की राह देख रहे नेताओं की जल्द ही लॉटरी लगने वाली है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने राजनीतिक नियुक्तियों के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही कहा गया है कि निष्ठावान वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडल और प्राधिकरणों में पदस्थ किया जाए।

गौरतलब है कि इन दिनों प्रदेशभर के भाजपा नेताओं के भोपाल से लेकर दिल्ली तक के फेरे बढ़ गए हैं। यह नेता अपने साथ अपनी उपलब्धियों के ब्यौरे के साथ ही पूर्व में मिले आश्वासनों का पुलिंदा लेकर भी चल रहे हैं। उन्हें सत्ता में भागीदारी के लिए जो नेता मददगार साबित होने वाला लगता है, उसे अपनी बायोडाटा वाली फाइल थमा दी जाती है। यह वे नेता हैं, जिन्हें विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दावेदारी के बाद भी टिकट नहीं दिया गया था। यही वजह है कि अब यह नेता चाहते हैं कि उन्हें निगम-मंडल में भागीदारी मिल जाए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद से निगम-मंडलों में अपनी ताजपोशी का इंतजार कर रहे नेताओं की उम्मीद जल्द पूरी हो सकती है। पार्टी हाईकमान ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। निगम-मंडलों में उन सीनियर नेताओं की नियुक्ति की जाएगी जो पार्टी में लगातार समर्पित भाव से काम कर रहे हैं और उन्हें अब तक कोई बड़ा पद नहीं मिला है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े नेताओं को भी तरजीह दी जाएगी। भाजपा ने इसके लिए संघ से भी 10 नाम मांगे हैं। वहीं प्रदेश संगठन भी अपनी सूची तैयार कर रहा है। जिस पर मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट के गठन के बाद सभी निगम मंडलों को भंग कर दिया गया था।

गौरतलब है कि भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन नेताओं ने इस बात के संकेत दिए थे कि जिन नेताओं ने चुनाव में अच्छा काम किया है और पार्टी के हर फैसले के साथ रहे हैं। पार्टी उनका पूरा ख्याल रखेगी। इसके बाद से ही निगम-मंडलों में पदों पर नियुक्ति को लेकर हलचल शुरू हो गई थी। इनमें अधिकांश वे नेता शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव के समय किन्हीं कारणों से टिकट से वंचित कर दिए गए थे पर उन्होंने बगावती तेवर न अपनाते हुए पार्टी द्वारा तय प्रत्याशी के पक्ष में पूरे मन से काम किया। ऐसे वरिष्ठ नेता अब निगम-मंडलों एवं प्राधिकरणों में अपनी तैनाती चाहते हैं। निगम-मंडल में नियुक्तियों को लेकर दावेदारों में बैचेनी बढ़ती जा रही है। टिकट पाने से वंचित रह गए जिन नेताओं के नसीब में आश्वासन आए थे वे इन नियुक्तियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा संगठन और चुनाव के कामों में सालों से लगे नेताओं को भी अपने काम के ईनाम का इंतजार है। इसके अलावा कांग्रेस से चार साल पहले और विधानसभा चुनाव के दौरान अपने समर्थकों के साथ आए नेताओं को भी अपने राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार है।

सूत्रों की मानें तो दिल्ली में इसे लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश संगठन महामंत्री बीएल संतोष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से चर्चा कर चुके हैं। निगम, प्राधिकरण, आयोग समेत चार दर्जन सार्वजनिक उपक्रमों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सदस्य अथवा संचालक मंडल में नियुक्तियां होनी हैं। इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि इनके दावेदारों की संख्या काफी ज्यादा है और पार्टी को नाम तय करने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं संघ भी अपने कोटे के 10 नामों पर विचार कर रहा है। इसमें अधिकांश वे नेता शामिल हैं जो संघ से भाजपा में गए हैं। शिवराज सरकार में संभागीय संगठन मंत्री के दायित्व से मुक्त किए गए आधा दर्जन से अधिक नेताओं को निगम-मंडल में पदों से नवाजा गया था। इनमें आशुतोष तिवारी, शैलेंद्र बरूआ, जितेंद्र लिटौरिया जैसे नेता शामिल थे। तब इन्हें आरएसएस के कोटे से ही माना गया था। इस बार इनकी जगह नए नामों पर संघ विचार कर रहा है। निगम-मंडलों में दो बार रह चुके नेताओं को इस बार मौका नहीं मिलेगा। ऐसा नए चेहरों को मौका देने के लिए किया जा रहा है। संगठन से जुड़े एक बड़े नेता की मानें तो इस बार ज्यादा से ज्यादा नए चेहरों को निगम-मंडल और प्राधिकरणों में जगह दी जाएगी। दरअसल पार्टी हाईकमान को कई नेताओं ने लिखित में भेजा है कि कुछ चेहरों को हर बार निगम-मंडल में कोई न कोई पद दिया जाता है। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जो नेता दो बार निगम-मंडल या प्राधिकरणों में ताजपोशी पा चुके हैं, उन्हें अब और मौका नहीं दिया जाएगा। संगठन के कुछ ऐसे नेता जिन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर काम किया है, उन्हें इस बार प्राथमिकता में रखा जाएगा। इसमें प्रदेश से लेकर जिलों तक के नेता शामिल है।

● **कुमार विनोद**

इन निगम-मंडल और प्राधिकरणों में होनी हैं नियुक्तियां

मप्र में जिन निगम-मंडल और विकास प्राधिकरणों में नियुक्ति होना है। उनमें प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, जबलपुर, सिंगरौली, कटनी, अमरकंटक और रतलाम में विकास प्राधिकरण है। मोहन सरकार ने अब तक रामकृष्ण कुसमारिया को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा मप्र में तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण, भंडार गृह निगम, जन अभियान परिषद, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड, सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, पाठ्य पुस्तक निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, ऊर्जा विकास निगम, संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, बीज एवं फार्म विकास निगम, हाउसिंग बोर्ड, पर्यटन विकास निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, महिला एवं वित्त विकास निगम, पाठ्य पुस्तक निगम, बीज एवं फार्म विकास निगम, पर्यटन विकास निगम, खनिज विकास निगम, नागरिक आपूर्ति निगम, राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, जन अभियान परिषद, क्रिस्प, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, श्रम कल्याण मंडल, माटी कला बोर्ड, वन विकास निगम, इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल विकास प्राधिकरण, योग आयोग, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार मंडल, राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग, रतलाम विकास प्राधिकरण, युवा आयोग, उज्जैन विकास प्राधिकरण, कटनी विकास प्राधिकरण, देवास विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में नियुक्तियां होनी हैं।

सकते में क्यों है सरकार... ?

अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बना ली है, लेकिन सत्ता और संगठन को अनजाना डर सता रहा है। शायद यही वजह है कि विगत दिनों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की तो उन्होंने उन्हें कई तरह की हिदायतें दीं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि आप लोग जब भी किसी से बात करें तो वाट्सएप पर करें। वहीं जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने आए तो इस बात का ध्यान रखें कि कमरे में वह किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर न आए। यानी उसका मोबाइल या अन्य ऐसे सामान बाहर ही रखवा दिया करें।

प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को यह हिदायत क्यों दी है, यह तो वही जाने, लेकिन इसकी चर्चा देशभर में हो रही है। लोग इस बात की शोध में जुट गए हैं कि आखिर सरकार सख्ते में क्यों है? हालांकि जानकारों का कहना है कि विगत लोकसभा चुनाव में विपक्ष से कड़े मुकाबले के बाद जीती भाजपा अब हर बात पर फूंक-फूंककर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि उसके मंत्रियों की कोई ऐसी गलती सार्वजनिक न हो, जिससे सरकार को नीचा देखना पड़े।

सोशल मीडिया पर परफॉर्मेंस

केंद्र और राज्य सरकार अपने मंत्रियों की सक्रियता पर भी नजर रखे हुए है। इसके लिए मंत्रियों की सोशल मीडिया पर सक्रियता की परफॉर्मेंस आंकी जा रही है। कौन मंत्री एक्स, फेसबुक, वाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कितना सक्रिय है, इसकी निगरानी रखी जा रही है। दरअसल, सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में बहुसंख्यक आबादी सोशल मीडिया पर सक्रिय है। ऐसे में मंत्रियों और सरकारी योजनाओं की पहुंच आम आदमी तक आसानी से हो सकती है। गौरतलब है कि सरकार ने कई बार अपने मंत्रियों को निर्देशित किया है कि वे सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक सक्रिय रहें। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भाजपा लगातार जोर दे रही है। बावजूद इसके कई मंत्री और राज्यमंत्री सक्रिय नहीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के इंस्टाग्राम में 9.52 लाख और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय फेसबुक पर 10.2 लाख फॉलोअर्स के साथ सबसे आगे हैं। फेसबुक पर 5.67 लाख फॉलोअर्स के साथ डॉ. मोहन यादव दूसरे नंबर पर हैं। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को 3.76 लाख लोग फॉलो करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश के पहले ऐसे मंत्री हैं, जिनके नाम से सोशल मीडिया एक्स पर सर्वाधिक फॉलोअर्स हैं। वहीं मंत्री नागर सिंह चौहान के एक्स पर मात्र 46 फॉलोअर्स हैं।

छतरपुर के मोदी पर अड़ी

बुंदेलखंड के एक जिले छतरपुर में एक व्यवसायी इन दिनों परेशान है। दरअसल, इन व्यवसायी का सरनेम मोदी है, इसलिए इनका मामला सुर्खियों में है। बताया जाता है कि खनिज का व्यवसाय करने वाले मोदीजी का कोई गड़बड़झाला एक पत्रकार के हाथ लग गया है। उक्त पत्रकार ने मोदीजी से उक्त मामले को दबाए रखने के लिए 30 लाख रुपए की मांग कर डाली है। बताया जाता है कि शहर के कुछ अन्य प्रतिष्ठित व्यापारियों ने मोदीजी के पक्ष में आकर पत्रकार से सिफारिश की है कि वे अपनी मांग की राशि कुछ कम करें। बताया जाता है कि मामला 5 लाख रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन पत्रकार अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

2 अगस्त से राज्यपाल कॉन्फ्रेंस

देश के सभी राज्यों के राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस 2 और 3 अगस्त को दिल्ली में होगी। इसमें मप्र के राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी शामिल होंगे। राज्यपाल कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसमें राज्यों के पड़ोसी राज्य के साथ समन्वय बैठक और अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा कर फैसले लिए जाएंगे। मप्र के विधानसभा चुनाव के पहले राज्यपालों की भूमिका में बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय मुद्दों को लेकर हर राज्यपाल को पड़ोसी राज्य के साथ बैठक करने के निर्देश दिए थे। इसके चलते प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कुछ राज्यों के साथ बैठक भी की है और इस बैठक में मप्र के सीमावर्ती जिलों और दूसरे राज्यों के मप्र से सटे सीमावर्ती जिलों की कॉमन समस्याओं, बड़ी परियोजनाओं को लेकर चर्चा हुई थी। अब दिल्ली में 2 और 3 अगस्त को होने वाली राज्यपाल कॉन्फ्रेंस में इन मसलों पर केंद्र सरकार की ओर से रिपोर्ट ली जाएगी। अब तक की गई बैठकों की समीक्षा भी की जाएगी।

परिवहन की दुकान बंद

प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद 1 जुलाई से सभी परिवहन नाके बंद कर दिए गए हैं। इससे परिवहन चौकियों पर तैनात होने वाले कटर हटा दिए गए हैं। इस बीच कुछ जिलों के परिवहन अधिकारियों से मंत्री और विधायक इस कदर नाराज दिख रहे हैं कि उन्हें जिले से बाहर हटाने के लिए मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री तक शिकायती पत्र लिख दिया है। दरअसल, जब परिवहन चौकियां चलती थीं तो विधायक अपने लोगों को कटर के रूप में वहां तैनात कर देते थे। इससे परिवहन अफसरों को राहत तो मिलती ही थी, साथ ही जमकर कमाई भी होती थी। कटर हटाए जाने के बाद विधायक इस बात से नाराज हैं कि हमारे लोग अब क्या करेंगे।

● **राजेंद्र आगाल**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र में विकास की पंचवर्षीय योजना बनाई है। इसका उद्देश्य यह है कि पूरे प्रदेश में एक समान और एक साथ विकास होगा। इसके लिए उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से कहा है कि वे 2028 तक के विकास का रोडमैप तैयार करें। ताकि उनके क्षेत्र में संतुलित विकास हो सके। संभवतः मप्र में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे प्रदेश में एक समान विकास की रणनीति पर सरकार काम करने जा रही है।

मप्र में अब एक समान विकास

चुनावों से निपटने के बाद अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उनकी सरकार का पूरा फोकस विकास पर है। इसलिए मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में एक समान विकास कराने के उद्देश्य से संभागवार विधायकों के साथ बैठक कर विकास का खाका तैयार किया है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने विधायकों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2028 तक की विकास योजना का रोडमैप तैयार करें। प्रत्येक विधायक को सालाना 15 करोड़ के मान से 60 करोड़ रुपए अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के खर्च के लिए मिलेंगे।

मुख्यमंत्री का निर्देश है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए चार साल का समय शेष है। सभी विधायक अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचकर विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी कार्यों का क्रियान्वयन हो। चार साल का रोडमैप बनाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जन-जन तक पहुंचाने और जानकारी उपलब्ध कराने में विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन की मॉनीटरिंग लगातार होती रहे। हितग्राहियों से संपर्क बना रहे। सभी योजनाओं में पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जाएं, अपात्रों के नाम काटे जाएं। नगरीय निकाय और जनपद पंचायतों के अंतर्गत जनता से सीधी जुड़ी योजनाओं को अच्छी तरह से क्रियान्वित करें। जनता से जुड़े सभी अभियानों में बेहतर योगदान दें। सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार शिविर लगाए जाएं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हों।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने विधायकों को अपना हाईटेक ऑफिस तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विधायकों का ऑफिस सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ा रहेगा। विधायकों को भोपाल तक बार-बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों के ऑफिस से मुख्यमंत्री कार्यालय तक अपनी बात आसानी से पहुंचाकर समाधान करा सकेंगे। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि रोजगार आधारित कार्य को प्राथमिकता दें। जिला प्रशासन से मिलकर रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों को बढ़ाया जाए। ध्यान दिया जाए कि विधानसभा क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले। विधायक अपने कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण करें, इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक अपने कार्यालय की व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाए। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार बढ़ाया जाए। विधानसभा में किए गए अच्छे प्रयोगों का प्रचार-प्रसार करने के लिए स्मारिका का प्रकाशन करवाएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गौशालाओं के संचालन का उल्लेख करते हुए कहा है कि स्वसहायता समूहों को भी गौशाला संचालन के लिए दे सकते हैं। इससे गौशालाओं का संचालन अच्छी तरह हो सकेगा। दुग्ध उत्पादन के लिए बोनस देने की योजना बनाई जाएगी। स्वस्थ पशु अपने घरों में रखें, लावारिस और अपाहिज गौवंश को गौशालाओं में रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि एक जुलाई 2024 से पुलिस के कानूनों में जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रम आयोजित करके दी जाए। बदली गई धाराओं से नागरिकों को अवगत कराया जाए। स्कूल चलें अभियान में स्कूलों का निरीक्षण हो। स्कूलों में पुस्तकें, गणवेश तथा अन्य सामग्री वितरित कराई जाए। रोडमैप बनाकर स्कूलों का उन्नयन कराएं। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य

विभागों के खर्च पर रहेगा सरकारी पहरा

मप्र में सरकार इस बार बजट का उपयोग फूंक-फूंककर करेगी। विभागों को किश्तों में बजट दिया जाएगा और उनके खर्च की मॉनीटरिंग की जाएगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को विधानसभा में मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट की राशि पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का पिछला बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का था। बजट भले ही 3.65 लाख करोड़ का है, लेकिन विभागों को 2.20 लाख करोड़ में से राशि आवंटित की जाएगी। दरअसल, 3.65 लाख करोड़ रुपए के बजट में लेखानुदान की 1.45 लाख करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार ने मार्च में विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें चार महीने (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस तरह 3.65 लाख करोड़ की बजट राशि में से 1.45 करोड़ रुपए लेप्स हो जाएंगे। बची हुई 2.20 लाख करोड़ रुपए विभागों को 8 महीने के लिए आवंटित किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विभागों को बजट की राशि आवंटित की जाएगी। विभाग इस राशि को अगस्त 2024 से मार्च, 2025 तक खर्च कर सकेंगे।

पिछड़ा वर्ग के छात्रावास, स्कूल, आंगनवाड़ी, हॉस्पिटल में पौधे लगवाए जाएं। स्वसहायता समूहों के साथ विधानसभा के कार्यक्रम आयोजित कराएं।

प्रदेश की मोहन सरकार अगले साढ़े चार साल के लिए हर विधानसभा क्षेत्र का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराएगी। इस विजन डॉक्यूमेंट में हर एक विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को शामिल किया जाएगा। 60 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी, जबकि 40 करोड़ रुपए विधायक, सांसदों की क्षेत्र विकास निधियों से और सीएसआर, जनभागीदारी व रीडेंसिफिकेशन-रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए जुटाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों से कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 4 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं। हर काम का लक्ष्य और समयसीमा तय करें। इसमें कलेक्टर, विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधियों की मदद लेंगे। विधायकों से मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक हितग्राही को मिले इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। राशन का आवंटन उचित मूल्य दुकानों में पहुंचाया जाए। आयुष्मान योजना का लाभ हितग्राहियों को ठीक ढंग से मिले, जिन अस्पतालों में आयुष्मान योजना की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार सुनिश्चित कराएं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आयोजनों में भारतीय तिथियों और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम हों। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि राज्य सरकार गौशालाओं के संचालन के लिए प्रति गाय 40 रुपए की राशि प्रतिदिन के मान से उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्वालियर संभाग की सभी ग्रामों की पेयजल योजनाएं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। कोई भी गांव छूटा नहीं है।

भोपाल जिले की सातों विधानसभा सीटों में अगले चार साल में कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सफाई और बुनियादी ढांचे की जरूरत के हिसाब से प्लानिंग करें।

विधायक कलेक्टरों की मदद से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाने के लिए प्रयास करें। प्रत्येक विधायक अपनी विधानसभा में कलेक्टर के सहयोग से उद्योगों के लिए भूमि आरक्षित कराएं और औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके उद्योग लगवाए जाएं। कुटीर, लघु और वृहद उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए। उन्होंने कहा है कि भारतीय संसद ने तीन नए ऐतिहासिक कानून क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बनाकर न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन का कदम उठाया है। नए कानूनों का लगातार अध्ययन करें और उनकी जानकारी आमजन को कार्यक्रमों के माध्यम से दी जाए। आंगनबाड़ी, ऊषा-आशा कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और पंचायत के पदाधिकारियों इत्यादि को आयुष्मान योजना की पात्रता से जोड़ा गया है। इनका जिन अस्पतालों में आयुष्मान की सुविधाएं हैं वहां उचित उपचार किया जाए। दीनदयाल रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सभी बड़े अस्पतालों में भी दीनदयाल रसोई का काउंटर खोला जाए। जिससे बीमार के परिजनों को भोजन की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकेंद्रीयकरण की तरफ कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार विधायकों के अधिकारों को और अधिक बढ़ा रही है। जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि विधायकों के साथ मिलकर जिलों का विकास करें।

मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से कहा है कि विकास और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी से कहा है कि विधायकों द्वारा किए गए सवालों के जवाब लेने और विधायकों के जनहितैषी मामलों में सुनवाई करने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए विधायक और अफसर मिलकर इस दिशा में काम करें। उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वच्छता, बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार करके क्षेत्र के नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर फोकस किया जाए। एक जिला एक उत्पाद योजना से रोजगार के अवसर प्रदान करने को भी शामिल करें। गौरतलब है कि मप्र में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। पिछले 20 वर्षों में राज्य में तेज गति से आर्थिक विकास देखने को मिला है। अब प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 5 साल में विकास की गति दोगुना बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 5 वर्ष बाद यानी वर्ष 2028-29 में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी वर्तमान मप्र सरकार ने अगले 5 साल में अपने बजट का आकार बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

प्रतिव्यक्ति आय में 4 गुना वृद्धि

मप्र आज विकास के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। इस पर विधानसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भी मुहर लगी है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9.37 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं प्रतिव्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि हुई है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अनुसूचित वर्गों, महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के साथ व्यापार को बढ़ावा मिला है। मप्र 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सौर ऊर्जा उत्पादन में मप्र देश में चौथे स्थान पर है। मप्र देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में भरपूर सहयोग देगा। साल 2023-24 के लिए, मप्र का मौजूदा कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 13,63,327 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यह राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तार दर्शाता है। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि को शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य सकल घरेलू उत्पाद 12,46,471 करोड़ रुपए से लगभग 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मप्र विधानसभा में पास हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि साल 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 6,60,363 करोड़ रुपए थी, जो पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यह लगभग 6.01 प्रतिशत की वृद्धि है, जो दिखाती है कि मप्र सतत् रूप से आर्थिक प्रगति कर रहा है।

विवादों की भेंट चढ़ गए चौहान!

कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत को आखिरकार विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग का दायित्व सौंपा गया है। अभी तक वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी नागर सिंह चौहान निभा रहे थे। अब उनका कद घटा दिया गया है। नागर सिंह चौहान से वन एवं पर्यावरण विभाग छीनकर रामनिवास रावत को दिया गया है। वर्तमान में नागर सिंह चौहान के पास सिर्फ अनुसूचित जाति एवं कल्याण विभाग बचा है। माना जा रहा है कि विवादों के कारण चौहान का कद कम किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने इस एक कदम से अन्य मंत्रियों को संदेश दे दिया है कि सरकार में किसी को मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही मंत्रियों को संदेश दे दिया था कि सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। रामनिवास को वन एवं पर्यावरण विभाग सौंपकर मुख्यमंत्री ने क्या काबीना के अन्य साथियों को सख्त संदेश दे दिया है? यह सवाल इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का विषय बना हुआ है क्योंकि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद वन मंत्री रहे नागर सिंह चौहान ने अपने निजी स्टाफ में एक विवादित अधिकारी की सेवाएं जारी रखी हुई हैं। सरकार गठन के बाद से ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी मंत्री पुराने और विवादित अधिकारियों को अपना विशेष सहायक एवं ओएसडी नहीं बनाएगा। वन मंत्री नागर सिंह चौहान ने वित्त सेवा के अधिकारी रंजीत सिंह चौहान को बगैर सक्षम अनुमति के अपना विशेष सहायक बनाकर काम लेना शुरू कर दिया था। रंजीत सिंह पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उमंग सिंघार के स्टाफ में भी रहे हैं। रंजीत सिंह वित्त विभाग से बगैर अनुमति के पिछले 6 महीने से नागर सिंह के बंगले पर काम कर रहे थे। सामान्य प्रशासन विभाग ने भी रंजीत सिंह की सेवाएं वन मंत्री के स्टाफ में देने से इनकार कर दिया था। इस बीच मंत्री नागर सिंह के दबाव में पिछले दिनों एसीएस वित्त ने रंजीत सिंह को एनओसी देने के लिए अलग से फाइल चलाई थी।

सूत्रों का कहना है कि वन मंत्री रहते नागर सिंह चौहान ने अपने आसपास ऐसे लोगों का कॉकस बना लिया था, जो वन विभाग के अफसरों के कामकाज में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। प्रदेश के आईएफएस अफसरों ने भी रंजीत सिंह की कार्यशैली को लेकर मुख्यमंत्री तक गंभीर शिकायतें दर्ज कराई थीं। मुख्यमंत्री द्वारा वन विभाग की जिम्मेदारी नागर सिंह से लेकर रामनिवास रावत को सौंपने के निर्णय को एक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है क्योंकि वन मंत्री की कार्यशैली को लेकर संगठन से भी शिकायतों के स्वर उठ रहे थे। वैसे मुख्यमंत्री चाहते तो अपने पास के विभागों से कोई भी विभाग रामनिवास रावत को दे सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा न करते हुए नागर सिंह चौहान के कद को कम करना उचित समझा।

राजनीतिक प्रेक्षक यह मानकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैबिनेट की छवि को लेकर सख्त संदेश देना चाहते हैं। इस फेरबदल के साथ डॉ. मोहन यादव ने एक साथ दो संदेश दे दिए हैं। पहला किसी भी कीमत पर सरकार की छवि से समझौता नहीं किया जाएगा, दूसरा सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ही शासन में सर्वोच्च प्राधिकारी है इसके निर्देशों की अवहेलना भी स्वीकार नहीं होगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद उन सभी मंत्रियों के अनाधिकृत स्टाफ में भी खलबली मच गई है जो बगैर अनुमति के मंत्रियों के बंगले पर काम कर रहे हैं। अक्सर देखने में आता है कि नई सरकार बनते ही भोपाल में अफसरों का एक रैकेट सक्रिय हो जाता है जो वर्षों से मंत्रियों के स्टाफ में सेवाएं दे रहा है। कुछ अधिकारी तो दिग्विजय सिंह सरकार के समय से ही काम कर रहे हैं। इन्हीं दागदार अफसरों के कारण मंत्रियों की अक्सर फजीहत होती रहती है। संगठन स्तर पर भी इन्हें लेकर नाराजगी की बात सामने आती रहती है। बेहतर होगा कि सरकार के स्तर पर मंत्रियों के स्टाफ खासकर विशेष सहायक और ओएसडी की भर्ती के लिए एक मैकेनिज्म विकसित किया जाए। एक बार से अधिक किसी अफसर को मंत्री स्टाफ में पदस्थी की पात्रता ही न हो। अभी आलम यह है कि महिला बाल विकास, वित्त जैसे महकमों के दर्जनों अधिकारी वर्षों से मंत्रियों के स्टाफ में पदस्थ हैं।

गौरतलब है कि नागर सिंह चौहान की पत्नी अनीता चौहान हाल में हुए लोकसभा चुनाव में सांसद के तौर पर चुनी गई हैं। वह झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट से सांसद बनी हैं। यही कारण है कि नागर सिंह चौहान के विभाग में कटौती करके उन्हें अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली विभाग दिया गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसी कारण नागर सिंह चौहान को अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली विभाग दिया गया है। जानकारों का कहना है कि पार्टी नहीं चाहती है कि एक ही घर में पावर सेंटर बने। इसलिए नागर सिंह चौहान का मंत्रिमंडल में कद कम किया गया है।

● **सुनील सिंह**

अब जिलों के प्रभार का इंतजार

रामनिवास रावत को विभाग दिए जाने के बाद अब मंत्रियों को जिलों के आवंटन जल्द होने की उम्मीद जाग गई है। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के पहले मंत्रियों को जिलों के प्रभार का बंटवारा हो जाएगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ऐलान कर चुके हैं कि मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में झंडा फहराएंगे। पिछले दिनों दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके हैं। रामनिवास रावत को विभाग दिए जाने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रियों की प्रभार वाले जिलों की लिस्ट जारी हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के दौरान श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक कांग्रेस के सीनियर नेता रहे रामनिवास रावत ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। लंबे इंतजार के बाद सरकार में उन्हें 8 जुलाई को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई थी। इसके पहले उन्होंने विधानसभा में अपना इस्तीफा भेज दिया था। 12 दिन बाद उन्हें अब विभाग आवंटित कर दिया गया है। उधर, जल्द ही विजयपुर सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। रामनिवास रावत का इस सीट से मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि अंदरूनी विरोध के चलते उनकी राह आसान नहीं दिखाई दे रही है।

सीएम मोहन से पदोन्नति की आस

मप्र में कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पुरानी पेंशन

प्रदेश सरकार द्वारा अंशदायी पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) प्राप्त सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों को पेंशन फंड मैनेजर नियुक्त करने के लिए ज्यादा विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। यानी केंद्र सरकार के समान मप्र सरकार के 1 जनवरी 2005 के बाद सेवा में आए अंशदायी पेंशन योजना वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए योजना को विस्तारित किया गया है। जिससे कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता के अनुरूप एक से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर सकेंगे। जोखिम क्षमता के आधार पर निवेश की सीमा भी निर्धारित कर दी है। हालांकि नए विकल्प नहीं चुनने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को मौजूदा व्यवस्था का लाभ मिलता रहेगा। अभी तक मप्र सरकार के कर्मचारी पीएफआरडीए द्वारा अधिकृत पेंशन फंड एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई में निवेश करते आ रहे हैं। अब अंशदायी पेंशन योजना के कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन फंड में निवेश का मौका मिलेगा। हालांकि मप्र सरकार के वित्त विभाग ने अभी तक विकल्प के तौर पर नए पेंशन फंड की सूची जारी नहीं की है।

मप्र के कर्मचारियों का दुर्भाग्य ही है कि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस की सरकारों में भी उनकी पदोन्नति का रास्ता नहीं खुल सका है। राजनीतिक नफा नुकसान के फेर में प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार पदोन्नति देने से बच रही है। इसके लिए न्यायालय को सरकार बतौर हथियार प्रयोग कर रही है। इसकी वजह से सरकार को आर्थिक हानि तो हो ही रही है, साथ ही बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भी बगैर पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होना पड़ रहा है। यह बात अलग है कि इस दौरान पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए जरूर जमकर दिखावा किया गया है।

दरअसल प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले को लेकर विवाद की स्थिति बनने के बाद सरकार ने इस मामले से खुद को अलग करने के लिए मामले को टालना ही उचित समझा है। यही वजह है कि मामला सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। इस बीच मामले की सुनवाई के लिए सरकार वकीलों को करीब 20 करोड़ की फीस का भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा मंत्रियों की समिति से लेकर अन्य तरह के दिखावटी प्रयास भी कर चुकी है। इस बीच शिवराज सरकार फिर कमलनाथ और फिर शिवराज सरकार के बाद अब प्रदेश में डॉ. मोहन यादव की सरकार आ गई है। पुरानी सरकारों से निराशा हाथ लगने के बाद अब नई सरकार से कर्मचारियों को इस मामले में उम्मीद लगी हुई है। पदोन्नति का मामला भले ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन मप्र हाईकोर्ट कई प्रकरणों में कहा चुका है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। हाईकोर्ट में अलग-अलग बेंचों में लगे कुछ प्रकरणों में सुनवाई के बाद सरकार को कर्मचारियों को पदोन्नति देनी पड़ी है। इस बीच प्रदेश में करीब सवा लाख कर्मचारियों को बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त होना पड़ा है। दरअसल मप्र में पिछले आठ वर्ष से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नतियां नहीं हुई हैं। वर्ष 2016 में जबलपुर हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त कर दिया था। तब से अब तक तीन सरकार बदल चुकी हैं, लेकिन कोई भी सरकार पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल पाई है। मामला पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। इसको लेकर शिवराज सरकार ने समिति भी बनाई और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से नियम भी बनवाए पर उनका फायदा कर्मचारियों को नहीं मिल सका है। इस बीच हजारों अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए ही सेवानिवृत्त होने को मजबूर हो चुके हैं।

शिवराज के बाद कमलनाथ सरकार भी 15 माह के लिए आई पर उसने भी कुछ नहीं किया। मार्च 2020 में फिर शिवराज सरकार बनी और उन्होंने पदोन्नति के विकल्प के रूप में उच्च पद का प्रभार देने का निर्णय लेकर कर्मचारियों को साधने का प्रयास किया। प्रकरण अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अब 2016 के बाद से यह चौथी सरकार है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि मोहन सरकार पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कोई ठोस प्रयास कर इसका रास्ता निकालेगी। इसी बीच पशुपालन विभाग, नगर निगम, स्कूल शिक्षा समेत कुछ विभागों के कर्मचारियों ने पदोन्नति को लेकर सिंगल-सिंगल याचिकाएं लगाई। जिसमें उन्हें पदोन्नति का लाभ भी मिल गया है। हाईकोर्ट ने कई प्रकरणों में कहा है कि पदोन्नति में कोई रोक नहीं है। सपाक्स के अध्यक्ष केएस तोमर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति पर कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पदोन्नति के आदेश को पालन करवाने के मामले में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कई प्रकरणों में हाईकोर्ट ने कहा है कि पदोन्नति पर कोई रोक नहीं है। वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जा सकती है। लेकिन सरकार पदोन्नति ही नहीं देना चाहती है। पदोन्नति प्रारंभ करने के लिए सरकार को रास्ता जल्द निकालना चाहिए। पदोन्नति न होने से कर्मचारियों में हताशा का भाव बढ़ रहा है। नियम में समानता न होने के कारण भी प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। कनिष्ठ अपने वरिष्ठ से ऊपर निकल गए हैं। इसका प्रभाव सरकारी दफ्तरों की कार्य संस्कृति पर भी पड़ रहा है।

राज्य सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को प्रशासन अकादमी के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति से 15 जनवरी 2021 तक अनुशंसा मांगी थी। तय समय से कुछ दिन बाद समिति ने अपनी अनुशंसा दे भी दी, लेकिन उन पर अमल ही नहीं किया गया। इसके बाद सरकार ने 13 सितंबर 2021 को तत्कालीन गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन कर दिया। समिति ने अपनी अनुशंसा तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी। इसके बाद कुछ विभागों में कार्यवाहक पदोन्नति का रास्ता निकाला गया, लेकिन उसका भी पूरी तरह से कर्मचारियों को फायदा नहीं मिल सका है। मप्र के लगभग 7 लाख कर्मचारियों का 8 साल से पदोन्नति का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। वैसे इसे लेकर सरकार भी गंभीर नहीं है और दो साल में दो समितियां भी बना चुकी हैं, पर समितियों की अनुशंसा का लाभ सिर्फ कार्यवाहक पदोन्नति में सिमट गया है।

● **अरविंद नारद**

दोगुना बढ़ेगी विकास की गति

मप्र में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। पिछले 20 वर्षों में राज्य में तेज गति से आर्थिक विकास देखने को मिला है। अब प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार 5 साल में विकास की गति दोगुना बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 5 वर्ष बाद यानी वर्ष 2028-29 में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यानी वर्तमान मप्र सरकार ने अगले 5 साल में अपने बजट का आकार बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विधानसभा में हाल में मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कई मौकों पर अगले 5 वर्षों में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ रुपए वार्षिक तक ले जाने का ऐलान कर चुके हैं। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि बजट का आकार बढ़ाकर दोगुना करने का कार्य चुनौतीपूर्ण है। सरकार जिस अनुपात में अपना बजट बढ़ाना चाहती है, उसी अनुपात में उसे अपने राजस्व में वृद्धि करना होगी। यह संभव नहीं है कि सरकार का खर्च बढ़ जाए और उसकी आय में वृद्धि न हो।

अगर आंकलन किया जाए तो पिछले 20 साल में मप्र की जीडीपी करीब 20 गुना बढ़ी है। 2003 में भाजपा सरकार बनने के समय राज्य की जीडीपी 71,594 करोड़ रुपए थी, जो कि शिवराज सरकार के दौरान बढ़कर 13,22,821 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं, वर्ष 2003 मे प्रदेश की आर्थिक विकास दर 4.43 प्रतिशत हुआ करती थी, जो वर्ष 2023 में 16.43 प्रतिशत पर आ गई। इसके साथ ही प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 2003 में मात्र 11,718 रुपए हुआ करती थी, वर्ष 2023 तक शिवराज सरकार में 1 लाख 40 हजार रुपए हो गई है। ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि वर्ष 2028-29 में प्रदेश का बजट 7 लाख करोड़ करने का लक्ष्य पूरा हो सकता है।

2003 से अब तक यदि मप्र की आर्थिक रफ्तार पर नजर डालें तो उसमें आमूलचूल परिवर्तन नजर आता है। मप्र का 2003 में बजट 23 हजार करोड़ रुपए था जो अब बढ़कर 3 लाख 14 हजार करोड़ रुपए हो गया। जबकि 2024 में 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मप्र सरकार ने अगले 5 साल में अपने बजट का आकार बढ़ाकर दोगुना करने का जो लक्ष्य निर्धारित किया वह पूरा हो सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए बगैर सरकार के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। अगर सरकार पांच साल में अपने बजट को दोगुना करने में सफल होती है, तो यह प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार ने विधानसभा में 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मप्र को जीएसटी से 51,557 करोड़ तो 2024-25 में 61,026 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। राज्य उत्पाद शुल्क से 2023-24 में 13,845 करोड़, 2024-25 में 16,000 करोड़ स्टाम्प व पंजीकरण शुल्क से 2023-24 में 10,400 करोड़, 2024-25 में 12,500 करोड़, वाहन कर से 2023-24 में 4,440 करोड़, 2024-25 में 5,500 करोड़, विद्युत कर व शुल्क से 2023-24 में 3,858 करोड़, 2024-25 में 5,000 करोड़, अन्य प्राप्तियां से 2023-24 में 2,400 करोड़ और 2024-25 में 2,071 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने 3 जुलाई को विधानसभा में मप्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का 3.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। बजट की राशि पिछले साल से 16 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार का पिछला बजट 3.14 लाख करोड़ रुपए का था। बजट भले ही 3.65 लाख करोड़ का है, लेकिन विभागों को 2.20 लाख करोड़ में से राशि आवंटित की जाएगी। दरअसल, 3.65 लाख करोड़ रुपए के बजट में लेखानुदान की 1.45 लाख करोड़ रुपए की राशि भी शामिल है। सरकार ने मार्च में विधानसभा में 1.45 लाख करोड़ का अंतरिम बजट पेश किया था। इसमें चार महीने (अप्रैल से जुलाई तक) के लिए विभागों को खर्च के लिए राशि आवंटित की गई थी। इस तरह 3.65 लाख करोड़ की बजट राशि में से 1.45 करोड़ रुपए लेप्स हो जाएंगे। बचे हुए 2.20 लाख करोड़ रुपए विभागों को 8 महीने के लिए आवंटित किए जाएंगे। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विभागों को बजट की राशि आवंटित की जाएगी। विभाग इस राशि को अगस्त 2024 से मार्च 2025 तक खर्च कर सकेंगे।

● **प्रवीण सक्सेना**

हर साल 75 हजार करोड़ की वृद्धि

आगामी 5 साल में सालाना बजट 7 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए सरकार को हर साल बजट में करीब 75 हजार करोड़ रुपए की वृद्धि करनी होगी। इससे विभागों को और ज्यादा राशि आवंटित होने से विकास कार्यों के लिए भी ज्यादा राशि मिल सकेगी। आर्थिक विशेषज्ञ व भारत आर्थिक परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. देवेंद्र विश्वकर्मा का कहना है कि निश्चित ही मप्र को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाने के लिए बजट में वृद्धि करना जरूरी है, लेकिन बजट की राशि बढ़ाने के लिए सरकार को उसी अनुपात में अपनी आय भी बढ़ानी होगी। चूंकि केंद्र सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में प्रदेश को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में वृद्धि की संभावना है, लेकिन यह राशि फिक्स होती है। सिर्फ इसके भरोसे मप्र सरकार बजट नहीं बढ़ा सकती। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स में वृद्धि राजस्व बढ़ाने का तरीका नहीं है। ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा कि टैक्स की ठीक से वसूली हो और हर पात्र व्यक्ति टैक्स देने से वंचित न रहे। सरकार को मिनिमम टैक्स, मैक्सिमम कलेक्शन की पॉलिसी अपनानी होगी और प्राप्त होने वाले राजस्व का सही तरीके से उपयोग हो, इस पर गंभीरता से काम करना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश सरकारों की आय के साधन कम हो गए हैं। मप्र सरकार को भी चुनिंदा मदों से ही राजस्व मिल रहा है। इनमें एसजीएसटी, आबकारी, खनिज, विद्युत टैक्स, पेट्रोल-डीजल पर वैट, स्टाम्प व पंजीकरण, वाहन कर आदि शामिल हैं, लेकिन इनमें भी कई तरह के लीकेज हैं, जिन्हें रोककर सरकार राजस्व में वृद्धि कर सकती है।

आयोगों को ही न्याय की दरकार

मप्र में जरूरतमंदों और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए गठित आयोगों को इस समय खुद न्याय की दरकरार है। इसकी वजह यह है कि कई आयोगों के पास न तो चेयरमैन और न ही सदस्य हैं। इस कारण आयोगों में हजारों शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। न्याय के लिए पीड़ित आयोगों के चक्कर काट रहे हैं। न्यास की आस में आने वाले पीड़ितों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही हैं। आयोग लोगों को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। आम लोगों की समस्याओं पर सुनवाई करने वाले आयोगों में अध्यक्ष और सदस्य नहीं हैं। ये कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। ये मामले दर्ज करने तक सीमित हो गए हैं। इसका नतीजा ये है कि यहां पहुंचने वालों की संख्या कम हो गई है।

मप्र में आयोगों का गठन इसलिए किया गया है कि उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन अध्यक्ष और सदस्य विहीन आयोग वीरान पड़े हुए हैं। राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, माइनॉरिटी कमीशन सहित सभी प्रमुख आयोग में अध्यक्ष नहीं है। फरवरी 2024 में सभी को भंग कर दिया गया। इससे पहले भी इनका कामकाज प्रभावित हुआ। जिससे शिकायतें तो पहुंचीं लेकिन निराकरण नहीं हुआ। वर्ष 2018 में विधानसभा चुनाव के चलते आयोग अध्यक्ष विहीन होना शुरू हो गए थे। सरकार का गठन होते-होते अधिकतर आयोग कागजी हो गए। कुछ का कार्यकाल पूरा हो गया तो कुछ ने पद छोड़ दिया। राज्य महिला आयोग का कार्यकाल जनवरी 2019 में पूरा हो गया था। अब यहां शिकायतों को फाइल में रख लिया जाता है।

श्यामला हिल्स स्थित आयोग में लंबे समय से बेंच नहीं लगी। आयोग में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान में किसी की नियुक्ति नहीं है। यहां महिलाएं फरियाद लेकर आती हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पा रही। प्रकरण लंबित हो जाते हैं। यह भी इन्हें विभागों तक फारवर्ड करने तक सीमित हो गया। मप्र में सबसे बुरी स्थिति महिला आयोग की है। मप्र में महिला अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण है कि राज्य महिला आयोग की बेंच सात साल से लगी ही नहीं है। दरअसल, आयोग में ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही सदस्य। इस कारण प्रदेशभर की पीड़ित महिलाएं न्याय के लिए भटक रही हैं। राज्य महिला आयोग में करीब 24 हजार मामले लंबित हैं, जबकि नियमानुसार किसी भी शिकायत पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई करनी होती है। आयोग में 2018 के बाद से बेंच ही नहीं लगी है, इस कारण पीड़ित महिलाओं के मामले बढ़ रहे हैं। आयोग में करीब 3500 महिलाएं हर साल महिला आयोग में शिकायत दर्ज करवाने पहुंचती हैं। बता दें कि 2018 में आयोग की अध्यक्ष लता वानखेड़े का कार्यकाल खत्म होने के बाद 2019 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने 18 मार्च 2020 को शोभा ओझा को आयोग का अध्यक्ष बनाया और सदस्यों की नियुक्ति भी की थी। किंतु उसके बाद फिर से भाजपा की सरकार आई और नियुक्तियों का मामला कोर्ट पहुंच गया। इस दौरान एक भी दिन बेंच नहीं लगी। इसके बाद से 2022 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण हिंसा पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। महिला आयोग में प्रदेशभर से प्रतिदिन 9 से 10 महिलाएं शिकायत दर्ज करवा रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण महिलाएं निराश होकर लौट रही हैं। अब तो महिलाओं को वहां जाने पर महिला थाना या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में काउंसिलिंग के लिए भेजा जा रहा है।

प्रशासन की अन्य एजेंसियों से जब शिकायतकर्ता को निष्पक्ष कार्यवाही नजर नहीं आती, तब आयोग में शिकायत की जा सकती है। आयोग की ओर से संबंधित विभाग से जांच प्रतिवेदन मांगा जाता है। विभाग के द्वारा आयोग को प्रेषित जांच से जब शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता तब आयोग की पीठ में मामले की सुनवाई होती है। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। संबंधित अधिकारियों की पेशी लगाकर सुनवाई करता है। मामले का निराकरण कर शासन को अनुशंसा भेजी जाती है, लेकिन आयोगों में अध्यक्ष-सदस्यों के नहीं होने से प्रकरणों में इस तरह की कार्यवाही नहीं की जा सकती।

● **रजनीकांत पारे**

इनकी भी स्थिति खराब

माइनॉरिटी कमीशन में एक अध्यक्ष और चार सदस्य होने चाहिए। लंबे समय से यहां कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों के भरोसे काम चल रहा है। आने वाली शिकायतों पर सुनवाई होने की बजाय वे विभागों को भेजी जा रही हैं। यहां पहले 100 से ज्यादा मामले आते थे। अब आधे भी प्रकरण नहीं बचे। अभी केवल बाल आयोग में अध्यक्ष और सदस्य हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग मामलों में सुनवाई कर रहा है। हाल में कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष-सदस्यों के पद मार्च 2023 से खाली पड़े हैं। इस बीच तीनों आयोगों में हजारों की संख्या में शिकायती पत्र पहुंचे, लेकिन निराकरण एक का भी नहीं हुआ। राज्य महिला आयोग के एक कर्मचारी ने बताया कि प्रतिमाह लगभग 300 शिकायतें आयोग को मिलती हैं। सालभर में करीब 3 हजार शिकायतें प्राप्त होती हैं। कुछ शिकायतें आयोग से संबंधित नहीं होतीं, उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। बाकी आवेदनों पर संबंधित विभागों से जांच प्रतिवेदन मंगाकर फाइल बनाकर रख लिया जाता है। इनमें से कुछ मामलों में जांच प्रतिवेदन उपरांत ही निराकरण हो जाता है। बचे हुए प्रकरणों में अध्यक्ष-सदस्य की नियुक्ति के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। यही स्थिति राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति आयोगों की है। इन आयोगों में भी शिकायतों की पेंडेंसी हजारों में है।

भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में साल 2028 में लगने वाला सिंहस्थ ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की निगरानी में प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में लगने वाले कुंभ की तरह सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक और हाईटेक तरीके से होने वाले कार्यों के कारण सिंहस्थ विकास की मिसाल बनेगा।

अबकी बार होगा ऐतिहासिक सिंहस्थ

प्रत्येक 12 वर्ष बाद उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ इस बार वर्ष 2028 में होगा। डॉ. मोहन यादव सरकार ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 18 हजार 840 करोड़ रुपए की योजना बनी है, जिसमें 19 विभिन्न विभागों के माध्यम से 523 कार्य कराना प्रस्तावित है। सिंहस्थ-2016 से पहले सरकार ने साढ़े चार हजार करोड़ रुपए के काम उज्जैन और उसके आसपास के जिलों में कराए थे। तब 100 से अधिक सड़कों को चौड़ा किया था और 11 पुल बनाए गए थे। इस बार चार गुना राशि खर्च कर काम कराने का प्रस्ताव तैयार हुआ है।

सिंहस्थ आयोजन में विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है। समिति सिंहस्थ-2028 के अंतर्गत कराए गए कार्यों की समीक्षा, कार्योत्तर स्वीकृति, अतिरिक्त राशि आवंटन के प्रस्ताव आदि पर निर्णय लेगी। मंत्रिमंडल समिति में उप मुख्यमंत्री द्वय जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ऊर्जा में प्रद्युम्न सिंह तोमर, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम टेटवाल को सदस्य नामित किया गया है। मप्र की मुख्य सचिव को समिति का सचिव बनाया गया हैं।

प्रस्तावित योजना में भाजपा के संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) की झलक दिखाई पड़ती है। विगत दिनों मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ से पहले उज्जैन-इंदौर संभाग को धार्मिक-आध्यात्मिक सर्किट के रूप में विकसित करें। कार्य योजना में पशुपतिनाथ मंदसौर, खंडवा स्थित दादा धूनी वाले, भादवा माता, नलखेड़ा, ओंकारेश्वर आदि तक सुगम आवागमन और उनके अधोसंरचना सुधार को सम्मिलित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षिप्रा नदी के घाटों का विस्तार किया जाए ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरलता से स्नान कर सकें। सड़क मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, गेस्ट हाउस विकसित किए जाएं। शहर में संचालित होटलों और धर्मशालाओं की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। अफसरों ने बताया कि आगामी सिंहस्थ में 9 अप्रैल से 8 मई की अवधि में 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान प्रस्तावित हैं। सिंहस्थ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। सिंहस्थ के लिए उज्जैन में भूमि के आरक्षण एवं भूमि के उपयोग की जानकारी एकत्रित की जाएगी। नक्शे एवं तालिका के साथ उसके विश्लेषण की जानकारी भी होगी। इसके लिए उज्जैन कलेक्टर तथा टीएनसीपी आयुक्त को राज्य शासन ने जिम्मेदारी सौंपी है, जो पिछले दो सिंहस्थों के आयोजन की जानकारी लेकर इसे तैयार करेंगे। दोनों से कहा गया है कि वे विशेष रूप से संपूर्ण मेला क्षेत्र की भूमियों के विभिन्न

700 करोड़ से शिप्रा को संवारेंगे

सिंहस्थ से पहले शिप्रा नदी के संरक्षण और स्वच्छता के लिए 17 घाटों के पुनरुद्धार के साथ आकर्षक रिवर फ्रंट की योजना बन चुकी है। वहीं उज्जैन और इंदौर का दूषित जल शिप्रा में मिलने से रोकना, उज्जैन में ग्राउंड वाटर रिचार्ज सुधारना और सप्त सरोवरों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है। सिंहस्थ की तैयारियों के क्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिप्रा के संरक्षण और संवर्धन सहित उज्जैन के विकास पर कई बैठकें ले चुके हैं। इसके बाद सरकार द्वारा लगभग 700 करोड़ रुपए बजट वाला एक्शन प्लान बनाया गया है। 2016 में हुए सिंहस्थ में जहां लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने शिप्रा में डुबकी लगाई थी, वहीं 2028 में ये संख्या दोगुनी होने की संभावना है। शिप्रा तट पर बने 17 घाटों को बेहतर कनेक्टिविटी से आपस में जोड़ा भी जाएगा। घाट पर ही गंदे पानी को साफ करने की सुविधाएं विकसित होंगी। करीब 22 किमी में फैले इन घाटों को ऐतिहासिक संरचना के हिसाब से पुनर्जीवित किया जाएगा। नहाने, दूषित जल, ठोस कचरे के प्रबंधन के साथ अनुष्ठान के लिए व्यवस्था होगी। नदी को दूषित करने वाले 11 शहरी, 20 ग्रामीण नाले डाइवर्ट होंगे। घाटों पर सेफ्टी चेन, लाइटिंग के साथ वेंडरों को भी व्यवस्थित किया जाएगा। 2028 के आयोजन को ध्यान में रखकर वर्तमान में बने प्लेटफार्मों का सुधार होगा, विक्रय क्षेत्र व्यवस्थित होगा।

श्रेणी में आरक्षण, उनके आवंटन, वास्तविक उपयोग की विस्तृत जानकारी तैयार करें। विभिन्न श्रेणी के आवंटनों, जैसे प्रमुख अखाड़े, सामाजिक-धार्मिक संस्थाएं एवं अन्य श्रेणियों की विस्तृत सूची व विगत दो सिंहस्थ मेलों में इनके क्षेत्रफल, मांग और संख्या का ट्रेंड भी तैयार करें।

सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के साथ-साथ संपूर्ण मालवा और निमाड़ के जिलों में भी विकास कार्य होंगे। वहीं इंदौर, सांवेर, देवास व उज्जैन नगरीय क्षेत्रों में वर्ष 2040 की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए जल-मल योजनाएं और सीवेज ट्रीटमेंट प्लान वर्ष 2027 से पहले पूर्ण कर लिए जाएंगे। कान्ह नदी सहित क्षिप्रा नदी में मिलने वाले सभी नदी-नालों का दिसंबर 2027 तक ट्रीटमेंट सुनिश्चित किया जाएगा। धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के सप्त सागरों का पर्यटन स्थल के रूप में विकास एवं सुंदरीकरण किया जाएगा। इंदौर-भोपाल सड़क मार्ग के रास्ते उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को सीधे मंदिर पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च कर महामृत्युंजय द्वार से त्रिवेणी संग्रहालय पार्किंग स्थल तक 3700 मीटर लंबा फोरलेन एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। 80 करोड़ रुपए खर्च कर मेघदूत वन पार्किंग स्थल से श्री महाकाल महालोक के नंदी द्वार तक 500 मीटर लंबा और 150 करोड़ रुपए खर्च कर इंदौर गेट रेलवे स्टेशन से हरिफाटक पुल तक 800 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। 116 करोड़ रुपए से महाकाल मंदिर के आसपास की सड़कों का विकास किया जाएगा। 153 करोड़ रुपए से रेलवे स्टेशन से महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे बनाया जाएगा। 84 करोड़ रुपए से 4.3 किलोमीटर लंबे महाकाल सवारी मार्ग को 15 से 24 मीटर चौड़ा कर हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में विकसित किया जाएगा। 30 करोड़ रुपए से पंचकोशी यात्रा मार्ग के सात पड़ाव स्थलों पर बुनियादी कार्य कराया जाएगा। देवास रोड फोरलेन सड़क परियोजना से छूटे हिस्से (नागझिरी से दताना तक) में 38 करोड़ 52 लाख रुपए से फोरलेन सड़क बनवाई जाएगी। उज्जैन को जोड़ने वाले शेष छह मुख्य मार्गों को चौड़ा किया जाएगा। क्षिप्रा रिवर फ्रंट परियोजना अंतर्गत ऐतिहासिक 17 घाटों का वास्तु चरित्र पुनजीर्वित करना और 24 किलोमीटर दायरे में सात नए घाट, दो बैराज बनाना है। उज्जैन शहर में 100 और उपनगरीय क्षेत्रों तक 16 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गत दिनों भोपाल और इंदौर के मेट्रो प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा के बाद कहा कि सुगम यातायात के लिए प्रदेश के बड़े नगरों जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में मेट्रो के साथ वंदे मेट्रो, रोपवे, इलेक्ट्रिक बस और केबल कार जैसे साधनों का उपयोग किया जाएगा। आगामी आवश्यकताओं की दृष्टि से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। यातायात के विकल्पों के उपयोग के अंतर्गत उज्जैन से ओंकारेश्वर रूट, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से ग्वालियर के लिए भी विचार कर जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के बड़े नगरों के लिए नए ट्रैफिक प्लान की जरूरत को देखते हुए राज्य सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण इंदौर-उज्जैन के मध्य मेट्रो ट्रेन के संचालन का निर्णय शामिल है, जो सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही की सुविधा की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। इंदौर-उज्जैन के मध्य मेट्रो चलाने से संबंधित फिजिबिलिटी सर्वे की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। आने वाले समय में इंदौर एयरपोर्ट से महाकाल मंदिर तक वंदे मेट्रो की सुविधा प्रदेशवासियों और देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के लिए एक अहम सौगात होगी। विभिन्न नगर परस्पर बेहतर ढंग से जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हाल ही में हुई चर्चा के अनुसार मप्र में विभिन्न नगरों के लिए वंदे मेट्रो चलाने पर सहमति हुई है। पुरानी मेट्रो के स्थान पर वंदे मेट्रो सर्किल ट्रेन नागरिकों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। ऐसे नगरों जहां यातायात का दबाव बढ़ रहा है, वहां मेट्रो ट्रेन संचालन की दृष्टि से समेकित रूप से योजना बनाने के लिए सर्किल ट्रेन की सुविधा प्रारंभ करने पर सहमति हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की रेल मंत्री से मेट्रो ट्रेन की स्पीड से भी अधिक स्पीड से वंदे मेट्रो के संचालन, अत्याधुनिक तकनीक के प्रयोग और पीथमपुर-देवास जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के संबंध में भी चर्चा हुई है।

उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के पहले स्पिरिचुअल सिटी बनाई जाएगी। इसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही, 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह दर्शन मिल सकें। इसका उद्देश्य उज्जैन के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाना है। डॉ. मोहन सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संबंधित विभाग के अफसरों की बैठक कर चर्चा करेंगे।

● **जितेंद्र तिवारी**

सिंहस्थ में आएंगे 14 करोड़ मेहमान

सिंहस्थ में आने वाले 14 करोड़ मेहमानों की पेयजल एवं सीवरेज व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की नर्मदा परियोजना का अमला भोपाल से उज्जैन स्थानांतरित होने वाला है। महकमे की मंत्री संपतिया उइके ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा गया है कि अमला, सिंहस्थ क्षेत्र में पेयजल एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए योजना बनवाएगा। योजना को धरातल पर उतारकर उसका संचालन और रखरखाव करेगा। मालूम हो कि स्थानीय अधिकारियों ने सिंहस्थ-2028 के लिए 18 हजार करोड़ रुपए की योजना बना रखी है, जिसमें 1148 करोड़ रुपए की योजना पेयजल एवं सीवरेज इंतजाम पर खर्च किए जाने का लेख है। इस राशि में 948 करोड़ रुपए मेला क्षेत्र में जल प्रदाय एवं सीवरेज पाइपलाइन बिछाने, उच्च स्तरीय पानी की टंकियां, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, पंपिंग मैन स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर प्रस्तावित कार्य योजना को अमलीजामा पहनाने को फिलहाल विस्तृत कार्य योजना यानी डीपीआर बनवाई जा रही है। स्पष्ट यह भी किया है कि लगभग 200 करोड़ रुपए से शहर की पेयजल व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। 2016 के सिंहस्थ में 7 करोड़ लोग उज्जैन आए थे। तब मेला 3062 हेक्टेयर जमीन पर लगा था। इस बार 14 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है।

अलग भील प्रदेश की मांग

देश के 4 राज्यों के 49 जिले मिलाकर भील प्रदेश बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस मांग को लेकर गत दिनों बासंवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित महारैली में राजस्थान, मप्र, गुजरात और महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम पहुंचे। महारैली में भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि वे हिंदू नहीं हैं। इस रैली में कई सांसद-विधायक भी शामिल हुए। मानगढ़ धाम आदिवासियों का तीर्थ स्थल है। राजस्थान सरकार भील प्रदेश की मांग पहले ही खारिज कर चुकी है। बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सांसद राजकुमार रोत का कहना है कि भील प्रदेश की मांग नई नहीं है। बीएपी पुरजोर तरीके से यह मांग उठा रही है। महारैली के बाद एक डेलीगेशन राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री से प्रस्ताव के साथ मुलाकात करेगा।

आदिवासी समाज ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मप्र के 49 जिलों को मिलाकर नया राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग की है। इसमें राजस्थान के पुराने 33 जिलों में से 12 जिलों को शामिल करने की मांग है। भील समाज की सबसे बड़ी संस्था आदिवासी परिवार सहित 35 संगठनों ने यह महारैली बुलाई थी। आदिवासी परिवार संस्था की संस्थापक सदस्य मेनका डामोर ने मंच से कहा, आदिवासी महिलाएं पंडितों के बताए अनुसार न चलें। आदिवासी परिवार में सिंदूर नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं पहनते। आदिवासी समाज की महिलाएं-बालिकाएं शिक्षा पर फोकस करें। अब से सब व्रत-उपवास बंद कर दें। हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी परिवार संस्था चारों राज्यों में फैली हुई है। आदिवासी परिवार के संस्थापक भंवरलाल परमार का कहना है कि इसी मानगढ़ में सौ-सवा सौ साल पहले हमारे पुरखों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, तब 1500 लोगों को मार दिया गया। उनका क्या कसूर था? अब हमने फिर आंदोलन शुरू किया है। कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता। भील प्रदेश की मांग तो समय पर पूरी होगी ही। इसकी एक प्रक्रिया होती है।

राजस्थान विधानसभा में भी अलग भील प्रदेश बनाने की मांग उठी है। विधानसभा में धरियावद से बीएपी विधायक थावरचंद मीणा ने कहा कि आज जब मैं सदन में बोल रहा हूं, उस समय मानगढ़ धाम में 4 राज्यों के 10 लाख आदिवासी महासम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों को गुजरात, महाराष्ट्र, मप्र और राजस्थान में बांट दिया गया है। हमारी बोली, संस्कृति, रीति-रिवाज एक है तो हम सब मिलकर भील प्रदेश क्यों नहीं बना सकते हैं? गहलोत ने कहा कि मैं भी प्रदेश की मांग जाति के आधार पर नहीं कर रहा हूं। जब गुजराती के नाम पर गुजरात, मराठी के नाम पर महाराष्ट्र, पंजाबी के नाम पर पंजाब राज्य बन सकता है तो भीली बोली के आधार पर भील प्रदेश क्यों नहीं बन सकता है। मैं मांग करता हूं कि इसका प्रस्ताव पास करके सरकार को भेजा जाए। उन्होंने कहा कि भील प्रदेश हमारा अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे।

संसद में लग चुके हैं भील प्रदेश के समर्थन में नारे लगाए

बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने पिछले दिनों लोकसभा में सांसद की शपथ लेने के दौरान भी भील प्रदेश के समर्थन में नारे लगाए थे। वे भील प्रदेश बनाने की मांग करते हुए ऊंट पर बैठकर संसद पहुंचे थे। बांसवाड़ा जिले के जिस मानगढ़ धाम पर यह रैली हो रही है, वह आदिवासियों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है और चारों प्रदेश के आदिवासियों से इसका भावनात्मक जुड़ाव है। मानगढ़ की पहाड़ी का एक हिस्सा गुजरात में और एक हिस्सा राजस्थान में शामिल है। इस पहाड़ी क्षेत्र में गोविंद गुरू नामक आदिवासी नेता ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। तब 19 नवंबर 1913 को इसी धाम पर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें व उनके आदिवासी साथियों को घेर लिया था। यहां अंग्रेजों ने 1500 आदिवासियों का सामूहिक नरसंहार किया था। उन्हीं की याद में मानगढ़ धाम बना हुआ है। गोविंद गुरू को जीवित पकड़ कर बंदी बना लिया गया था। राजनीतिक रूप से इसके महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां सभा की थी, ताकि इससे लगे गुजरात के आदिवासी क्षेत्र को साधा जा सके। वहीं राजस्थान के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यहां बड़ी रैली की थी।

राजस्थान में राजनीतिक ताकत मिलते ही बीएपी ने अन्य जिलों और राज्यों के आदिवासियों को साथ लेकर अलग राज्य और संगठन मजबूत बनाने की मुहिम तेज कर दी है। बीएपी के पास राजस्थान के आदिवासी जिले बांसवाड़ा से 2 विधायक और एक सांसद है, लेकिन भील प्रदेश की मांग को लेकर सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है। जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी का कहना है कि जाति के आधार पर स्टेट नहीं बन सकता। ऐसा हुआ तो अन्य लोग भी मांग करेंगे। हम केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं भेजेंगे। खराड़ी ने कहते हैं कि जिसने धर्म बदला उनको आदिवासी आरक्षण का लाभ न मिले। खराड़ी ने डूंगरपुर दौरे के दौरान यह बयान दिया।

आदिवासियों के भील प्रदेश के आंदोलन पर भाजपा के आदिवासी विधायक समाराम गरासिया कहते हैं कि जो आदिवासी खुद को हिंदू नहीं मानते, उन्हें आरक्षण का हक नहीं है। आदिवासी धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन जाते हैं। अगर वे हिंदू नहीं हैं तो आरक्षण का फायदा क्यों ले रहे हैं? ऐसे लोग आदिवासी क्षेत्र के लिए चलाई जाने वाली योजना का फायदा लेने के अधिकारी नहीं हैं। रैली में अलग-अलग राज्यों से आए नेताओं ने भील प्रदेश बनाने का राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया। भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) आदिवासी परिवार नाम के संगठन से ही निकली है। आदिवासी परिवार को भारत आदिवासी पार्टी के नेताओं के साथ सामाजिक विंग के लोग मिलकर चलाते हैं। इसके साथ ही भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा भी भारत आदिवासी पार्टी का ही संगठन है। आदिवासी हक, अधिकार और आरक्षण के मुद्दे को लेकर 10 साल से ये संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। पहले आदिवासी परिवार के नाम पर संगठन खड़ा किया। इसके बाद राजस्थान में बीटीपी पार्टी से चुनाव लड़े। पहली ही बार में 2 विधायक जीतने के बाद आदिवासी परिवार से जुड़े नेताओं ने ही भारत आदिवासी पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई। इसके अलावा कई सामाजिक कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी भी इस विंग का हिस्सा है।

● **विकास दुबे**

जांच पर जांच, नहीं आई किसी पर आंच

मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)में संविदा नियुक्ति घोटाला ऐसा मर्ज हो गया है जिसका इलाज सरकार को नहीं मिल पा रहा है। दरअसल, सरकार ने इस घोटाले की तीन जांच कराई है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी पर इसकी आंच नहीं आई है। अब पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने चौथी बार जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस बार, पंचायत राज के आयुक्त मनोज पुष्प और मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के सीईओ एस कृष्ण चैतन्य को जांच अधिकारी बनाया गया है। एमपी-एसआरएलएम भोपाल में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने वर्ष 2015 में भर्ती की थी। इसी में से राज्य स्तरीय नियुक्तियों को लेकर शिकायतें हुई थी कि ये कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संविदा नियमों के विपरीत की गई हैं। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल का कहना है कि जिन अधिकारियों पर दाग लगे हैं, उनको भी तो अपने बचाव का मौका दिया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 9 साल पहले संविदा नियुक्ति में फर्जीवाड़ा हुआ था। पहले तीन आईएएस अफसर जांच कर चुके हैं, अब उसी मामले की चौथी जांच शुरू हुई है। इसकी पहली जांच मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद की तत्कालीन सीईओ आईएएस नेहा मारव्या ने की थी। उसके बाद इसी जांच की पुष्टि तत्कालीन प्रमुख सचिव पंचायत उमाकांत उमराव और फिर वर्तमान अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी कर दी। माना गया कि संबंधित अधिकारियों को सुनवाई का पूरा समय दिया और जांच प्रतिवेदन सही है। तीनों जांच के बाद अब विभागीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह लिखते हुए चौथी जांच के आदेश दिए हैं कि उनको (फर्जीवाड़े के आरोपी अफसर) भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि यही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से महत्वपूर्ण है। खास बात यह है कि पहली जांच के बाद ठीक ऐसी ही लाइनें पूर्व पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने भी फर्जी नियुक्ति देने व पाने वालों के लिए लिखी थी, जिसके बाद जांच के घेरे में आ रहे अफसरों ने भी अपना पक्ष रखा था।

मप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में संविदा नियुक्ति घोटाले की पहली जांच मप्र राज्य रोजगार गारंटी की तत्कालीन सीईओ नेहा मारव्या ने की। नेहा मारव्या ने 8 जून 2022 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने लिखा है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल द्वारा संविदा नीति का पालन नहीं किया गया। तत्कालीन एसआरएलएम सीईओ ललित मोहन बेलवाल और तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास अवस्थी ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुषमा रानी शुक्ला को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज (एनआईआरडी) हैदराबाद भेजा था। एसआरएलएम की कर्मचारी होने के बाद भी उन्हें एनआईआरडी हैदराबाद में काम करने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार राज्य परियोजना प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के लिए एनआईआरडी से चोरी किए गए लैटरहेड पर वहां के डायरेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर करके नौकरी हासिल की गई। अनुभव प्रमाण-पत्र और शैक्षणिक दस्तावेज भी गलत लगाए गए। दूसरी बार जांच पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव द्वारा की गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच अधिकारी ने ललित मोहन बेलवाल को उनका पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया, लेकिन वे नहीं आए। रिपोर्ट से साफ लगता है कि गड़बड़ी की जानकारी उन्हें थी। इसके बाद मामला विभागीय मंत्री को और फिर मुख्यमंत्री समन्वय में चला गया। तीसरी जांच विभाग के वर्तमान अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने नवंबर 2023 को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री समन्वय और मुख्य सचिव से चर्चा के बाद पुन: विभाग को वापस की गई है। जांचकर्ता अधिकारी के जांच प्रतिवदेन में प्रस्तुत तथ्य व दस्तावेजों से प्रतीत होता है कि नियुक्ति संबंधी जांच प्रतिवेदन सही है। इसके बाद यह फाइल विभागीय मंत्री को भेज दी गई। आयुक्त पंचायती राज मनोज पुष्प का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है और इसे पूरा होने में समय लगेगा। जांच के बारे में फिलहाल कुछ और बताना संभव नहीं है।

जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बड़े स्तर पर नियुक्तियों की चर्चा हुई, तब शिकायतें शासन स्तर पर उछलीं, जिसकी जांच तत्कालीन ओएसडी और आईएएस नेहा मारव्या द्वारा की गई। 8 जून 2022 को मारव्या ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि ललित मोहन बेलवाल की गड़बड़ी की जानकारी के बाद भी तत्कालीन एसीएस इकबाल सिंह बैस और अन्य ने कार्रवाई नहीं की और मामला न उछले, इसके लिए ललित मोहन बेलवाल को परियोजना प्रबंधक के पद से इस्तीफा लेकर हटा दिया।

● **लोकेश शर्मा**

मंत्री के आदेश को नकारा, फर्जी एचआर गाइडलाइन भी बना डाली

आजीविका मिशन में भर्ती के मामले में अधिकारियों द्वारा जमकर भ्रष्टाचार तो किया ही गया, सरकार की आंखों में भी धूल झोंकी गई। जब गड़बड़ी की शिकायत पर 8 नवंबर 2017 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तत्कालीन मंत्री ने फाइल पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना अंतर्गत एनआरएलएम में भर्ती वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के माध्यम से जिला और जनपद स्तर पर भर्ती प्रक्रिया से मुझे अवगत कराया गया है। इस प्रकार की भर्ती के लिए पूर्व में भी कर्मचारी चयन का कार्य इस संस्था से नहीं कराया गया। चयन में पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता नितांत आवश्यक है, इस प्रक्रिया में किसी भी त्रुटि की गुंजाइश होने पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए पूर्व में लिए निर्णय पर पुनर्विचार कर भर्ती प्रक्रिया तत्काल निरस्त की जाए। लिखकर टीप दर्ज कर दी तो इन अधिकारियों ने उसे भी दरकिनार कर दिया। मंत्री के उस लिखित आदेश, जिसमें भर्ती के लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को अधिकृत करने कहा गया था, उसे भी नहीं माना। मिशन के ज्वॉइंट कमिश्नर राकेश शुक्ल के पत्र से भी बेलवाल द्वारा फर्जी ह्यूमन रिसोर्स गाइडलाइन बनाने और बैंस द्वारा मनमानी नियुक्ति के लिए उन्हें अधिकृत करने की पुष्टि भ्रष्टाचार को उजागर करती है।

बिना संचालक मंडल के हाउसिंग सोसायटियां

मप्र में गृह निर्माण सहकारी समितियों में वर्षों से चुनाव नहीं होने से हाउसिंग सोसायटियां ठप पड़ी हुई हैं। इस कारण समितियों में काम-काज ठप पड़े हुए हैं। आलम यह है कि सदस्यों के हित में न तो फैसले हो पा रहे हैं और न लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं। न ही पैसे वापस हो पा रहे हैं। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गृह निर्माण सहकारी समितियों में चुनाव कराए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में अधिकांश सहकारी समितियां भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं। प्रदेशभर में कई गृह निर्माण सहकारी समितियों के खिलाफ जांच चल रही है। इसके बावजूद विभाग गंभीर नहीं है। ज्यादातर हाउसिंग सोसायटियों में संचालक मंडल के चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। विभाग ने अधिकारियों को ही प्रशासक नियुक्त कर रखा है। यह स्थिति कई वर्षों से है। सोसायटियों का कामकाज ठप हो गया है। हालात यह हैं कि सदस्यों के हित में न तो फैसले हो पा रहे हैं और न लोगों को प्लॉट मिल रहे हैं। न ही पैसे वापस हो पा रहे हैं। भोपाल व इंदौर की 1438 सोसायटियों में से 802 में प्रशासक नियुक्त हैं।

प्रदेश में 2,110 गृह निर्माण सहकारी सोसायटियां पंजीकृत हैं। नियम यह है कि किसी भी गृह निर्माण सहकारी समिति के कामकाज का संचालन उसका संचालक मंडल करता है। रजिस्ट्रेशन के तीन माह के अंदर मंडल का चुनाव कराना अनिवार्य है। मंडल में 14 सदस्य होते हैं। इनमें से 11 को सोसायटी के सदस्य चुनते हैं। तीन सदस्य नामांकित होते हैं। संचालक मंडल के सदस्य ही अध्यक्ष, दो उपाध्यक्षों का चुनाव करते हैं। मंडल का कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके बाद सहकारिता अधिनियम के अनुसार यह स्वत: भंग हो जाता है। भोपाल-इंदौर की हाउसिंग सोसायटियों में सबसे ज्यादा घपले होने के बावजूद ज्यादातर में संचालक मंडल नहीं हैं। इन शहरों में 1438 हाउसिंग सोसायटी पंजीकृत हैं। इनमें से केवल 368 में ही संचालक मंडल हैं। यह जानकारी विधानसभा में विधायक कमलेश्वर डोडियार के सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। सारंग का कहना है कि जल्द ही सभी सहकारी सोसायटियों के चुनाव कराए जाएंगे। भोपाल, इंदौर की 268 सोसायटियों के परिसमापन की प्रक्रिया भी जारी है।

गृह निर्माण सहकारी समितियों में गड़बड़ियों की भरमार है। आलम यह है कि मूल सदस्य प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। भोपाल की रोहित हाउसिंग सोसायटी में मूल सदस्य सालों बाद भी प्लॉट के लिए भटक रहे हैं। गौरव सोसायटी में नए सदस्य बनाकर प्लॉट दे दिए गए। मूल सदस्य प्लॉट के इंतजार में बूढ़े हो गए हैं। बिट्ठल नगर सोसायटी में बाहरी लोगों को जमीन बेची गई, जिसका केस कोर्ट में है। टीकमगढ़ की 21 समितियों में से छह परिसमापन की प्रक्रिया में हैं। इनमें इंदिरा गृह निर्माण समिति में सबसे ज्यादा अनियमितताएं हैं। लोग प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए परेशान हैं। किसी के नाम पर आवंटित प्लॉट दूसरे को बेच दिया गया है। अध्यक्ष पद पर सालों से एक ही परिवार का कब्जा है। समिति ने एक वर्ग के लोगों को प्लॉट दिए हैं। खंडवा में 38 समितियां हैं। इनमें से 15 का परिसमापन हो चुका है। वर्तमान में 23 समितियों में संचालक मंडल हैं। इसमें से 5 में 5 साल से ज्यादा समय से चुनाव नहीं हुए हैं। इस कारण प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। रेरा लागू होने के बाद नई समितियों का पंजीयन भी नहीं हुआ है। इंदौर में जागृति गृह निर्माण संस्था की जमीन पर मूल सदस्यों के प्लॉट कर्ताधर्ताओं ने सविता गृह निर्माण संस्था को बेचा। इसमें जालसाज बॉबी छाबड़ा भी शामिल था। इस वजह से कॉलोनी राजगृही में प्लॉट कम हो गए, जिसके बाद नया नक्शा पास किया गया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ग्वालियर जिले की 303 समितियों में संचालक मंडल हैं। योगेंद्र कुमार ने सहकारी गृह निर्माण आवास संघ में भू-आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की। इसी तरह अजीत कुमार बनर्जी ने आदित्य रेसीडेंसी कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की शिकायत की है। सतना में 16 जिले में गृह निर्माण समितियां हैं। इनमें से 15 परिसमापन में हैं। कामदगिरी समिति में तत्कालीन अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने परिजनों के नाम पर प्लॉट आवंटित करा दिया था, जिनकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। अधिकारियों के दखल के बाद 32 रजिस्ट्री शून्य घोषित की गईं। इनकी जांच चल रही है।

गौरतलब है कि गृह निर्माण सोसायटियों द्वारा बेची गई जमीन, प्लॉट के संबंध विकास अनुज्ञा से लेकर, नामांतरण, अंतरण के संबंध में अब कोई अनापत्ति और एनओसी जारी नहीं होगी। इस संबंध में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाओं की तरफ से रोक लगा दी गई। कई गृह निर्माण सोसायटियों में फर्जी तरीके से मतदान कराने के बाद वास्तविक सदस्यों के प्लॉटों की बिक्री के मामले सामने आने के बाद इस संबंध में शासन की तरफ से नई गाइडलाइन बनाई जा रही है। जब तक यह सामने नहीं आती, रोक लगी रहेगी। राजधानी में 535 गृह निर्माण सोसायटी हैं, इसमें से 270 ही सही तरीके से काम कर रही हैं। बाकी विवादित हैं, तो काफी में प्रशासक नियुक्त हैं। आदेश में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं द्वारा विक्रय की भूमियों के संबंध में नए दिशा-निर्देश और प्रावधान (एसओपी) बनाए जा रहे हैं।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

रोहित गृह निर्माण की 143 अपात्र रजिस्ट्रियां होंगी शून्य

जिले की विवादित रोहित गृहनिर्माण समिति के अपात्र 143 प्लाटों की रजिस्ट्री शून्य करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उपायुक्त सहकारिता भोपाल ने सिविल कोर्ट में प्रकरण दायर कर दिया है। दरअसल प्लाटों की रजिस्ट्री शून्य करने के निर्देश 13 वर्ष पहले तत्कालीन संचालक मंडल को जांच अधिकारी ने दिए थे। तब ही से यह मामला अटका हुआ था। बता दें कि सहकारिता विभाग ने वर्ष 2004-05 में बावड़ियाकलां स्थित रोहित गृहनिर्माण समिति के अनियमितता और फर्जीवाड़े के आरोपों के सामने आने के बाद जांच कराई थी। मौजूदा उपायुक्त सहकारिता छविकांत वाघमारे ने बताया कि रोहित गृहनिर्माण समिति के अपात्र सदस्यों के 143 प्लाटों की अवैध रजिस्ट्री शून्य कराने के लिए सिविल कोर्ट में प्रकरण लगाया गया है। इन रजिस्ट्रियों को शून्य कराने के बाद बचे हुए पात्र सदस्यों को वरिष्ठता सूची के आधार भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

सहकारिता में दिखेगा आधी आबादी का दम

म प्र में 11 साल बाद 4524 कृषि सहकारी संस्थाओं के चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत की तरह ये चुनाव भी राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह पर नहीं होते, मगर संस्थाओं से जुड़े 66 लाख किसानों को साधने के लिए पार्टियों का पूरा दखल होता है। लंबे समय बाद होने वाले इन चुनावों को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू की हैं। भाजपा की कोशिश है कि महिलाओं के लिए आरक्षित पदों के अलावा बाकी पदों पर भी महिलाएं चुनी जाएं।

सहकारी समितियों का कार्यकाल मार्च 2018 में खत्म हो गया था, लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार ने चुनाव कराने के बजाय यहां प्रशासक नियुक्ति कर दिए। कमलनाथ सरकार ने भी इन संस्थाओं में चुनाव नहीं कराए। इसके बाद फिर सत्ता में लौटी शिवराज सरकार ने भी पूरे कार्यकाल में इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब तक प्राथमिक सहकारी संस्थाओं से लेकर जिला सहकारी बैंक और अपेक्स बैंक में प्रशासक नियुक्त हैं। फिलवक्त मप्र राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि विपणन संघ, राज्य सहकारी आवास संघ, राज्य उपभोक्ता संघ, राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ, स्टेट डेयरी फेडरेशन, राज्य सहकारी बुनकर संघ, सहकारी लघु वनोपज संघ, राज्य सहकारी औद्योगिक संघ, सिल्क फेडरेशन, राज्य सहकारी बीज उत्पादक संघ, सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम जैसी बड़ी सहकारी संस्थाओं में प्रशासक बैठे हैं।

प्रदेश में सहकारिता पर कभी कांग्रेस का पूरी तरह कब्जा था पर दो दशक से लगातार सत्ता में रही भाजपा ने अब पूरा परिदृश्य ही बदल दिया है। अधिकांश सहकारी बैंकों में उसके ही समर्थक नेता अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और डायरेक्टर बनते हैं। हालांकि चुनाव न होने से समितियों पर प्रशासकों को तैनात किया गया है। सहकारिता चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। लेकिन सदस्य सूची नहीं बन पाने के कारण कुछ महीने के लिए चुनाव टल गए हैं। सहकारी समितियों का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था, पर तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने तब चुनाव नहीं कराए। कमलनाथ सरकार के पतन के बाद बनी शिवराज सरकार ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। इस बीच इन चुनावों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। कोर्ट ने दिसंबर में सरकार को आदेश दिया कि वह चुनाव 10 मार्च 2024 के पहले कराए। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया है। हालांकि भाजपा का सहकारिता प्रकोष्ठ अभी चुनाव प्रक्रिया शुरू किए जाने के पक्ष में नहीं है, उसका कहना है कि बरसात में चुनाव नहीं होने चाहिए। उसने अक्टूबर-नवंबर में चुनाव की मांग की है। फिलवक्त चुनाव प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब फिर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है। भाजपा आरक्षित पदों के अलावा अन्य पदों पर भी इनकी भागीदारी चाहती है। इसे लेकर संगठन नेताओं की बैठक हो चुकी है।

जिलाध्यक्षों और विधायकों से कहा गया है कि वे क्षेत्र की सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं को इन चुनावों में भागीदारी करवाएं। प्राथमिक साख समितियों के चुनाव के बाद को-ऑपरेटिव बैंक और राज्य स्तरीय अन्य सहकारी संस्थाओं के चुनाव बेहद अहम होते हैं। इन चुनावों में हर ब्लॉक से एक डायरेक्टर चुना जाएगा। बैंक की सदस्य संख्या के हिसाब से 11 से 14 डायरेक्टर चुने जाते हैं। ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके अलावा हर संभाग से एक डायरेक्टर चुना जाता है जो अपेक्स बैंक के अध्यक्ष का चुनाव करता है। इनमें भोपाल और इंदौर जैसे बड़े संभागों से दो डायरेक्टर भी चुने जाते हैं पर इनकी संख्या अधिकतम 15 ही हो सकती है। इन डायरेक्टरों में एक राष्ट्रीय सहकारी बैंक एसोसिएशन और एक राष्ट्रीय सहकारी संघ में प्रतिनिधि के तौर पर भेजा जाता है।

कृषि सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के 9 हजार से ज्यादा पद आरक्षित हैं। भाजपा चाहती है कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हर संस्था में 11 डायरेक्टर बनाए जाते हैं। जिसमें से 2 महिलाएं होती हैं। यह डायरेक्टर अपनी संस्था के अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष व जिला सहकारी बैंक के प्रतिनिधि चुनते हैं। 2 उपाध्यक्ष में से एक महिला उपाध्यक्ष का बनना तय है। इस हिसाब से देखें तो 4524 संस्थाओं में 9 हजार 48 महिलाएं उपाध्यक्ष बनेंगी। लेकिन, सूत्र कहते हैं कि भाजपा आरक्षित पदों के अलावा बाकी पदों पर भी महिलाओं को मौका देना चाहती है। हालांकि, बारिश के सीजन में होने वाले इन चुनावों को लेकर भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ ने आपत्ति दर्ज करते हुए इन्हें अक्टूबर या नवंबर में करवाने की मांग सरकार से की है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई जमीन को वापस लेने की कोशिश कर रही है। ये चुनाव सितंबर से पहले हो जाएंगे। कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुभाष यादव की राजनीति सहकारिता से ही शुरू हुई थी। 1998 से 2003 तक जब यादव उपमुख्यमंत्री रहे, तब कांग्रेस से चुने गए 45 विधायकों की पृष्ठभूमि में सहकारिता थी।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

ग्वालियर-चंबल में नहीं हो पाएंगे चुनाव

ग्वालियर-चंबल संभाग की सहकारी संस्थाओं में चुनाव होने के आसार नहीं है। इसकी वजह यह है कि यहां के 99 फीसदी किसान डिफॉल्टर हैं। चुनाव की पात्रता के लिए किसान का सहकारी बैंक से लोन लेना अनिवार्य है। लेकिन किसान डिफॉल्टर होता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कहते हैं कि 2018 के चुनाव में कमलनाथ ने घोषणा की थी कि सरकार किसानों का ब्याज माफ करेगी, लेकिन नहीं किया। तब से लेकर अब तक बड़ी संख्या में किसान डिफॉल्टर हो गए हैं। सोसाइटी को जो अंशदान मिलता है, वह साल के अंत में जमा होना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा दो-दो साल तक राशि जमा नहीं कराने के कारण सोसाइटी भी डिफॉल्टर हो गई है। जो सोसाइटी डिफॉल्टर होती है, वहां चुनाव नहीं हो सकता है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव तीन महीने के लिए टलने की भी संभावना है। भाजपा सहकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर का कहना है कि जुलाई-अगस्त में चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने की संभावना है। उनका तर्क है कि इन दिनों में किसान खेत नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यह समय फसलों की बुवाई का होता है। जानकार भी मानते हैं कि सहकारी समितियों के चुनाव बारिश के मौसम में नहीं हो सकते हैं।

जंगल में खैर नहीं...

खैर के गोंद से लेकर लकड़ी तक कीमती

खैर का पेड़ बेहद कीमती एवं मजबूत होता है। खैर के गोंद में कई औषधीय गुण होते हैं, इसलिए इसके गोंद का उपयोग कई प्रकार की दवाओं में होता है। खैर की लकड़ी से ही कत्थे का निर्माण होता है और खैर की लकड़ी का कोयला सबसे महंगा व अच्छा कोयला होता है। सरकार के नियमानुसार वन विभाग को खैर के एक-एक पेड़ का हिसाब रखना होता है। सूखकर गिरे पेड़ को वन विभाग कत्था बनाने वाली फैक्ट्री को नीलामी में बेचता है, लेकिन पहाड़गढ़ में यह बेशकीमती पेड़ काटकर आग के हवाले कर राख में तब्दील कर दिया गया है। मुरैना के डीएफओ स्वरूप दीक्षित का कहना है कि जिस तरह की स्थिति बताई जा रही है, वह बेहद चिंताजनक है। पहाड़गढ़ क्षेत्र में एसडीओ, रेंजर से लेकर अन्य मैदानी अमला भरपूर संख्या में है, हर बीट में नियमित गश्त करने के निर्देश हैं, इसके बाद भी जंगल में पेड़ काटे जा रहे हैं, जमीन पर कब्जा कर खेती हो रही है तो गलत है। मैं टीम भेजकर इसकी जांच करवाता हूं। जंगल में अतिक्रमण करने वालों के अलावा लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी।

गुणवत्ता के हिसाब से लगभग पांच हजार प्रति क्विंटल तक में बिकने वाली खैर की लकड़ी की तस्करी के लिए माफिया ने शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर उटीला वृत की सिंहपुर रेंज में जंगल को लगभग खत्म कर दिया है। दो दशक पहले तक यहां मिलने वाले खैर के बड़े पेड़ अब नजर नहीं आते हैं और जंगल में अब सिर्फ ठूंठ ही बचे हैं। स्थिति यह है कि आठ से दस इंच का तना मुश्किल से ही कहीं मिलता है। कत्थे के लालच में खैर की तस्करी करने वालों ने कुछ पैसों के लालच में इस क्षेत्र की पहचान रहा यह जंगल अब लगभग खत्म कर दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के जिन पांच जिलों में खैर के पेड़ सबसे ज्यादा हैं, उनमें ग्वालियर की सिंहपुर रेंज और शिवपुरी जिला शामिल हैं और अगर देश की बात करें तो पूरे देश का 1.70 प्रतिशत खैर सिर्फ मप्र में है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पेड़ों की जो प्रजातियां खतरे में हैं, उनमें खैर को भी शामिल किया है। इसके बावजूद इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वन विभाग के अधिकारी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं और मैदान स्तर पर जिन वनकर्मियों पर सुरक्षा का दारोमदार है, वे भी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को दिए जा रहे लालच ने अब लोगों के मन से डर निकाल दिया है।

खैर की लकड़ी का सबसे ज्यादा अवैध व्यापार ग्वालियर के अलावा प्रदेश की राजधानी भोपाल, छिंदवाड़ा, देवास, सतना और जबलपुर जिलों से हो रहा है। यहां के वन क्षेत्र में निगरानी के बावजूद लगातार लकड़ी की कटाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में करीब 300 टन लकड़ी अभी तक पकड़ी जा चुकी है, फिर भी खैर की तस्करी पर विराम नहीं लग सका है। लॉकडाउन से पहले पकड़े गए खैर के तस्करों से पूछताछ में सामने आया था कि अलग-अलग जिलों से काटी गई चार हजार ट्रक से ज्यादा लकड़ी दूसरे राज्यों में भेजी गई है। एक दशक पूर्व तक शिवपुरी जिले में कत्था बनाने की फैक्ट्री थी। इसके बंद होने के बाद हरियाणा, उप्र, राजस्थान के शहरों में खैर की लकड़ी की मांग है। इनमें पान मसाला बनाने वाली बड़ी कंपनियों के भी शामिल होने की संभावना है। फैक्ट्रियों में वैध से ज्यादा खैर की अवैध लकड़ी पर ज्यादा फोकस रहता है। सामान्य लकड़ियों की आड़ में खैर की लकड़ी को आसानी से परिवहन किया जाता है। लकड़ी काटने के लिए पूरी चेन काम कर रही है। शहरी क्षेत्र में मौजूद व्यापारी लकड़ी के लिए बिचौलिए को पैसे देता है। बिचौलिया स्थानीय बिचौलिए को पैसे देता है। इसके बाद स्थानीय बिचौलिया क्षेत्रीय गरीब लोगों को लकड़ी काटने के लिए उत्साहित करता है।

एक गट्ठर के करीब 120 रुपए पहाड़गढ़ से श्योपुर जिले के सहसराम तक की 52 किलोमीटर लंबी टूलेन सड़क का निर्माण पिछले साल ही पूरा हुआ है। इस सड़क से मानपुर और गूलापुरा की ओर मुड़ते ही दोनों ओर खैर के पेड़ों का घना जंगल दिखता है, लेकिन यह जंगल मृगतृष्णा जैसा ही हो गया है, जो दिखने में घना लगता है, लेकिन सड़क से 400 से 500 मीटर अंदर जाकर देखा तो पेड़ों की जगह कटे हुए ठूंठों का जंगल नजर आ रहा था, कहीं चाटी चलाकर समतल की गई जंगल की जमीन तो कहीं सैकड़ों बीघा में बने खेत, जिनमें सरसों की फसल के अवशेष खड़े नजर आ रहे थे। भूमाफिया जंगल की जमीन के लिए बेशकीमती खैर के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, पेड़ों को जला रहे हैं। गौरतलब है कि पहाड़गढ़ तहसील के मानपुर, रकेरा, गूलापुरा क्षेत्र में घना जंगल था, जिसमें केवल खैर के पेड़ थे, इसीलिए इस क्षेत्र को खैराई के नाम से पहचाना जाता है। भूमाफिया तेजी से इस जंगल को उजाड़ रहे हैं। जहां कभी घना जंगल हुआ करता था, वहां अब खैर के पेड़ों के काटे जाने के बाद हजारों की संख्या में ठूंठ ही ठूंठ नजर आ रहे हैं।

भूमाफिया खैर के जंगल को उजाड़कर उसे खेत बनाने के लिए इतने बेखौफ हैं, कि जहां समतल जंगली जमीन देखी उसकी झाड़ियों से बागड़ कर कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद खैर के पेड़ों की कटाई होती है। पेड़ों को काटकर जंगल में ही जला दिया जाता है, इस कारण जगह-जगह जले हुए पेड़ों की राख के ढेर, अधजले पेड़ नजर आते हैं। जंगल की जमीन पर चाटी चलाकर उसे सपाट करके हजारों बीघा जमीन में खेती हो रही है। बारिश से पहले जंगल को उजाड़ने का काम जोरों पर है। हर महीने 80 से 90 बीघा जमीन पर कब्जा हो रहा है।

मानपुर, रकेरा, गूलापुरा क्षेत्र के खैर के जंगल में बीते डेढ से दो साल में डेढ़ हजार बीघा से ज्यादा का जंगल नष्ट कर उसे खेत बना लिया गया है। जिस जंगल में वन विभाग की तार फेंसिंग व बाउंड्री के पत्थर चोरी हो रहे हैं, उसी जंगल में भूमाफिया जंगल काटकर बनाए गए खेतों की बाउंड्री बड़ी शान से कर रहा है। लगातार उजड़ रहे जंगल को बचाने वन विभाग का भरापूरा अमला है, लेकिन जहां जंगल उजड़ रहा है, वहां महीनों-महीनों रेंजर तो क्या वनरक्षक तक नहीं जा रहे हैं।

● **बृजेश साहू**

व्यापारी काट रहे मौज और भटक रहे किसान

छतरपुर जिले में बनी कृषि उपज मंडी पर व्यापारियों ने कब्जा जमा लिया है। बता दें, यहां सालों पहले बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने किसानों के लिए मंडी का निर्माण करवाया था। लेकिन अब इस मंडी में बने टीनशेड पर व्यापारियों का कब्जा है। कब्जे की वजह से मंडी परिसर में फल-सब्जी का कारोबार कर रहे छोटे व्यापारी भी प्रभावित हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि मंडी परिसर में बने टीनशेड पर बड़े व्यापारियों का कब्जा है। टीनशेड मंडी सचिव के द्वारा बड़े व्यापारियों के नाम स्थान आवंटित कर दिए गए हैं। कई दुकानें आवंटित होने के बाद भी खाली हैं। वहीं, छोटे व्यापारी और किसानों को मंडी में बैठने के लिए भी स्थान नहीं है। फल-सब्जी मंडी परिसर में 67 दुकानों का निर्माण कराया गया था, जिसमें नीलामी प्रक्रिया से 41 दुकानों का आवंटन लाइसेंसी फल-सब्जी व्यापारियों के लिए किया जा चुका है। वहीं, 23 दुकानों का अनुबंध न होने से आवंटन निरस्त कर दिया गया। वहीं, 3 दुकानों पर स्टे चल रहा है। इन दुकानों के आवंटन में लेन-देन करने के भी आरोप लगे हैं।

वहीं, लाइसेंसधारी व्यापारियों का आरोप है कि मंडी में शेष 23 दुकानों का अनुबंध इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि दुकानदारों से अतिरिक्त रुपए मांगे जा रहे हैं। अब तक मंडी प्रबंधन ने इस बात पर गंभीरता नहीं दिखाई। सिर्फ 6 व्यापारी ही अपनी दुकानों से व्यापार कर रहे हैं। दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने की बजाय मंडी अधिकारी परिसर में ही व्यापारियों को स्थाई जगह देने में रूचि दिखा रहे हैं। दुकानदारों ने आरोप लगाए कि जो व्यापारी मंडी सचिव से साठगांठ कर लेता है, उसे अच्छा स्थान आवंटित कर दिया जाता है। मंडी में दुकानों का निर्माण वर्ष 2014-15 में कराया गया। लेकिन 26 दुकानों के अनुबंध न होने की वजह से यह आज भी बंद पड़ी हैं। दुकानों का अनुबंध न होने से वर्ष 2022 में भारसाधक अधिकारी मंडी समिति के निर्देशन पर 26 दुकानों को सील कर दिया गया। प्रांगण में बनी दुकान क्रमांक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 60, 61, 62, 63, 64, 65 की अभी भी विक्रय प्रक्रिया नहीं हो पाई। ऐसे में व्यापारी मंडी परिसर से ही अपना व्यापार कर रहे हैं। यदि कुछ दिन और इन दुकानों को व्यापारियों को विक्रय नहीं किया जाता है तो धीरे-धीरे यह जर्जर हालत में पहुंच जाएंगी।

फल-सब्जी मंडी के बड़े व्यापारी अपनी दुकानों से व्यापार करने की बजाय टीनशेड से पूरा व्यापार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने एरिया में लोहे की जाली लगाकर बंद कर रखा है। इस तरीके से तीन टीनशेड में 48 स्थानों पर कब्जे किए गए हैं। इस संबंध में रामगढ़ के किसान रवि साहू और विकास शिवहरे का कहना है कि जिन व्यापारियों के कब्जे हैं, उनसे मंडी समिति द्वारा अवैध तरीके से राशि की वसूली की जाती है। जिससे वह धड़ल्ले से अपना व्यापार टीनशेड से कर रहे हैं। साथ ही मंडी समिति द्वारा राशि वसूलने की वजह से वह कब्जे हटाने से पीछे हट रहे हैं। छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने इस मामले में कहा कि मंडी परिषद में हुए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। साथ ही छोटे व्यापारियों और किसानों को स्थान मिलेगा। वहीं, जिन व्यापारियों के नाम दुकानें आवंटित हैं, उन्हें दुकानों का कब्जा दिलाया जाएगा।

वहीं जिला मुख्यालय में कृषि उपज मंडी की समस्याओं के कारण किसानों का मोहभंग हो रहा है। व्यापारी और किसान समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं। विभिन्न स्तरों में शिकायत की गई फिर भी व्यवस्थाएं नहीं सुधरीं। स्थानीय कृषि उपज मंडी के व्यापारियों का कहना है कि आवारा जानवरों के कारण किसान मंडी में अनाज बेचने नहीं आ रहे। गल्ला व्यापारी अंकित अग्रवाल का कहना है कि आवारा जानवर किसानों की अनाज से भरी बोरियां काटकर अनाज खाने लगते हैं। यदि किसान किसी कार्य से दाएं-बाएं हो जाता है तो उसके अनाज पर आवारा जानवर टूट पड़ते हैं। मंडी में पानी की भी विकराल समस्या बनी है इसलिए किसान और व्यापारी बेहद परेशान हैं। लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं है। शाम 7 बजे अंधेरा होने लगता है। यदि कोई किसान अपनी फसल की तौल के लिए मंडी में रात गुजारता है तो उसे पानी, अंधेरा सहित अन्य अव्यवस्थाओं से जूझना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं के बारे में एक अन्य व्यापारी भोले पिपरसानियां व अमित अग्रवाल ने प्रशासन का ध्यान खींचा है। अमित कहते हैं कि आवारा बैल आपस में लड़-झगड़कर व्यापारियों और किसानों को चोटिल कर देते हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा फसल को भी नुकसान पहुंचाया जाता है। व्यापारियों का कहना है कि सचिव को लिखित शिकायत देने के साथ ही मुख्यमंत्री शिकायत निवारण 181 में भी शिकायत दर्ज कराई मगर कोई कारगर हल नहीं निकल सका है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कृषि विभाग में भी गड़बड़ी

5 साल पहले जनहित याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश से बुंदेलखंड पैकेज के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कराए गए कार्यों की जांच हुई है। मुख्य तकनीकी परीक्षक मप्र द्वारा की गई जांच में बुंदेलखंड पैकेज में हुए कार्यों में अनियमितताएं पाई गईं। बुंदेलखंड के लिए विशेष पैकज से मप्र के 6 जिलों को 3860 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। जिनमें से मप्र शासन द्वारा 2801 करोड़ 2 लाख खर्च किए गए। छतरपुर जिले में पहले चरण के काम में 918.22 करोड़ रुपए खर्च हुए। जांच बुंदेलखंड पैकेज से कराए गए 6 जिलों में कार्यों की रेंडम आधार पर की गई है। जिसमें भारी अनियमितता मिली, लेकिन कार्रवाई के प्रस्ताव के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कृषि विभाग को बुंदेलखंड पैकेज से 614.36 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसमें वेयर हाउस, मंडी निर्माण, उद्यानिकी, डीजल पंप वितरण, आदि कार्य कराए जाने थे। उक्त संबंध में मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा आंशिक जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि नौगांव में कार्यालय भवन, मैनेजर आवास गृह, चौकीदार भवन, वाटर पोर्श और बड़ामलहरा में कैंटीन, कृषक सूचना केंद्र, पंप हाउस का हस्तांतरण नहीं किए जाने से संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो रही हैं। इसके अलावा छतरपुर जिले में माइको एरीगेशन योजना में बांटे गए स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सेट की कुल संख्या 1059 के विरूद्ध दो चरणों में किए गए सत्यापन में 339 हितग्राहियों का मौके पर भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कुल 101 कृषकों को कम सामान प्राप्त होना तथा 40 कृषकों को बिल्कुल भी सामान प्राप्त नहीं होना पाया गया। कलेक्टर द्वारा की गई जांच विवरण के आधार पर उप समिति द्वारा किए गए आंकलन में छतरपुर जिले के अंतर्गत हेराफेरी की संभावित राशि 65.24 लाख रुपए है।

नई महामारी बना कोचिंग कल्चर...!

देश में कोचिंग कल्चर नई महामारी बनकर उभरा है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी शहरी तबका, हर जगह कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है। कभी न पूरे होने वाले ख्वाब बेच रही कोचिंग इंडस्ट्री मौत के कुएं में देश का भविष्य गढ़ रही है। नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में घुसा सीवर का पानी भारत में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अभाव के कारण दांव पर लगती जिंदगियों की दर्दनाक कहानी है।

● राजेंद्र आगाल

देश में बेरोजगारी चरम पर है, सरकारी नौकरियों का टोटा है, फिर भी नौकरी के लिए तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटरों की भरमार है। देश में महंगाई भले ही आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन अभिभावक और अभ्यार्थी नौकरी के नाम पर हर साल लाखों रुपए कोचिंग इंडस्ट्रीज में खपा रहे हैं। यानि देश में कोचिंग कल्चर नई महामारी बनकर उभरा है। यह महामारी ऐसी है कि नर्सरी से लेकर यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग के नहीं हो रही है। देश में बढ़ते कोचिंग कल्चर को देखते हुए रोज नए-नए कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं। इस कारण शहरों में कोचिंग चलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। मौके की नजाकत को देखते हुए कोचिंग संचालक कहीं बेसमेंट में, तो कहीं बहुमंजिली इमारतों के ऊपर बड़े-बड़े शेड बनाकर अभ्यार्थियों को ज्ञान की घूंटी पिला रहे हैं। बिना सुरक्षा मापदंडों के चल रहे ये कोचिंग संस्थान आए दिन जान ले रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सामने आ चुका है।

नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर में घुसा सीवर का पानी भारत में भ्रष्टाचार और जवाबदेही के अभाव के कारण दांव पर लगती जिंदगियों की दर्दनाक कहानी है। देश की सबसे ऊंची प्रशासनिक सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए चलने वाले सबसे महंगे कोचिंग सेंटर्स में बिना इजाजत के बेसमेंट में लाइब्रेरीज चलाई जा रही हों और शिकायत करने के बाद पास में जाम पड़े सीवर का कोई हल ना निकाला जाए, तो उसका यही मतलब समझा जाएगा कि इस घटना में गई तीन जानों के लिए स्थानीय प्रशासन, कोचिंग का व्यापार करने वाले कारोबारी और सबसे ऊपर देश की सरकार जिम्मेदार है। घटना का शिकार आईएएस की कोचिंग करने आए छात्र बने, जो अपेक्षाकृत समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं, संभवत: इसलिए ये मामला मीडिया और राजनीतिक हलकों में बड़ा मुद्दा बन पाया। वरना, अपने देश में इंसान की जिंदगी इतनी मूल्यवान नहीं समझी जाती कि उस पर उपरोक्त समूह अपना इतना वक्त जाया करें!

बिना ज्यादा बारिश हुए बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में घुसे पानी का बहाव इतना तेज था कि तीन छात्रों की मौत हो गई। कई दूसरे छात्रों को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के गोताखोरों ने बाहर निकाला। एक छात्र ने मीडिया के सामने आकर कहा है कि उसने महीनेभर पहले गैर-कानूनी ढंग से बेसमेंट लाइब्रेरी चलाए जाने की शिकायत ऑनलाइन माध्यम से दर्ज कराई थी। कई अन्य लोगों ने बताया है कि वहां सीवर जाम होने की समस्या कई दिनों से थी, जिसकी सूचना दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को थी। मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्यों? कोचिंग संस्थान पैसे वाले लोग चलाते हैं। उनका पैसे वाले लोगों और राजनेताओं के साथ उठना-बैठना होता है। इसलिए नियम-कायदों को ताक पर रखकर वे मनमानी करते रहते हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुई बिल्डिंग ऐसी अकेली नहीं है, जहां इस तरह की आपराधिक लापरवाही बरती जा रही हो। हादसे के बाद उस इलाके में सैकड़ों छात्र इसीलिए आक्रोश में विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हुए, जिन्हें पुलिस अपने अंदाज में घसीटकर ले गई। और इसके साथ ही घटना के बाद की खानापूर्ति शुरू हो गई है।

मप्र में 520 करोड़ का धंधा

भारत में छोटी से बड़ी परीक्षाओं में नकल और उनके पेपर लीक के मामले समय-समय पर सामने आते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगातार बड़ी-बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के रिकॉर्ड टूटने से विद्यार्थी परेशान होकर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। मप्र में इस संदर्भ में पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि देशभर में परीक्षा माफिया का जाल फैला हुआ है। पेपर लीक से लेकर परीक्षा पास कराने तक के लिए दलाल सक्रिय हैं। ये दलाल कोचिंग संस्थानों के लिए काम करते हैं। दलालों का दावा है कि उनके दम पर ही कोचिंग का धंधा फल-फूल रहा है। एक अनुमान के अनुसार, मप्र में कोचिंग का करीब 520 करोड़ का धंधा है। आपको जानकार आश्चर्य होगा कि मप्र तेजी से एजुकेशन हब बनता जा रहा है। उप्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के छात्र यहां आकर इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या अन्य विषयों में उच्च शिक्षा लेकर देशी-विदेशी संस्थानों और सरकारी नौकरियों में बड़े ओहदे पर जा रहे हैं। दरअसल, मप्र देशभर के कोचिंग संस्थानों के लिए कमाई का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। आलम यह है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में तो जितने स्कूल और कॉलेज नहीं है उससे ज्यादा यहां कोचिंग संस्थान हैं। मप्र में कोचिंग का धंधा कितना फायदेमंद है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां के किसी भी कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाना भी अपने आप में बड़ी सफलता है। अर्थव्यवस्था का तेज रफ्तार से विकास, भू-मंडलीकरण के चलते भारत में तेजी से बढ़ा विदेशी निवेश और मध्यवर्ग की आय में हुई बढ़ोत्तरी ने देश में शिक्षा के प्रति गंभीर रूझान पैदा किया है। इसकी स्वाभाविक वजह भी है, देश के लगभग सभी क्षेत्रों में पेशेवरों की मांग में नाटकीय बढ़ोत्तरी हुई है।

कानून तो अंधा है!

राव आईएएस कोचिंग सेंटर की घटना में 3 युवाओं की मौत के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स चल रहे हैं। सबसे अधिक जो मीम्स ट्रेंड हुआ है वह है- गंदा है पर धंधा है और जो कानून है वो अंधा है! कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सीवर का पानी घुस जाने से चार घंटे से अधिक समय तक फंसे रहने से तीन छात्रों की मौत हो गई। मृतक छात्रों की पहचान तानिया सोनी, श्रेया यादव (दोनों की उम्र 25 वर्ष) और नवीन डेल्विन (28) के रूप में की गई है। तानिया तेलंगाना और श्रेया उप्र की थीं, जबकि नवीन केरल के निवासी थे। वे सभी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जिस राव कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ वह बेसमेंट में अवैध रूप से लाइब्रेरी चला रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी, या यूं कह सकते हैं कि इसे देखकर हर जिम्मेदार अनजान बन गया।

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या मप्र की राजधानी भोपाल या व्यावसायिक राजधानी इंदौर, हर जगह कोचिंग इंडस्ट्री ऐसी ही अव्यवस्थाओं के बीच चल रही है। खासकर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर तो बड़े-बड़े दावों के साथ युवाओं को सपने दिखाकर उनका शोषण कर रहे हैं। वर्तमान में यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री एक ऐसी मशीन में तब्दील हो गई है, कि हर शहर के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोचिंग संस्थान की मार्केटिंग टीम के लोग देखे जा सकते हैं। भारत के तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए की यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री है। जिसे आज कॉर्पोरेट की तरह चलाया जाता है। फीस की लड़ाई, टैलेंट की खोज, सेलिब्रिटी-फैकल्टी एंडोर्स की तलाश और आक्रामक मार्केटिंग और पीआर- यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में प्रसिद्ध कोला युद्धों की सभी सामग्रियां हैं। यह इतना बड़ा हो गया है

कभी न छूटने वाली लत

यूपीएससी चक्र व्यसनी है। पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में एक साल का समय लगता है। अधिकांश लोग यह सोचकर यहां आते हैं कि उन्हें मुखर्जी नगर की गलियों में कई साल नहीं बिताने पड़ेंगे, लेकिन आशा और कोशिशों की थकावट को लेकर निरंतर सावधानी उन्हें लंबे समय तक शिकार में बनाए रखती है, समय इतना लंबा कि कई लोग अपना पूरा एक दशक गंवा देते हैं। हर साल लाखों लोग हारकर और कम आत्मसम्मान के साथ इस चक्र से बाहर निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग खुद को संभालते हैं और शिक्षण और सामाजिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी तैयारी के अनुभव का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, जिनके पास अभी भी ऊर्जा बची है वे राज्य सेवाओं का ऑप्शन चुनते हैं। कई छात्रों ने अपनी जिंदगी के 8-10 साल यूपीएससी की तैयारी में बिताए और इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन वो इसे क्लियर नहीं कर सके। इसके बाद वे स्टेट सर्विस की ओर रुख करते हैं या कोई अन्य सर्विस चुनते हैं। वहीं कई छात्र अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कई छात्रों ने यहां सालों बिताए और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अपने अंतिम प्रयास में असफल होने के बाद, उन्हें अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा, जहां वे अभी भी नौकरी के अवसरों की तलाश में हैं। कई छात्र तो खुद को इससे बाहर निकालने के लिए डिप्रेशन की गोलियां भी लेते हैं।

कि अब यह हताश युवाओं को कभी न पूरे होने वाले ख्वाब की तरह दिखने लगा है और सरकार भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी है।

संस्थानों के लिए जलग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है। प्रतिष्ठित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या पिछले एक दशक में दोगुनी हो गई है। 2012 में यह संख्या 5 लाख से बढ़कर 2022 में 11 लाख से अधिक हो गई है। इसमें राज्य सेवा परीक्षाओं को भी जोड़ दें तो बाजार समुद्र जितना बड़ा हो गया है। जो बात यूपीएससी की कोशिशों को किसी जुए से कम नहीं बनाती, वो यह है कि पदों की संख्या पिछले कुछ साल से लगभग स्थिर बनी हुई है। 2022 में 1,022 पद थे, जो 2012 में 1,091 से कम हैं। इस प्रकार के अनुपात के साथ, यह लगभग राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने जैसा है जहां केवल 11 खिलाड़ी ही भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जगह बनाते हैं। विफलता यहां अपवाद नहीं बल्कि एक नियम है। यह कड़ी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाली कमजोरी है जिसका कुछ संस्थानों द्वारा फायदा उठाया जा रहा है। पिछले साल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने लगभग 20 कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन के बारे में नोटिस भेजा था। इसके बाद डीओपीटी ने कहा था कि चयनित उम्मीदवार कोचिंग संस्थानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्रालय ने उद्योग के लिए नियम भी जारी किए हैं। पिछले 20 साल में एक चक्करदार उछाल देखा गया है, या जिसे कुछ लोग एक अस्थिर बुलबुला कह सकते हैं। यह एक विशाल इंडस्ट्री में परिवर्तित होने लगा है। शिक्षक-उन्मुख से लेकर राजस्व-उन्मुख तक, संस्थानों में कई नए कार्यक्षेत्र सामने आए हैं और शिक्षक अब गुमनाम नहीं रहे।

एक स्टार लाइनअप है

अवध ओझा, विकास दिव्यकीर्ति, खान सर, हालांकि, लिस्ट लंबी है और संस्थान आधुनिक शैली की कॉर्पोरेट मशीनों में तब्दील हो गए हैं। उनके पास लक्ष्य, लंबे समय तक काम करने के घंटे और विविध टीमें हैं जो कोचिंग व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं को देखती हैं। मार्केटिंग टीमें विज्ञापनों को देखती हैं, ग्राफिक्स टीमें वीडियो के लिए ग्राफिक्स तैयार करती हैं जो कोर्स कंटेंट और सोशल मीडिया पोस्ट में जाते हैं। कुछ के पास पीआर टीमें भी हैं जो उन्हें अपने ब्रांड को

कोटा अब स्टूडेंट्स के लिए नहीं रहा फैक्ट्री!

देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की कोचिंग करवाने के लिए नामचीन शहर कोटा में इस साल कोचिंग स्टूडेंट्स की जगह पर आर्थिक संकट आने लगा है। साल 2024 में अब तक करीब 1.20 लाख ही स्टूडेंट्स कोटा में कोचिंग करने आए, जो पिछले सालों की अपेक्षा आधे हैं। ऐसे में शहर की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि यहां से शुरू हुए कोचिंग संस्थानों ने अपनी कोचिंग की ब्रांचें अलग-अलग राज्य में खोल दीं, जैसे उप्र, बिहार से जो बच्चे आते थे उन स्टूडेंट्स का कोटा में आना कम हो गया है। हॉस्टल के लीज होल्डर देवेश त्रिपाठी का कहना है कि कोटा में स्टूडेंट्स कम आने की वजह से सबसे बड़ा असर हॉस्टल इंडस्ट्रीज पर पड़ा है। हॉस्टल के कमरे खाली हैं, खर्चे तक नहीं निकाल पाए रहे हैं। नया कोचिंग हब कोरल पार्क में हालात बिगड़ने लगे हैं, जिन हॉस्टल में स्टूडेंट आए हैं, उनके किराए में भारी गिरावट आई है, जो रूम 18 हजार या 20 हजार रुपए का मिलता था। वह रूम आज 4 से 5 हजार रुपए में मिल रहा है। कई हॉस्टल वाले अपने हॉस्टल को चलाने के लिए रूम के साथ स्टूडेंट्स को खाना भी दे रहे हैं। लोगों के रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। दुकानों पर ग्राहकी कम होने लगी हैं। कोचिंग एरिया में लोगों ने अपने काम धंधे बंद कर दिए हैं। कोचिंग संस्थानों में स्टाफ की सैलरी में कटौती हुई हैं। कुछ कोचिंग संस्थानों ने स्टाफ को जॉब से तक हटा दिया है। कोचिंग सिटी के बाजार छात्रों से गुलजार रहते थे। आज हालात उल्टे हैं। उम्मीद के मुताबिक स्टूडेंट्स के नहीं आने से दुकानों पर भीड़ खत्म हो गई। कई ऐसी दुकानें हैं जिन पर ताले तक लटक गए। कुछ कोचिंग संस्थानों में तो स्टाफ को घर भेज दिया है। इंडस्ट्रीयल एरिया स्थित एक कोचिंग संस्थान में करीब 250 के आसपास लोगों की छुट्टी कर दी गई है। इसमें बैक स्टाफ से लेकर हाउसकीपिंग और मेंटेनेंस का स्टाफ शामिल है। कुछ फैकेल्टी को भी घर भेजा है। एक अन्य कोचिंग संस्थान में 10 से 30 परसेंट तक सैलरी में कमी की है। मेस चलाने वाले हेमराज का कहना है कि उनके आसपास की कई मेस बंद हो गईं। उनकी मेस में 250 स्टूडेंट्स थे। साल 2022 में स्टूडेंट्स बढ़ने पर उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी थी, लेकिन इस साल 60 से 70 स्टूडेंट्स मेस में खाना खाने पहुंच रहे हैं। स्टाफ भी हटाना पड़ा है। एक अन्य मेस संचालक बलबीर कहते हैं कि उनके अलग-अलग आउटलेट पर 2800 स्टूडेंट्स खाना खाते थे, अब यह संख्या आधी रह गई, इसका असर यह हुआ है कि हमने स्टाफ कम कर दिया।

बढ़ावा देने में मदद करती हैं। कोचिंग इंडस्ट्री काफी समय तक सरकार की नजरों से दूर थी, लेकिन जब सरकार ने देखा कि इंडस्ट्री को कुछ नियम-कायदों की जरूरत है तो उसने एक एडवाइजरी जारी की। कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजने से लेकर गाइडलाइन जारी करने तक ये संस्थान अब सरकार के रडार पर आ गए हैं। लगभग दो दशक पहले, सरकार ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा के नियमों में बदलाव किया था, जिसमें स्कूली कोर्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रयासों की संख्या दो तक सीमित कर दी गई थी। इसका उद्देश्य कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करना भी था। योजना स्पष्ट रूप से काम नहीं आई, चाहे वो आईआईटी कोचिंग हो या यूपीएससी, क्योंकि वो उन पर नियंत्रण नहीं रख सके, अब उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं। यूपीएससी कोचिंग बाजार ज्वालामुखी बन रहा है क्योंकि यह आशाजनक है, यह बायजूस जैसे एड-टेक प्लेटफॉर्म के विपरीत नहीं है जिसने हाल के वर्षों में बाजार में केवल भीड़ बढ़ाई है। कोचिंग इंडस्ट्री के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, सरकार ने देखा है कि इस इंडस्ट्री के पास पैसा है। क्रिप्टो और जुआ ऐप्स की तरह, सरकार इसके बारे में भी कुछ करेगी।

मोटा पैसा, आईएएस फैकल्टी

यूपीएससी कोचिंग संस्थानों के पूरे पेज के अखबारी विज्ञापनों पर एक नजर बड़े पैसे, बड़े सितारों और बड़े सपनों की ओर इशारा करती है। अखबारों के विज्ञापन, होर्डिंग्स पर अव्वल तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट, कोचिंग संस्थान विज्ञापनों में बहुत अधिक निवेश करते हैं। वे उन लोगों को चौंका देने वाली मोटी रकम देते हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है या जो नौकरशाह के रूप में रिटायर्ड हो चुके हैं। एक आईएएस अधिकारी, जिन्होंने अपनी तैयारी के दिनों में कोचिंग भी ली थी, नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं, मुझे हर हफ्ते एक घंटे तक चलने वाले दो मेंटरशिप सत्र लेने के लिए प्रति माह 2 लाख रुपए की पेशकश की गई थी। और स्टार शिक्षकों को दी जाने वाली प्रीमियम सैलरी करोड़ों में है, जहां तक रिटायर्ड नौकरशाहों का सवाल है, ऐसे केंद्रों पर कई लोगों की मांग काफी अधिक रहती है। नौकरशाही अक्सर नौकरशाहों के लिए नौकरियां पैदा करती है, शिक्षा उद्योग उनके लिए एक नया मौका है। एक रिटायर्ड अधिकारी का कहना है कि विज्ञापनों में आपकी तस्वीर और छात्र को आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के लिए ही आपको लाखों रुपए की पेशकश की जा रही है। लेकिन यह हमेशा प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ नहीं होता है जो प्राप्त होता है।

कोचिंग इंडस्ट्री के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वे विभिन्न प्रकार के सौदे करते हैं, कभी-कभी संस्थान उनकी सेवाओं और जिस ब्रांड छवि का लाभ उठाते हैं, उसके बदले में उनकी (नौकरशाहों की) किताबें खरीदते हैं। शिक्षक, टॉपर्स और रिटायर्ड अधिकारी कोचिंग जगत के चमकदार पहलू हैं। इस चमक के पीछे सपनों का रोज मरना, गलाकाट प्रतिस्पर्धा, शिकारी मूल्य निर्धारण और आक्रामक मार्केटिंग की रणनीतियां हैं जो नए ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। जैसे ही बड़े मेट्रो बाजार फैलने लगे और कोविड-19 ने घर से पढ़ने के कल्चर की शुरुआत की, कोचिंग संस्थान ऑनलाइन मोड के जरिए से इस अप्रयुक्त बाजार पर कब्जा करने के लिए तैयार हो गए हैं। वे किफायती शुल्क संरचना का वादा करते हैं। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन कोचिंग का महत्व बढ़ गया है और ऑनलाइन कोचिंग मॉडल के साथ ये संस्थान किफायती शुल्क ढांचे के साथ देश के छोटे शहरों तक पहुंच गए हैं, लेकिन ये संस्थान केवल राजस्व और निवेश पर टिके रहते हैं। वायरस ने दुनिया को रोक दिया, लेकिन यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री को नहीं। अभ्यर्थी अध्ययन सामग्री और शिक्षकों को खोजने के लिए इंटरनेट के हर कोने को देख रहे थे। उन्होंने कोचिंग केंद्रों को छोड़ दिया था, लेकिन अपने सपने को नहीं। चूंकि, ऑनलाइन कक्षाओं के मॉडल ने मुनाफा कमाया, इसलिए संस्थानों ने यह सुनिश्चित किया कि वे उम्मीदवारों से जितना संभव हो उतना लाभ कमा सकें।

कोचिंग के भरोसे पढ़ाई

सिर्फ ज्यादातर मध्यवर्गीय परिवार के शिक्षा के प्रति बढ़े रूझान और अवसरों को हासिल करने की ललक का ही परिणाम नहीं है कोचिंग का भारी-भरकम कारोबार, बल्कि इसके पीछे कुछ आधारभूत अधिसंरचनात्मक कमियां भी हैं। यही नहीं, पिछले कुछ सालों से बोर्ड की परीक्षाओं में पास होने के लिए भी मां-बाप के साथ-साथ बच्चे भी गंभीर हो रहे हैं। इन सब वजहों से देश में बड़ी तादाद में शिक्षकों की जरूरत बढ़ी है,

माता-पिता की उम्मीदों का भार

आजकल के मां-बाप अपने बच्चों से ज्यादा प्रतिस्पर्धी हैं। वह बच्चों को कोचिंग क्लास जाने पर जोर दे रहे हैं क्योंकि वे खुद स्कूल के काम में बच्चों की मदद कर पाने में असमर्थ हैं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि बच्चे अपने माता-पिता की आशाओं और सपनों को ढोने के लिए नहीं बने हैं और न ही उन्हें बनना चाहिए। मनोवैज्ञानिक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि सामाजिक प्रतिष्ठा, माता-पिता की चिंताएं और हताशा शिक्षा को एक निराशाजनक प्रतिस्पर्धा में बदल रही है। इसके गंभीर परिणाम सामने आए हैं। बच्चों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से बड़े होने पर उनके आत्मसम्मान में कमी आ सकती है। कुछ इसी तरह की चिंता फ्लेम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गोयल ने बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर की। उन्होंने कहा कि बच्चे उन घंटों का इस्तेमाल अपने आपको योग्य बनाने में कर सकते हैं। एग्जाम याद करने की क्षमता का टेस्ट है। वे छात्रों का मूल्यांकन करते हैं, उनका आंकलन नहीं करते हैं। छात्र पढ़ाई के बोझ तले दबे हुए हैं। इससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। नई दिल्ली के मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले पंद्रह साल के रक्षित बल्हारा को याद नहीं कि उसने आखिरी बार फुटबॉल कब खेला था। उन्होंने कहा कि मैं अपना खाली समय सोशल मीडिया पर बिताता हूं क्योंकि इसके लिए मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। शहर के संस्कृति स्कूल की 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने आकाश इंस्टीट्यूट से तब पढ़ाई छोड़ दी जब वह 10वीं कक्षा में थी। छात्रा का कहना है कि वहां मेरे ऊपर पढ़ाई का काफी दबाव था। मेरे पास इंस्टीट्यूट छोड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा। रोजाना पढ़ाई के घंटे बेहद थकाने वाले थे। उन्होंने बाद में एक ग्रुप ट्यूशन ज्वाइन कर लिया।

जिसकी भरपाई ये कोचिंग सेंटर कर रहे हैं। और भी कई वजहें हैं कोचिंग केंद्रों के तेजी से एक व्यवस्थित कारोबार में तब्दील होने की। दरअसल संचार सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के बेहतर होने की वजह से अब पढ़ने-लिखने के तमाम गैर-पारंपरिक माध्यम भी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे- डिस्टेंस लर्निंग तथा ऑनलाइन एजुकेशन। इस कारण भी कोचिंग सेंटर्स की मांग बढ़ी है, क्योंकि बिना फिजिकली क्लास अटेंड किए पढ़ाई के दौरान जो कमियां महसूस होती हैं, उनकी भरपाई ये कोचिंग केंद्र कराने का दावा करते हैं। वैसे कोचिंग सेंटर्स के इस तरह शहर-दर-शहर, कस्बे-दर-कस्बे फैलने के पीछे हमारी शिक्षा व्यवस्था में कुछ नीतिगत खामियां हैं। मप्र के एक वरिष्ठ आईएएस कहते हैं कि 70 के दशक तक देश में कोचिंग सेंटर नहीं हुआ करते थे या यूं कहें कि इस तरह कोचिंग सेंटर्स का देश में जाल नहीं फैला था। व्यक्तिगत रूप से ही ट्यूशन पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक या अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कमजोर आय वर्ग के छात्रों का ही यह पेशा हुआ करता था। लेकिन जब देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला पाने वालों की तादाद वहां उपलब्ध सीटों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ गई, तो दाखिला नीति में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और परीक्षाओं के जरिए दाखिला मिलने लगे, जबकि इसके पहले तक महज मेरिट के आधार पर छात्रों को मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन मिल जाते थे।

कोचिंग लघु उद्योग बना

मप्र के कई शहरों ने अपने आपको करियर लांचर के रूप में स्थापित किया है। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर भी पूरी तैयारी के साथ शामिल हो गए हैं। इंदौर में तो यह एक लघु उद्योग ही है। इंदौर में लगभग 250 से ज्यादा देश के विभिन्न हिस्सों के कोचिंग सेंटर्स की शाखाएं और यहां के निजी कोचिंग केंद्र हैं। यहां मप्र ही नहीं देश के विभिन्न शहरों के छात्र विभिन्न स्तरों की पढ़ाई व विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यहां कोचिंग केंद्रों के चलते हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला हुआ है। लेकिन खेद की बात है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां के छात्रों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। हालांकि देश के बड़े कोचिंग सेंटर्स के रूप में अभी भी दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये इतने बड़े शहर हैं और यहां इतने बड़े और विविधता वाले उद्योग हैं कि उन सबके बीच कोचिंग एक प्रमुख उद्योग के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाता। जबकि हकीकत यही है कि देश के कोचिंग कारोबार की राजधानी दिल्ली ही है। क्वालिटी के लिहाज से भी और क्वांटिटी के लिहाज से भी।

हर जगह दिल्ली जैसे हालात!

दिल्ली में कोचिंग सेंटर में हादसे ने देशभर में चल रहे कोचिंग सेंटर्स में बरती जा रही लापरवाही को लेकर आंखें खोल दी हैं। दिल्ली जैसे ही हालात विभिन्न शहरों में हैं। कहीं बेसमेंट में क्लासेज चल रही हैं, तो कहीं पार्किंग बना रखी है। हालत यह है कि बेसमेंट में हमेशा छात्र-छात्राओं की मौजूदगी रहती है। ऐसे में दिल्ली जैसे हादसे किसी भी शहर में हो सकते हैं। मप्र की राजधानी भोपाल के एमपी नगर में बने कोचिंग परिसरों की हालत भी दिल्ली के कोचिंग सेंटरों से अलग नहीं है। एमपी नगर जोन-2 क्षेत्र में भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित व्यावसायिक परिसर में कोचिंग सेंटर चल रहे हैं। यहां बेसमेंट में पार्किंग है। ऐसे में छात्र-छात्राओं की भीड़ लगी रहती है। हाल ही में निरीक्षण के दौरान फायर एनओसी और आपदा की स्थिति मे डैमेज कंट्रोल के इंतजाम नहीं थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कई कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहे हैं। गोपालपुरा बाइपास और आसपास की कॉलोनियों में ही इनकी संख्या 50 के आसपास है। महेश नगर में कुछ लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही हैं। यहां दिनभर छात्र-छात्राओं की आवाजाही रहती है। हालात यह है कि प्रताप नगर में कोचिंग हब बनकर तैयार है लेकिन वहां जाने को कोई तैयार नहीं है। जेडीए प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि जल्द ही संबंधित विभागों से समन्वय कर टीम भेजकर मौका निरीक्षण करवाएंगे। वहीं कोटा के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राकेश व्यास ने बताया कि कोचिंग एरिया में जलभराव की कोई शिकायत नहीं है। दिल्ली हादसे के बाद यहां भी जलभराव की स्थिति में इंतजामों की समीक्षा करेंगे। जलभराव की स्थिति होने पर बच्चों को कैसे सुरक्षित निकाला जा सकता है, क्या बंदोबस्त है, इसकी जांच करेंगे।

जिस तरह से दिनोंदिन कोचिंग का यह कारोबार भारी-भरकम आकार ग्रहण करता जा रहा है, उसको देखते हुए बड़े कार्पोरेट खिलाड़ियों का इसकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक ही है। वैसे सत्यम कंप्यूटर्स और एनआईआईटी जैसी बड़ी कार्पोरेट कंपनियां पहले से ही एक क्षेत्र विशेष में मौजूद हैं। अब जो खबर है उसके मुताबिक रिलायंस, विप्रो जैसी कंपनियां भी इस क्षेत्र में एक बड़ी रूपरेखा के साथ कूदने जा रही हैं। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर की ही खबरें हैं, लेकिन इस उद्योग में भविष्य के लिए जो शानदार संभावनाएं दिख रही हैं, उसके चलते यह तय है कि आज नहीं तो कल कोचिंग कारोबार में बड़े कार्पोरेट खिलाड़ी अवश्य दिखाई देंगे।

आसान नहीं है दाखिला

भले कोचिंग केंद्र पैसा कमाने का जरिया हों, भले यह सपना दिखाकर अच्छी-खासी कमाई कर रहे हों, लेकिन यह भी तय है कि प्रतिष्ठित कोचिंग केंद्रों में हर किसी का दाखिला आसान नहीं है। दिल्ली, कोटा यहां तक कि इंदौर और भोपाल में भी कई प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर हैं, जहां हर छात्र एडमिशन पाना चाहता है, भले ही इनकी फीस दूसरे सेंटर्स के मुकाबले दोगुनी ही क्यों न हो। लेकिन ये सेंटर सभी छात्रों को एडमिशन नहीं दे पाते। एक तो व्यवस्थागत मजबूरी है और दूसरी बात साख का भी सवाल है। ये प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटर अपने यहां अच्छे छात्रों को ही एडमिशन देते हैं ताकि वे सफल हों और इससे इन केंद्रों की प्रसिद्धि भी बरकरार रहे। इसके लिए ये कोचिंग सेंटर प्रवेश हेतु एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसमें सफल छात्रों को ही एडमिशन देते हैं। कोचिंग संचालकों का कहना है कि कोचिंग केंद्रों की फीस अलग-अलग पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं और शहरों पर निर्भर करती है।

मप्र में बनेगा किराएदार एक्ट

प्रदेश में 2047 तक 50 प्रतिशत शहरीकरण की संभावना

प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास नीरज मंडलोई ने शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शहरीकरण की आवश्यकता पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। शहरी जनसंख्या वर्तमान परिदृश्य में निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 2047 तक 50 प्रतिशत शहरीकरण होने की संभावना है। प्रदेश में निरंतर शहरीकरण हो रहा है। ग्रामीणों के शहरों में आने पर रोजगार, भोजन, आवास, यातायात, जैसी व्यवस्थाओं के लिए तैयारी करनी होगी। सड़क, बिजली, पानी, जल-मल निकासी पर भी कार्य करना होगा। मंत्री ने कहा कि कई ठेकेदार बहुत कम रेट पर ठेके ले लेते हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके लिए एक कमेटी बनाने को कहा गया है, जो यह तय करेगी कि काम का वर्केबल रेट क्या है। इससे कम रेट में टेंडर लेने पर उस टेंडर का रद्द कर दिया जाएगा। इससे काम की गुणवत्ता भी प्रभावित ना हो। नगर निगम में बसों के संचालन के घाटे से निकालने के लिए प्रोफेशनल लोगों को हायर करने को कहा गया है। साथ ही कुत्तों के बंध्याकरण को लेकर भी निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने को कहा गया है।

मप्र में डेवलप हो रहीं अवैध कॉलोनियों को रोकने में नगर निगम आयुक्तों और महापौरों ने असमर्थता जताई है। उनका कहना है कि ऐसे कोई कठोर नियम नहीं हैं, जिससे अवैध कॉलोनी बनाने वाले को सख्त सजा दी जा सके। इसको लेकर कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है। इस पर नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रमुख सचिव को अवैध कॉलोनी रोकने सख्त नियम बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने किराएदारी का नया एक्ट बनाने के लिए भी निर्देश दिए हैं ताकि कोई किराएदार प्रापर्टी पर कब्जा न कर सके।

नगर निगम के महापौर और निगमायुक्तों की बैठक के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा- त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शहर सरकार सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए नगर निगम, नगरपालिका सबसे महत्वपूर्ण लेयर हैं। 16 नगर निगम के महापौर से बात हुई है। इसमें फ्री-होल्ड का मसला उठा है जिसके नियम बने हैं, लेकिन उसमें काम नहीं होता है। इस कारण शहर का विकास रुका हुआ है। प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि कमिश्नर के साथ बैठकर नगर निगम को फ्री-होल्ड करने के अधिकार दें। सभी अटकलों को समाप्त किया जाए। विजयवर्गीय ने कहा कि अवैध कॉलोनी प्लानिंग सिस्टम को खराब कर रही है। ग्रीन एरिया में अवैध कॉलोनी बनाई जाती है। खेल के मैदान में अवैध कॉलोनी बना दी जाती है। ग्रीन एरिया में अवैध कॉलोनी बन जाती है, इसलिए तय किया है कि ग्रीन एरिया में सिर्फ पौधरोपण करें। हमारा टारगेट दो करोड़ का था जिसे हमने बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने साढ़े पांच करोड़ का संदेश दिया है। मास्टर प्लान की ग्रीन लैंड पर पौधरोपण करने के लिए कहा है।

विजयवर्गीय ने कहा कि आवारा डॉग्स को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। इसमें इनके कारण आने वाली दिक्कतों पर चर्चा के लिए पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव को बुलाया था जिस पर उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। कई बार कुत्तों के क्रूर होने की वजह भूखा होना बताया गया है। इसकी रोकथाम के लिए जागरुकता के कार्य करने को कहा है। साथ ही इनका बधियाकरण करने के लिए कहा है। रीवा में अच्छा काम हो रहा है। निजी एजेंसी से यह काम कराया जा रहा है। इसी तर्ज पर अन्य निगमों को भी काम करने के लिए कहा है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के शहरों में जहां मल्टी स्टोरी बन रही है वहां लिफ्ट में लोग फंसते हैं। पर्याप्त फायर सिस्टम की भी कमी होती है। यह निर्देश दिए हैं कि विकास में जनभागीदारी हो। इसके लिए सबको साथ लेकर काम करने के लिए कहा है ताकि क्वालिटी वर्क हो।

मंत्री ने कहा कि बैठक में यह निर्देश दिए गए हैं कि किराएदारी का एक आधुनिक एक्ट बने। पेंशनर्स मकान बनाकर किराए से देते हैं और बाद में किराएदार कब्जा कर लेते हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि प्रॉपर्टी मालिक का हक बना रहे। किराएदार उस पर हक नहीं जमाए। उन्होंने कहा है नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। नगर निगमों के अंतर्गत सबसे अधिक खर्च बिजली में होने का मामला सामने आया है। वाटर सप्लाई के बिल को कम करने के लिए सोलर एनर्जी का अधिकतम उपयोग करने के लिए कहा गया है। सोलर सिस्टम की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी। एसीएस ऊर्जा मनु श्रीवास्तव ने इसको लेकर भी प्रेजेंटेशन दिया है। विजयवर्गीय ने निगमों में नुकसान की स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि बस संचालन में नगर निगम को नुकसान होता है। इसलिए निगम के महापौर और आयुक्त से कहा है कि स्मार्ट अफसर रखें जो स्मार्ट वर्किंग करें। प्रोफेशनल लोगों को हायर करना हो तो हायर करें, सरकार उसकी परमिशन दे देगी। महापौर का काम सिर्फ नाली साफ कराना नहीं है। उनसे क्रिएटिव वर्क करने को कहा है। बैठक में मंत्री ने महापौरों और निगमायुक्तों से कहा कि आप शहर सरकार हैं, अपनी शक्तियां पहचान कर कार्य करें, परंतु निर्णय लोकहित में होने चाहिए। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत अनाधिकृत कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इस पर महापौर की तरफ से सख्त कानून नहीं होने की बात कही गई तो मंत्री ने कहा कि अब सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। साथ ही मंत्री ने किराएदारी एक्ट भी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स मकान बनाकर किराए से देते हैं, उनको किराएदार परेशान करते हैं। इसको लेकर एक्ट बनाएंगे ताकि संपत्ति मालिक का स्वामित्व बना रहे और किराएदार को भी असुविधा ना हो। बैठक में फ्री-होल्ड का मुद्दा भी उठा। इसके नियम बने हैं, लेकिन उसके अनुसार काम नहीं होता। इसके चलते शहर का विकास रुका हुआ है। मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर निगम को फ्री होल्ड करने के अधिकार देने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान के ग्रीन एरिया में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करने के लिए कहा है। इससे अवैध कब्जे भी रुकेंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि बहुमंजिला भवनों के लिफ्ट एवं फायर सेफ्टी सिस्टम नगरीय निकाय द्वारा देखे जाएं। फायर संचालनालय का गठन किया जाएगा, इसके लिए लगभग 400 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

● **कुमार राजेंद्र**

कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं

लोकसभा चुनावों में 99 सीटें जीतकर कांग्रेस ने अपनी दमदारी दिखाई है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि कांग्रेस के पास कई राज्यों में लीडरशिप ही नहीं है। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, लगातार 26 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसी ही स्थिति देश के कई अन्य राज्यों में भी है।

लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भले कांग्रेस को कॉन्फिडेंस दिया हो, लेकिन राज्यों में पार्टी की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। सीनियर लीडर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मप्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बेटे और राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार गए। हरियाणा में पार्टी गुटबाजी में फंस गई है। उप्र, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में पार्टी के पास चुनाव जिताने वाले चेहरे नहीं हैं।

13 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने हिमाचल और उत्तराखंड में दो-दो सीटें जीतीं। फिलहाल राज्यों में कांग्रेस के सामने 3 चुनौतियां हैं। पहली पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है। दूसरा पुरानी लीडरशिप कमजोर होती दिख रही है और तीसरी जहां सीनियर लीडर ज्यादा हैं, वहां गुटबाजी है। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। कांग्रेस की लीडरशिप पहले सोनिया गांधी के आसपास घूमती थी। उनके सलाहकार पार्टी चलाते थे। अब गांधी फैमिली के तीन पावर सेंटर्स हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनकर राहुल की स्थिति और मजबूत हो गई है। राहुल गांधी आने वाले दिनों में किस तरह पार्टी को स्ट्रक्चर करते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है।

मप्र में कांग्रेस पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारी है। लोकसभा चुनाव के बाद हुई मीटिंग में पार्टी ने तय किया है कि सीनियर लीडर्स के साथ युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स से बात की। उन्होंने सीनियर लीडर्स की गुटबाजी को हार की वजह बताया। बैठक में शामिल रहे एक नेता का कहना है कि मीटिंग में सबसे ज्यादा फोकस इसी पर रहा कि कैसे युवाओं को आगे लाया जाए। पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस ने अलग-अलग टीमों में युवाओं को सहप्रभारी बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। मप्र में कांग्रेस के उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया कहते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और सभी सीनियर लीडर्स ने विधायकों से वन-टू-वन बात की है। अब नए लोगों को मौका मिलेगा और पुराने लोगों को भी जोड़ा जाएगा।

राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब भी सियासी तल्खी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 से 8 सीटों पर पहुंची है, लेकिन इस जीत पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट दावा कर रहे हैं। मई, 2024 में 73 साल के हुए अशोक गहलोत रिटायरमेंट के मूड में नहीं हैं। इसलिए राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव के आसार कम हैं। 2023 में गहलोत ने साफ कर दिया था कि उनका रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। गहलोत अब भी उसी स्टैंड पर कायम हैं।

सूत्र बताते हैं कि गहलोत की रणनीति है कि अगर उन्हें चौथी बार लीड करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो उनकी जगह सचिन पायलट को भी मौका न मिले। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पायलट के लिए चुनौती हैं। डोटासरा सियासी तौर पर प्रभावी जाट समुदाय से आते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट रशीद किदवई का कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस की पूरी राजनीति गहलोत और पायलट के बीच ही थी। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जगह बना ली है। कांग्रेस में साफ नजर आता है कि इनमें से कोई भी नेता बड़ी भूमिका में आ सकता है। वहीं, कांग्रेस लीडर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहते हैं कि हमें युवा जोश के साथ अनुभव भी चाहिए। हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में क्लीयर है कि 50 प्रतिशत युवाओं को मौका देंगे और बाकी सीनियर रहेंगे। सीनियर नेताओं के अनुभव के बिना पार्टी नहीं चल सकती।

महाराष्ट्र में नाना पटोले पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही सुधरी है। 2014 में कांग्रेस ने यहां 2 सीटें जीती थीं, 2019 में एक सीट जीती और 2024 में 13 सीटें जीतकर नंबर वन पार्टी बन गई। फिर भी पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक संदीप सोनवलकर का कहना है कि कांग्रेस में अंदरखाने बहुत बिखराव है। पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप खत्म हो चुकी है। पुराने नेताओं में सिर्फ पृथ्वीराज चव्हाण बचे हैं, जो 2014 से साइडलाइन हैं। नाना पटोले सिर्फ विदर्भ के नेता हैं, पूरे महाराष्ट्र में वे अपने दम पर चुनाव नहीं जिता सकते। पार्टी के अंदर ही उनकी नहीं चल रही है। संदीप कहते हैं कि अभी विधान परिषद चुनाव में पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। नाना पटोले भाजपा से आए हैं, यही वजह है कि आज भी पार्टी के कई नेता उन्हें अपना नहीं पाए हैं। अशोक चव्हाण और दूसरे

बिहार, ओडिशा, आंध्रप्रदेश में लीडरशिप का संकट

उप्र के अलावा बिहार, ओडिशा, आंध्रप्रदेश में भी कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार में उप्र के जिन नेताओं को मंत्री बनाया था, वे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इनमें जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह बड़े नाम हैं। बिहार में भी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। सांसदों के मामले में वो बड़ी पार्टियों में 5वें नंबर पर है। आंध्रप्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की बहन शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसी ही कोशिश ओडिशा में भी चल रही है। यहां 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है। उसका संगठन भी नहीं है। जम्मू-कश्मीर, उप्र, बिहार, ओडिशा और आंध्रप्रदेश में न तो फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है और न सेकंड लाइन है। वहां समीकरण के हिसाब से, सहयोगियों के हिसाब से जीत-हार होती रहती है।

हार के कारण राज्यों में बदल रही लीडरशिप

राजनीतिक जानकार रेणु मित्तल कहती हैं कि कुछ राज्यों में कांग्रेस के रीजनल लीडर ताकतवर हो गए थे। वे अपने हिसाब से राज्य चलाते थे। उनकी लीडरशिप में पार्टी लगातार हारी है, इसलिए इन राज्यों में लीडरशिप बदल रही है। कुछ नेता 2024 चुनाव के बाद खत्म हो गए हैं। इनमें एक कमलनाथ हैं और दूसरे अशोक गहलोत। उनकी लीडरशिप में पार्टी कभी नहीं जीती। पार्टी जब भी जीती, उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पार्टी फिर हारी। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता रहा। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार तो उनके बेटे भी हार गए। रेणु मित्तल आगे कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की साख 5 साल में इतनी कम हुई है कि पार्टी राज्य में एक ही सीट जीत पाई। कांग्रेस की जिन राज्यों में सीधी लड़ाई है, वहां कई जगह पार्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कांग्रेस ने कभी अपना संगठन बनाने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा इस सोच में रही कि भाजपा डाउन होगी, तो लोग खुद हमें वोट करेंगे।

बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के पीछे भी नाना पटोले का ही हाथ माना जाता है। विधानसभा चुनाव से पहले हाईकमान इस ओर ध्यान नहीं देता है तो कांग्रेस में और फूट दिख सकती है।

हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं। कांग्रेस ने राज्य की जिम्मेदारी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे रखी है। हुड्डा विधायक दल के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष उदयभान उनके करीबी माने जाते हैं। हरियाणा में दूसरा खेमा पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद कुमारी शैलजा का है। रणदीप सिंह सुरजेवाला भी शैलजा खेमे के नेता माने जाते हैं। 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष थीं। तब हुड्डा से उनकी अदावत की वजह से पार्टी बंटी नजर आती थी। 2022 से कांग्रेस ने एक बार फिर हुड्डा पर भरोसा जताया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनाव भी पार्टी उनके ही नेतृत्व में लड़ने वाली है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने चुनाव से पहले शहरी क्षेत्र में पदयात्रा निकालने का ऐलान किया है। इसके तुरंत बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके रथयात्रा का कार्यक्रम फाइनल कर दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हरियाणा में संगठन स्तर पर लिए जाने वाले फैसलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ही चल रही है। कुमारी शैलजा खुलेआम इसका विरोध करती रही हैं। राज्य में जाट और दलित के पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की परेशानियां हैं, उन्हें पार्टी हाईकमान को दूर करना पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस के पास चुनाव जीतने और सत्ता में वापस आने का बड़ा मौका है। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती है, तो इससे केंद्र की राजनीति पर असर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़े लेवल पर संगठन में बदलाव करने की तैयारी में है। पार्टी में कई सीनियर लीडर रिटायरमेंट की उम्र में आ चुके हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पुराने नेताओं की जगह नए चेहरों पर जोर दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष सहित सभी पद युवा या नए चेहरों को देने का प्लान है। अगले दो महीने में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हटाने की भी चर्चा है। दो नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि नए चेहरों और युवाओं को आगे करने पर सीनियर नेताओं का साथ नहीं मिल रहा है। कलह के डर से पार्टी कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के ज्यादातर नेताओं ने बेटों को राजनीति में लॉन्च कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि हमारे पास कई सीनियर नेता हैं। पार्टी को उनका बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। हम प्रदेश स्तर पर बदलाव करेंगे, तो निचले स्तर तक युवाओं के साथ अनुभवी चेहरों को भी मौका देंगे।

झारखंड में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। यहां कांग्रेस के कई नेता मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को बदलने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जून में हुई मीटिंग में भी ये मांग उठी। सूत्र बताते हैं कि राज्य के सीनियर नेताओं ने हाईकमान के सामने कहा कि मौजूदा अध्यक्ष ने संगठन के लिए कोई खास काम नहीं किया। उन्होंने अपनी बात साबित करने के लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का सहारा लिया। रिजल्ट के मुताबिक, कांग्रेस 13 विधानसभा सीटों पर आगे रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 16 और भाजपा को 52 सीटों पर बढ़त मिली। इस लिहाज से देखें, तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार तय है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दो सीटें जीती हैं।

2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू-कश्मीर में चुनाव हैं। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने यहां काम शुरू कर दिया है। हालांकि, कांग्रेस और राहुल गांधी के रणनीतिकार उप्र और गुजरात में संगठन मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी 6 जुलाई को गुजरात गए थे। वहां वे जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थीं। भाजपा ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उप्र में भी जातिगत जनगणना और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को फायदा मिला है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि प्रदेश में सहयोगी पार्टी सपा को दलित और ओबीसी वोट मिले, उसकी वजह भी कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत हैं। केरल के केसी वेणुगोपाल दिल्ली में बहुत पावरफुल हैं। अब प्रियंका गांधी खुद वायनाड से चुनाव लड़ने जा रही हैं। जम्मू-कश्मीर में गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़कर चले गए। वहां लीडरशिप क्राइसिस है। ये दिक्कत कश्मीर में ज्यादा है, जम्मू में उतनी नहीं है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहां भी सेकंड लाइन की लीडरशिप है। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजेंद्र सिंगला हैं, प्रताप सिंह बाजवा हैं। रवनीत सिंह बिट्टू और सुनील जाखड़ जैसे कुछ नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, बावजूद इसके पंजाब में लीडरशिप क्राइसिस नहीं है। सूत्रों के मुताबिक, कमलनाथ के नेतृत्व में पार्टी मप्र में चुनाव हारी, तभी दिल्ली से नई लीडरशिप बनाने का आदेश हुआ। इसके बाद जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष और उमंग सिंघार को विधायक दल का नेता बनाया गया। ये राहुल गांधी का आदेश था कि सेकंड लीडरशिप को तुरंत मौका देना चाहिए। ऐसे ही राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा को कंटीन्यू किया गया और टीकाराम जूली को विधायक दल का नेता बनाया गया। जहां-जहां पार्टी हार रही है, वहां-वहां राहुल गांधी अपने हिसाब से लीडरशिप डेवलप कर रहे हैं।

● **विपिन कंधारी**

देश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दबदबा अन्य पिछड़ा वर्ग का है। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों के वोटिंग पैटर्न देखें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी। ये वोट खिसकने के चलते कई राज्यों में उसको नुकसान हुआ। इसीलिए भाजपा अब दोबारा ओबीसी वोटरों को साधने में जुट गई है।

संगठन से सत्ता तक ओबीसी को तरजीह

लोकसभा चुनाव के बाद देश की सियासत पूरी तरह से बदल गई है। इस चुनाव में ओबीसी मतदाता असल गेम चेंजर साबित हुए हैं। इसके चलते ही भाजपा 303 सीटों से घटकर 240 सीटों पर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनानी पड़ी है। भाजपा ने अपने खिसके हुए जनाधार को दोबारा से वापस लाने के लिए ओबीसी पर खास फोकस किया है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने सभी राजनीतिक नियुक्तियों में ओबीसी को ही अहिमयत देने का काम किया है। फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो या विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य की बात हो। ऐसे में देखना है कि भाजपा क्या दोबारा से ओबीसी का विश्वास जीत पाएगी?

देश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा दबदबा अन्य पिछड़ा वर्ग का है। इसकी आबादी 50 फीसदी से भी ज्यादा है। केंद्रीय ओबीसी सूची में करीब ढाई हजार जातियां शामिल हैं। ये जातियां अब तक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पार्टियों की समर्थक हैं। लोकसभा चुनाव में इस बार ओबीसी जातियों के वोटिंग पैटर्न देखें तो भाजपा और उसके सहयोगी दलों के वोट प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली थी। जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को फायदा मिला है। ओबीसी वोट खिसकने के चलते उप्र, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में भाजपा की सीटें कम हो गई हैं। इसीलिए भाजपा अब दोबारा से ओबीसी वोटरों को साधने के जतन में जुट गई है।

भाजपा ने बिहार और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष में बदलाव किया है। राजस्थान में ब्राह्मण समुदाय के नेता सीपी जोशी को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले मदन राठौड़ की ताजपोशी कर दी है। इसी तरह भाजपा ने बिहार में सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर दिलीप जायसवाल को संगठन की कमान सौंप दी है। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ओबीसी के घांची समाज से आते हैं। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कलवार समाज से हैं। इस तरह से भाजपा ने दोनों प्रदेश में पार्टी की कमान ओबीसी समुदाय के नेता को सौंप दी है। इसके पीछे भाजपा का सियासी मकसद साफ छिपा हुआ है। बिहार में 62 फीसदी तो राजस्थान में 55 फीसदी के करीब ओबीसी समुदाय के लोग हैं, जिसे देखते हुए भाजपा ने दांव खेला है।

महाराष्ट्र में खिसके सियासी जनाधार को भाजपा दोबारा से पाने के लिए एक फिर से चार दशक पुराने फॉर्मूले पर लौटी है। भाजपा ने एमएलसी चुनाव में पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ खोत को प्रत्याशी ही नहीं बनाया बल्कि जिताने का भी काम किया है। इसमें तीन ओबीसी समुदाय से हैं और दलित-मराठा एक-एक हैं। सूबे की सियासत में अपनी जड़ें जमाने के लिए भाजपा ने ओबीसी समुदाय के तहत आने वाली माली, धनगर और वंजारी समुदाय को जोड़कर माधव फॉर्मूला बनाया था। इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर भाजपा लंबे समय तक राजनीति करती रही है, लेकिन 2014 के बाद से मराठा समुदाय पर फोकस करने के चलते माधव फॉर्मूला पीछे छूट गया था। इसका नुकसान भाजपा को 2024 चुनाव में लगा है। इसीलिए भाजपा ने अपने पांच में से तीन ओबीसी एमएलसी बनाए हैं ताकि अपने पुराने वोटबैंक का विश्वास जीता जा सके।

उप्र में भाजपा का सियासी वनवास ओबीसी वोटों के दम पर ही टूटा था। 2014 में भाजपा ने गैर-यादव ओबीसी और गैर-जाटव दलितों पर

वसुंधरा राजे के साथ बैलेंस बनाने का दांव

मदन राठौड़ भाजपा के दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं और दो बार के विधायक रह चुके हैं। पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा सीट से दो बार चुने गए हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी थी। हालांकि, उन्होंने पार्टी के नेतृत्व द्वारा बात करने के बाद अपना पर्चा वापस ले लिया था, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। मदन राठौड़ के जरिए वसुंधरा राजे को भी साधने का दांव भाजपा नेतृत्व ने चला है। इसकी वजह है कि राठौड़ को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है। 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान मदन राठौड़ ने भाजपा के उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी संभाली थी। भाजपा के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मदन राठौड़ लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के सजातीय भी है।

फोकस करके एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाने में कामयाब रही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा के पीडीए फॉर्मूले के चलते सेंध लग गई है। कुर्मी, कोइरी, निषाद जैसी ओबीसी जातियां इस बार सपा के पाले में खड़ी रही हैं। इसकी वजह से भाजपा उप्र में पहले नंबर की पार्टी से नंबर दो की पार्टी बन गई है जबकि सपा 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में भाजपा अब दोबारा से ओबीसी वोटरों का विश्वास जीतने की कोशिश में है, जिसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से खाली हुई विधान परिषद की सीट पर मौर्य समाज से आने वाले बहोरन लाल मौर्य को एमएलसी बनाने का काम भाजपा ने किया है। इस तरह भाजपा ने उप्र में भविष्य के लिए अपने संकेत दे दिए हैं कि उसका फोकस ओबीसी पर ही रहने वाला है।

बिहार की सियासत ओबीसी वोटों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई है। इसीलिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव में मीसा भारती और सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर के सांसद चुने जाने के बाद उनकी राज्यसभा सीटें खाली हो गई हैं। उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव काराकाट सीट से इसीलिए हार गए थे, क्योंकि भोजपुरी एक्टर पवन सिंह चुनाव मैदान में निर्दलीय उतर गए थे। इसके चलते ही भाजपा ने कुशवाहा को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। इसके जरिए कुशवाहा को साधे रखने के साथ-साथ ओबीसी वोटों को भी संदेश देने की स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। इसके अलावा भाजपा ने जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सम्राट चौधरी से लेकर ओबीसी समुदाय से आने वाले दिलीप जायसवाल को सौंपी है, इससे समझा जा सकता है कि भाजपा का फोकस बिहार में किस वोटबैंक पर है।

लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिन राज्यों में नुकसान उठाना पड़ा है, उसमें राजस्थान भी शामिल है। सूबे की 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें गंवाने के बाद भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सीपी जोशी से लेकर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को सौंप दी है। गत दिनों भाजपा ने राजस्थान के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया। इसके साथ ही भाजपा ने अरुण सिंह की जगह पर राधा मोहनदास अग्रवाल को राज्य का प्रभारी बनाया है। राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मदन राठौड़ को ऐसी ही नहीं सौंपी गई है बल्कि सोची-समझी रणनीति के तहत उनकी नियुक्ति की गई है। भाजपा ने मदन राठौड़ के जरिए अपने कोर वोटबैंक ओबीसी को साधने का दांव चला है तो साथ ही पार्टी और संघ बैकग्राउंड से आने वाले नेताओं को भी संदेश दिया है। जनसंघ से भाजपा तक की यात्रा करने वाले मदन राठौड़ के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ भी बेहतर संबंध रहे हैं। इस तरह से भाजपा ने राजस्थान विधानसभा उपचुनाव से पहले मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर सियासी संदेश देने की कोशिश की है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को आरएसएस बैकग्राउंड होने का फायदा मिला है। मदन राठौड़ का जन्म 2 जुलाई 1954 को पाली जिले के रायपुर गांव में हुआ था। मदन राठौड़ शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के दिनों से ही वे राजनीति में सक्रिय होने लगे थे। 1970 के दशक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने अपनी पारी का आगाज किया था। रामजन्मभूमि के आंदोलन के वक्त उन्हें मथुरा के नरहौली थाने में गिरफ्तार किया गया था। मदन राठौड़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने से राजस्थान में आरएसएस की ताकत बढ़ी है और सियासी तौर पर वो पार्टी के लिए मुफीद हो सकता है। राजस्थान में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा को सियासी झटका लगा है, उसके चलते ही पार्टी ने अब ओबीसी जातियों पर खास फोकस किया है। इसलिए भाजपा ने मदन राठौड़ को प्रदेश संगठन का मुखिया बनाकर ओबीसी समुदाय के वोटबैंक का साधने का दांव खेला है। मदन राठौड़ घांची समाज से आते हैं, जो अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल है। राजस्थान में घांची समाज के लोग पशुपालक, दूध और तेल-घी का व्यवसाय करते हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में घांची समुदाय के लोग रहते हैं। झारखंड में तेली समुदाय के लोग भी खुद को घांची समाज की उपजाति मानते हैं। इस तरह भाजपा ने कई राज्यों में दांव खेला है। राजस्थान में ओबीसी समुदाय की आबादी 55 फीसदी के करीब है। राजस्थान को ओबीसी की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, क्योंकि यहां 10-15 नहीं बल्कि पूरी 91 छोटी-बड़ी जातियां है। देश के किसी राज्य में ओबीसी वोट बैंक में इस प्रकार सोशल इंजीनियरिंग कहीं पर भी नहीं है। ऐसे में पार्टी ने घांची समुदाय से आने वाले मदन राठौड़ के जरिए ओबीसी को साधने के लिए दांव खेला है। इतना ही नहीं प्रदेश के 25 में से 12 सांसद ऐसे हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और 120 विधानसभा सीट पर उनका प्रभाव है। भाजपा ओबीसी वोटर के सहारे राजस्थान में अपना दबदबा बनाए हुए हैं।

मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंप कर भाजपा ने राजस्थान में सत्ता और संगठन के बीच बैलेंस बनाने के साथ-साथ सियासी समीकरण को साधने का दांव चला है। सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय से आने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों में है। इसीलिए संगठन की जिम्मेदारी ब्राह्मण चेहरे सीपी जोशी से लेकर ओबीसी समुदाय से आने वाले मदन राठौड़ को सौंपी है। इस तरह भाजपा ने ब्राह्मण और ओबीसी के जरिए सूबे के सियासी समीकरण को साधे रखने की स्ट्रैटेजी बनाई है। इसके अलावा सत्ता और संगठन के बीच राजनीतिक बैलेंस बनाने के लिए प्लान बनाया है। मदन राठौड़ 80 के दशक में संघ से भाजपा में आए हैं और उसके बाद जिला संगठन से अपना काम शुरू किया। इसके अलावा प्रदेश संगठन में भी अलग-अलग पदों पर रहे हैं।

● इन्द्र कुमार

उपचुनाव से पहले संगठन में बदलाव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मदन राठौड़ को ऐसे समय मिली है, जब राजस्थान की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। भाजपा ने सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को संगठन की बागडोर सौंपकर उपचुनाव में जीत दर्ज करने का दांव चला है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा के लिए उपचुनाव जीतना काफी अहम हो गया है। ऐसे में भाजपा ने संगठन का चेहरा बदलकर उपचुनाव में जीत का तानाबाना बुना है। मदन राठौड़ ने खुद को पार्टी का सच्चा सिपाही बताते हुए उपचुनाव जीतने की हुंकार भी भर दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय बनाकर उपचुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह से उपचुनाव उनके लिए अग्निपरीक्षा है। देखना है कि वे किस तरह सियासी बैलेंस बनाकर चलते हैं?

लाल आतंक होगा खत्म!

पुनर्वास अभियान से जुड़ रहे नक्सली

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लाल आतंक का सफाया होने लगा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित नक्सल उन्मूलन नीति के तहत पुनर्वास अभियान पूना नार्कोम अभियान और नियद नेल्लानार योजना चलाई जा रही है। इन अभियानों और योजनाओं का असर अब जमीन पर दिख रहा है। नक्सली अब लाल आंतक का दामन छोड़कर शांति के साथ मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ किसी एक ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की यह सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। सुरक्षा बलों के लिए ये मुठभेड़ कई मायनों में अहम है। यह सफल ऑपरेशन जंगल के बीच अबूझमाड़ के अंदर सुरक्षा बलों के प्रवेश का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ इलाके को नक्सलियों का कोर इलाका माना जाता है। पिछले तीन दशकों से यह इलाका सुरक्षाबलों के लिए चुनौती बना हुआ है। जंगलों और पहाड़ों के बीच का यह इलाका नक्सलियों के लिए अभेद्य गढ़ बन गया। इस मुठभेड़ ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि पिछली कई वारदातों में शामिल नक्सलियों का सफाया हो गया है।

मानसूनी सीजन में फोर्स के जवानों को इजराइल का हैरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) ड्रोन की मदद से मूवमेंट कराया जा रहा है। इसकी मदद से 200 किमी के दायरे में नजर रखी जा रही है। बारिश के दौरान जंगल के अंदरूनी इलाकों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए यह मददगार साबित हो रहा है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (एनटीआरओ) के जरिए जानकारी जुटाई जा रही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर फोर्स को संबंधित स्थानों में भेजकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जाता है कि बस्तर में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए आसमान से नजर रखी जा रही है। रात के समय नक्सलियों के मूवमेंट और उनके ठिकानों को चिन्हांकित करने की क्षमता होने के कारण इसका उपयोग किया जा रहा है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि सीधे टारगेट पॉइंट को कवर करने में काफी मदद मिल रही है। नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने में योजना में कारगार साबित हो रहा है। बता दें कि पहले यह ड्रोन को दुर्ग-भिलाई के नंदनी स्थित सेंटर से उड़ान भरता था। इसके बाद में जगदलपुर शिफ्ट किया गया था। इसकी उपयोगिता को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में पत्थरबाजी एवं आतंकवादियों से निपटने के लिए कश्मीर ले जाया गया था।

रिमोट से उड़ान भरने वाला ईंधन चलित अत्याधिक ड्रोन एक बार में 8-10 घंटे तक उड़ान भर सकता है। वहीं करीब 1000-15000 फीट की ऊंचाई से जंगल के अंदर की गतिविधियों को देख सकता है। इससे मिले इमेज और फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के बाद नक्शे से संबंधित इलाके चिन्हांकित किए जा रहे हैं। सटीक जानकारी देने की क्षमता को देखते हुए राज्य के बार्डर और इसके आसपास के इलाकों को कवर किया जा रहा है। बताया जाता है कि उत्तर और दक्षिण बस्तर में नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए इसका उपयोग किया जा रहा है। नक्सलियों का सफाया करने के लिए रणनीति के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसके लिए यूएवी से साथ ही स्थानीय इंटेलिजेंस की टीम से मिले इनपुट के आधार पर फोर्स अभियान चला रही है। बता दें कि राज्य में भाजपा सरकार के आने के बाद लगातार चलाए जा रहे आक्रामक ऑपरेशन से नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। नक्सलियों के खिलाफ बारिश में भी लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके लिए विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। यहां एक चार्ट दिया गया है जिसमें जनवरी 2024 से 6 जुलाई 2024 तक बस्तर में नक्सलियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों को दिखाया गया है। चार्ट में निगरानी अभियान, खुफिया जानकारी जुटाना, गश्त और मुठभेड़ सहित विभिन्न तरीकों से हर महीने किए गए ऑपरेशनों की संख्या दिखाई गई है।

छत्तीसगढ़ में इस साल अब तक कम से कम 100 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2004-14 की तुलना में 2014-23 में देश में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा में 52 प्रतिशत की गिरावट आई है और मौतों की संख्या 69 फीसदी यानी 6,035 से 1,868 हो गई है। पिछले साल के आखिरी में, नक्सल प्रभावित राज्यों में सुरक्षा स्थिति की विस्तृत समीक्षा के बाद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर एक हाई पॉवर कमेटी का गठन किया गया। इसके सदस्यों में पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और खुफिया ब्यूरो के महानिदेशक, माओवाद विरोधी ग्रिड के अधिकारी और अन्य शामिल थे। अधिकारी ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई का परिणाम अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों ने 2014 से माओवादी बहुल इलाकों में शिविर स्थापित करना शुरू कर दिया। 2019 के बाद 250 से ज्यादा ऐसे शिविर स्थापित किए गए। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2014-23 की तुलना में 2004-14 में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं 14,862 से घटकर 7,128 हो गई हैं। वामपंथी उग्रवाद की वजह से सुरक्षाकर्मियों की मौत की संख्या 2004-14 में 1,750 से 72 प्रतिशत कम होकर 2014-23 के दौरान 485 हो गई है, जबकि नागरिक मौतों की संख्या 68 प्रतिशत घटकर 4,285 से 1,383 हो गई है। 2010 में हिंसा की घटनाओं वाले जिलों की संख्या 96 थी। 2022 में यह 53 प्रतिशत घटकर 45 हो गई। इसके साथ ही हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 2010 में 465 से घटकर 2022 में 176 हो गई। पिछले पांच सालों में, उन 90 जिलों में 5,000 से अधिक डाकघर स्थापित किए गए जहां माओवादी उपस्थिति है या जहां उग्रवादी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि 30 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में 1,298 बैंक ब्रांच खोली गईं और 1,348 एटीएम शुरू किए गए।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

महाराष्ट्र में होगा खेला

महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में असेंबली के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वहां की राजनीति तेजी से बदल रही है। अभी तक अजित पवार की एकनाथ शिंदे और भाजपा गठबंधन सरकार से खटपट की खबरें आ रही थी। अब शरद पवार के एक कदम ने भी लोगों के कान खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और एनसीपी (शरतचंद्र पवार गुट) सुप्रीमो शरद पवार ने गत दिनों सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस मुलाकात को यूं तो महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर आधारित बताया गया लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसके पीछे राज्य में पनप रहे नए राजनीतिक समीकरणों का इशारा बता रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक सहयाद्री के राजकीय गेस्ट हाउस में हुई इस मुलाकात में राज्य में दूध के दाम बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और चीनी मिलों के हालात पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राज्य में पिछले कई महीनों से चले आ रहे मराठा आरक्षण के मुद्दे पर पवार और शिंदे में बातचीत हुई। करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई। बैठक से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मराठा आरक्षण के मुद्दे पर दोनों नेता चिंतित नजर आए। मराठा आरक्षण के विरोध में ओबीसी जातियों की लामबंदी को देखते हुए दोनों नेताओं ने इस मामले में फूंक-फूंककर कदम आगे बढ़ाने पर जोर दिया। जिससे असेंबली चुनाव से पहले राज्य में किसी तरह का जातीय तनाव न पैदा हो जाए। सीनियर पवार से बातचीत में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मराठा आरक्षण देने के लिए अब तक सरकार की ओर से किए गए उपायों से अवगत कराया।

महाराष्ट्र के दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात अमित शाह के महाराष्ट्र भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद हुई। उस रैली में अमित शाह ने शरद वार को भ्रष्टाचार का स्रोत बताकर बड़ा हमला बोला था। शाह ने रैली में कहा कि शरद पवार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे। उन्होंने भ्रष्टाचार को महाराष्ट्र में संस्थागत रूप दे दिया, जिसका खामियाजा आज राज्य की जनता भुगत रही है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का मुखिया भी बताया था। अमित शाह के सीधे अटैक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शरद पवार को आईना दिखाते हुए उन्हें अंदर झांकने को कहा था। शिंदे ने कहा कि वे हम पर करप्शन का आरोप लगाते हैं, जबकि हमारी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी मामला निकलकर नहीं आ सकता। वहीं जो लोग लंबे समय तक महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज रहे, उन्हें हम पर आरोप लगाने से आत्म-निरीक्षण कर लेना चाहिए। बताते चलें कि लोकसभा चुनावों में उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट न आने से राज्य के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में बिखराव के सुर तेज हुए हैं। बताया जा रहा है कि अजित पवार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और वंचित अघाड़ी गठबंधन के साथ तालमेल करके असेंबली चुनावों में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। ऐसा करके वे मराठा, मुसलमानों और दलितों का गठबंधन कर ज्यादा सीटें जीतने की जुगत में हैं। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे भी अपना वजूद बनाए रखने के लिए नया गठबंधन साथी तलाशने में लग गए हैं, यह सवाल लोगों के अधरों पर है।

महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद परिस्थिति पूरी तरह बदल गई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए की बुरी हार के बाद गठबंधन के भीतर ही सिरफुटव्वल शुरू हो गया है। इस चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर जहां संघ ने एनसीपी के अजित पवार के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं एनसीपी भी अब आक्रामक हो गई है। अपने विधायकों और नेताओं की बगावत से आजीज आ चुके अजित पवार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने कहा है कि भले ही हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन हम स्थानीय निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहते हैं। अजित पवार ने यह भी भविष्यवाणी की कि विधानसभा चुनाव अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में होंगे। साथ ही कल्याणीनगर मामले को लेकर विधायक पर लगे आरोपों और जिला योजना की बैठक में शरद पवार को कथित तौर पर बोलने नहीं देने को लेकर भी अजित पवार ने सफाई दी। अपनी पार्टी के पुणे इकाई को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा कि एनसीपी अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। ऐसे में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम में जुट जाना चाहिए। अजित पवार के इस बयान को उनकी पार्टी के भीतर मची भगदड़ को थामने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल, अजित पवार का यह बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ में बड़ी संख्या में स्थानीय नेताओं ने एनसीपी शरद गुट का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के खराब प्रदर्शन के बाद अजित पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाने की है। हालांकि, स्थानीय निकायों के चुनाव की तारीख अभी तक घोषित नहीं हुई है। कल्याणीनगर दुर्घटना मामले में विधायक सुनील टिंगरे से तीन से चार बार पूछताछ हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, इसलिए उनकी बदनामी हो रही है। अजित पवार ने कहा है कि लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते मदद के लिए बुलाते हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। पुणे में जिला योजना समिति की बैठक में फंड आवंटन पर झूठी कहानी गढ़ी गई। यह कहना स्पष्ट रूप से झूठ है कि बुजुर्गों को बोलने की अनुमति नहीं थी। मैंने अभी नियम बताए हैं। लेकिन अजित पवार ने सुप्रिया सुले पर तंज कसते हुए कहा कि ये सही नहीं है कि उनसे एक बार फिर झूठ बोला गया।

● **बिन्दु माथुर**

राज्य में राजनीतिक हलचल

महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राजनीतिक खेमेबंदी का दौर भी शुरू हो चुका है। एनसीपी (अजित गुट) से ताल्लुक रखने वाले पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्र के कई नेताओं ने शरद पवार की पार्टी का दामन थाम लिया था। इससे महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति के दिग्गज नेता शरद पवार काफी उत्साहित हैं। इतना ही नहीं, छगन भुजबल भी शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं, ऐसे में राजनीतिक कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इस सवाल पर भी चर्चाएं आम हो चुकी हैं कि क्या दोनों पवार फिर से एक साथ एक मंच पर आएंगे? हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की अगुवाई वाली महायुती गठबंधन को झटका लगा था। वहीं, एनसीपी (शरद गुट), शिवसेना (उद्धव गुट) और कांग्रेस की महाअघाड़ी को ठीक-ठाक सफलता मिली।

बड़े खेल ही तैयारी में महारानी

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह तीन दिवसीय झालावाड़ दौरे पर रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे ने झालावाड़ जिले के झालरापाटन और पिड़ावा कस्बे में स्कूटी पर बैठकर कस्बे का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने दौरे के दौरान वसुंधरा राजे जनता के बीच जिस तरह से सक्रिय नजर आई, सियासी गलियारों में उसे लेकर अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। प्रदेश में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बड़े खेल की तैयारी में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में कहीं भी प्रचार नहीं किया। वसुंधरा राजे झालावाड़ में ही अपने बेटे दुष्यंत सिंह की सीट पर एक्टिव रहीं। लोकसभा चुनाव के बाद झालावाड़ के तीन दिवसीय दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राज्य में पूरी तरह एक्टिव नजर आई। झालावाड़ जिले में वे 3 दिन तक सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर जायजा भी लिया और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र से पांच बार से विधायक हैं। वह साल 2003 में यहां से विधायक चुनी गई थीं। वसुंधरा राजे दो बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। प्रदेश में उन्हें जनाधार वाला नेता माना जाता है। पार्टी में उनकी गिनती कद्दावर नेताओं में की जाती है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों वसुंधरा राजे के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल की वसुंधरा राजे से मुलाकात को अहम माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिस तरह झालावाड़ जिले में सक्रिय नजर आ रही हैं। उससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे किसी बड़ी तैयारी में हैं। झालावाड़ में संगठन पदाधिकारी की बैठक लेते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि चुनाव के लिए तैयार रहो। अब इसे लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। सियासी गलियारों में उनके इस बयान को लेकर अलग-अलग मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में होने वाले नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारी को यह निर्देश दिए हैं। वही राजनीति के जानकारों का मानना है कि वसुंधरा राजे किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। बहरहाल वसुंधरा राजे के इस बयान ने राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल की बढ़ेंगी चुनौतियां

राजनीतिक विश्लेषक मनीष गोधा का मानना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए आने वाला समय मुश्किल भरा होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को केंद्रीय राजनीति में भेजा जा सकता है। दूसरी ओर कांग्रेस के डोटासरा ने विधानसभा उपचुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अपनी क्षमता साबित की है। वे हाईकमान के पसंदीदा बनेंगे। गहलोत के लिए यह दूसरी हार है। उनके बेटे को दूसरी बार पराजय का सामना करना पड़ा है। ऐसे में गहलोत को केंद्रीय संगठन में इस्तेमाल किए जाने की संभावना बन रही है। राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा का प्रभाव बढ़ने की उम्मीद है। अशोक गहलोत को पार्टी के केंद्रीय संगठन में शामिल किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल, इस चुनाव में छह प्रमुख नेताओं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बहुत कुछ दांव पर लगा था।

लोकसभा चुनाव और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे की तस्वीर एक बार फिर पार्टी के पोस्ट में नजर आने लगी है। पार्टी मुख्यालय पर लगे पोस्टर में वसुंधरा राजे की फोटो को देखा जा सकता है। हाल ही में हुई भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में भी वसुंधरा राजे पहुंची थीं। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसे लेकर माना जा रहा है कि पार्टी में वसुंधरा राजे की अहमियत बढ़ी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा उपचुनाव में वसुंधरा राजे कितनी सक्रिय नजर आती हैं। हालिया लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद राजस्थान में बड़े राजनीतिक बदलाव की संभावना है। सियासी विश्लेषक और वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। यही नहीं, संभावना यह भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आने वाले महीनों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा ही नहीं कांग्रेस में भी बड़े बदलावों की संभावना जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस ने पिछले तीन चुनावों में पहली बार कड़ी चुनौती पेश की और सहयोगियों के साथ मिलकर 25 सीटों में से 11 सीटें हासिल कर लीं। भाजपा को 14 सीटों से संतोष करना पड़ा। भाजपा इस बार 25 सीटों की हैट्रिक बनाने से चूक गई। नतीजों से कांग्रेस का खेमा गदगद है। ये नतीजे राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषक नारायण बारेठ कहते हैं कि इस चुनाव ने शीर्ष नेतृत्व को संदेश दिया है कि राज्यों में वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुभवी नेतृत्व का उपयोग किया जाना चाहिए। अब राजे हों या गहलोत, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों का शीर्ष नेतृत्व उन्हें दरकिनार करने का जोखिम नहीं मोल लेगा। वसुंधरा राजे को दरकिनार करने से भाजपा को इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है। मौजूदा वक्त में भाजपा को पूरे राजनीतिक परिदृश्य की समीक्षा करने की जरूरत है। सियासी इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि पिछले 25 सालों से राजस्थान की राजनीति गहलोत और राजे के इर्द-गिर्द घूमती रही है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सरकार से दूर तो संगठन के करीब

उप्र में लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा में सियासी घमासान जारी है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से शुरू हुई संगठन बनाम सरकार की लड़ाई कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भले ही कैबिनेट की बैठकों से लेकर कुंभ की तैयारी को लेकर ही समीक्षा मीटिंग से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन भाजपा संगठन के साथ तालमेल बैठाकर चल रहे हैं। केशव मौर्य भाजपा विधायकों के साथ-साथ सहयोगी दलों के नेताओं के साथ भी मिलजुल रहे हैं और पार्टी दफ्तर में होने वाली बैठक में भी शिरकत कर रहे हैं। उप्र भाजपा में संगठन बनाम सरकार की लड़ाई अब खुलकर सामने है। गत दिनों लखनऊ के भाजपा कार्यलय में बैठक हुई, जिसमें दोनों उपमुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक के साथ-साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि उनकी पहले से आजमगढ़ और वाराणसी में मीटिंग निर्धारित थी। इसके चलते मुख्यमंत्री योगी बैठक में नहीं आ सके जबकि पार्टी के चार शीर्ष नेता उपस्थित रहे।

केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक का भाजपा कार्यलय में होने वाली बैठक में रहना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के न पहुंचने को लेकर सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य संगठन के साथ बेहतर तालमेल बैठाकर चल रहे हैं, क्योंकि प्रदेश कार्यसमिति की बैठक से वो कई बार कह चुके हैं कि संगठन, सरकार से बड़ा होता है। लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद भले ही कैबिनेट की बैठकों से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन संगठन के साथ नजदीकी बनाकर चल रहे हैं। वे गत दिनों संगठन महामंत्री धर्मपाल और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक कर सियासी संदेश देने की कवायद करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ और वाराणसी की बैठक के चलते प्रदेश दफ्तर की मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। मुख्यमंत्री योगी द्वारा आजमगढ़ में बुलाई गई बैठक में सुभासपा अध्यक्ष और पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश को शामिल होना था। राजभर ने मुख्यमंत्री योगी की बैठक में शामिल होने के बजाय लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य के साथ मुलाकात की। हालांकि, उनकी केशव से किस मुद्दे पर बात हुई, यह किसी से शेयर नहीं किया गया। राजभर की केशव से मुलाकात को भाजपा के भीतर चल रही खींचतान के तहत हो रही लामबंदी से जोड़कर देखा जा रहा है।

उप्र में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को गहरा झटका देने का काम किया है। भाजपा उप्र में 62 सीटों से घटकर 33 पर पहुंच गई है। उप्र में हार के चलते ही भाजपा बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई। इसके बाद से लगातार बैठकों का दौर जारी है। हार पर मंथन ने भाजपा में टेंशन पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की हार के पीछे अति आत्मविश्वास बताया तो केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताया। इसके बाद से भाजपा में खींचतान जारी है। केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में अपने तेवर दिखाए थे। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और हमेशा रहेगा। मैं उपमुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इसके बाद दूसरे दिन केशव ने अपनी ही योगी सरकार को पत्र लिखकर पूछा कि संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन कितना किया गया है। केशव ने जिस नियुक्ति और कार्मिक विभाग (डीओएपी) से सूचना मांगी है, वह मुख्यमंत्री योगी के पास है।

केशव प्रसाद मौर्य के कदम को योगी को संदेश देने से भी जोड़कर देखा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि लोकसभा चुनाव में सीट कम आने के बाद मुख्यमंत्री योगी और केशव में दूरियां बढ़ गई हैं। इसीलिए वह सरकार की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो रहे और बार-बार सरकार से बड़ा संगठन को बताकर सियासी एजेंडा सेट करने में जुटे हैं। उप्र में मिली हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अपनी रिपोर्ट में योगी सरकार के प्रति कार्यकर्ताओं की नाराजगी को रेखांकित किया है। 2017 में उप्र विधानसभा चुनाव के समय केशव मौर्य भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। पार्टी को बंपर चुनावी कामयाबी मिली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली थी। केशव को उपमुख्यमंत्री बनकर संतोष करना पड़ा। इसके बाद से केशव मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच सियासी टकराव की खबरें आती रहीं। 2022 के चुनाव से पहले संघ ने केशव और योगी के बीच सियासी संतुलन बनाने के लिए हस्तक्षेप किया था।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

खत्म होती नहीं दिख रही तकरार

उप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच लंबे समय से तनातनी की खबरें आती रही हैं। संगठन बड़ा या फिर सरकार। इस मसले पर दोनों नेताओं में जबरदस्त अदावत की स्थिति दिखती रही है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा के खराब प्रदर्शन को लेकर भी दोनों नेताओं की अपनी-अपनी थ्योरी है। योगी बनाम केशव के झगड़े में अब नया मोड़ आ गया है। विवादों की कड़ी में ताजा मामला है, आउटसोर्सिंग में आरक्षण न लागू करने का। भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने पहले ही ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस बात पर मुख्यमंत्री योगी को चिट्ठी भी लिखी थी। ये आरोप लगे थे कि योगी राज में कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में पिछड़ों और दलितों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य कैंप का दावा है कि चुनाव से पहले ही वे इस खतरे को भांप गए थे। उनकी ओर से उप्र सरकार से कई बार जानकारी मांगी गई थी। उन्होंने चिट्ठी लिखकर कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में सवाल किया था कि कितने लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिला, पर उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का मानना है कि आउटसोर्सिंग पर दी जाने वाली नौकरी में रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। जबकि उप्र सरकार ने साल 2008 में ही कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाने वाली नौकरी में इसकी व्यवस्था की थी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार से पूछा है कि अब तक कितने पिछड़े और दलितों को आउटसोर्सिंग में नौकरी दी गई है। उन्होंने इसके लिए नियुक्ति और कार्मिक विभाग के प्रमुख को चिट्ठी लिखी है।

मजबूरी या तवज्जो...

लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठने लगी थी। मोदी सरकार ने भले ही विशेष राज्य की मांग से इनकार कर दिया हो, लेकिन बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसी के तहत बिहार में गया को औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेगा। यह कॉरिडोर औद्योगिक विकास को कार्यान्वित करेगा। यह मॉडल बहुत ही अच्छा होगा। इस मॉडल में विकास भी दिखेगा और विरासत की भी झलक होगी।

वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा। बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। इसके अलावा बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनाया जाएगा। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा। पूंजीगत निवेशों में सहायता के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार सरकार के बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाह्य सहायता के अनुरोध पर तेजी से कार्यवाही होगी। वित्तमंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का ऐलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजगीर के तीर्थ क्षेत्रों का भी विकास होगा। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए वहां विकास किया जाएगा।

केंद्र सरकार की ओर से पेश इस बार के बजट में राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 60,000 करोड़ रुपए अधिक के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया। इनमें तीन एक्सप्रेसवे, एक बिजली संयंत्र, विरासत कॉरिडोर, नए एयरपोर्ट एवं खेल बुनियादी ढांचे के लिए योजनाओं की रूपरेखा पेश की गई। बजट में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे तथा बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा एक्सप्रेसवे और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के विकास के लिए केंद्र के सहयोग की घोषणा की गई। वित्तमंत्री ने कहा कि चार परियोजनाओं की कुल लागत 26,000 करोड़ रुपए होगी। बिहार के लिए अन्य सौगातों में भागलपुर जिले के पिरपैंती में 2400 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित करना शामिल है, जिस पर 21400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कहा कि वो बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार की मदद करेगा। बिहार नेपाल से निकलने वाली कई नदियों की बाढ़ से अक्सर पीड़ित रहता है। कोसी से संबंधित बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जांच भी की जाएगी। सरकार बाढ़ से निपटने के लिए राज्य को 11,500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी।

वित्तमंत्री ने गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने की भी घोषणा की है। इसमें से एक पुल बक्सर में बनाने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से बिहार के नालंदा शहर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य में पर्यटन की अन्य संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा। इसी क्रम में बिहार में बिजली की समस्या को देखते हुए यहां पिरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर की भी रूपरेखा तैयार की गई है।

अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री ने बिहार की दुखती रग कोसी नदी की समस्या का भी हल निकालने की बात की। उन्होंने कहा कि इस नदी में हर साल आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए अलग से बजट जारी किया जाएगा। इसी क्रम में सड़क परियोजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने बिहार के लिए 26000 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के सहयोग से बिहार को आर्थिक मदद उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश आदि राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना शुरू होगी। इसके लिए औद्योगिक गलियारे के प्रारूप पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचे थे। उस समय उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं बिहार को 25 हजार करोड़ रुपए का बजट देने का अभी और इसी समय ऐलान करता हूं। किसी कारण प्रधानमंत्री उस समय तो वह वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार के बजट में उन्होंने बिना कुछ कहे बिहार के लिए झोली खोल दी। 25 हजार करोड़ की जगह इस बार के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 60 हजार करोड़ से भी अधिक का बजट दे दिया है।

● **विनोद बक्सरी**

बिहार की जरूरतों वाला बजट

केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि बजट सकारात्मक और स्वागत योग्य है। इस बजट में बिहार की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत बिहार के मानव संसाधन विकास और बुनियादी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए आगे कहा कि इस बजट में बिहार की सड़क संपर्क परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की संरचनाओं के लिए विशेष राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में बिहार के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विशेष सहायता की घोषणा की गई है। बिहार को बाढ़ से बचाव के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कोशी-मेची नदी जोड़ परियोजना, नदी प्रदूषण न्यूनीकरण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है, जो स्वागत योग्य है। बिहार के लिए बजट में विशेष प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को विशेष धन्यवाद।

संकट में फंसा पाकिस्तान

पाकिस्तान लगातार भारत में आतंकवादी हरकतों को अंजाम देता रहा है। मुंबई में 2008 में हुए हमलों से लेकर कठुआ, पठानकोट और उरी वगैरह में उसने आतंक फैलाया है। पर अब पाकिस्तान खुद ही अपने द्वारा लगाए आतंकवाद की आग में स्वाहा हो रहा है। वह भयभीत है। डर का कारण चीन का नाराज होना है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के मारे जाने के कारण चीन सरकार उससे सख्त नाराज है। इसलिए सारे पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को अब खास सुरक्षा दी जा रही है, जो पाकिस्तान में चीन की मदद से चल रही परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस्लामाबाद में एक नया पुलिस बल भी बनाया गया है। ये सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि चीनी वित्त पोषित मेगा परियोजनाओं को निशाना बनाया जा रहा है। इनमें काम करने वाले चीनियों को आतंकवादी चुन-चुन कर मार रहे हैं। इन हमलों के कारण ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाएं खतरे में हैं।

चीन ने पाकिस्तान में अपना बड़े स्तर पर निवेश करना 2015 से शुरू किया था। चीन की योजना थी कि वह पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर का निवेश विभिन्न परियोजनाओं में करे। इस वक्त हजारों चीनी कामगार और इंजीनियर पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में युद्ध समाप्त होने के बाद अमेरिका से मदद मिलनी बंद हो गई थी। उसके बाद, उसे चीनी निवेश का ही एकमात्र सहारा था। उस पर भी फिलहाल तो ग्रहण लगा हुआ दिखता है। पिछले तीन वर्षों में, पाकिस्तान में आतंकवादी समूह फिर से उभरे हैं। इस दौरान आतंकवादी हमलों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका असर चीनी परियोजनाओं पर खूब ज्यादा हुआ है। इस कारण से चीन से पोषित परियोजनाओं पर काम ठंडा पड़ने लगा है। पिछले मार्च के महीने के अंत में, सशस्त्र आतंकियों ने अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित ग्वादर में चीनी निर्मित और संचालित बंदरगाह को निशाना बनाया, जिसमें दो पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। कुछ दिनों बाद, आतंकवादियों ने देश के दूसरे सबसे बड़े एयर बेसपर हमला किया। यह बलूचिस्तान में है। यहां भी चीनी नागरिक सक्रिय थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ली थी।

पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक जलविद्युत परियोजना पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें पांच चीनियों की मौत हो गई। इसके बाद चीनी कंपनियों ने कम से कम तीन महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं पर अपना काम रोक दिया था। ये परियोजनाए थीं- दासू बांध, डायमर-बाशा बांध और तारबेला पांचवां एक्सटेंशन। खैबर पख्तूनख्वा सीमांत गांधी के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। चीनियों पर हमले खैबर पख्तूनख्वा के अलावा बलूचिस्तान में भी हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सटे हुए अफगानिस्तान से। पाकिस्तान के मशहूर अखबार दि डॉन में 1 अप्रैल, 2024 को छपी एक खबर के अनुसार, इस साल के पहले तीन महीनों में देश के दो प्रमुख राज्यों क्रमश: खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बीते साल की इसी अवधि की तुलना में आतंकी और हिंसक वारदातों में 92 और 86 फीसदी बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है, अपने नागरिकों पर हमले के कारण चीन नाराज है। पाकिस्तान चीन को अपना सबसे भरोसे का मित्र कहता है। चीन के नाराज होने से पाकिस्तान की सांसें रुक रही हैं। पाकिस्तान से मिल रही खबरों पर यकीन करें तो कुछ चीनी नागरिक अपनी जान को खतरा होने के कारण पाकिस्तान छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार बार-बार अपराधियों को पकड़ने का वादा कर रही है। लेकिन, हो कुछ नहीं रहा है। चीनियों पर हो रहे हमलों के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी), बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट-खुरासान को जिम्मेदार माना जा रहा है। ये तीनों इस्लामिक आतंकी संगठन अब पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लगभग जंग छेड़े हुए हैं।

खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और कोहिस्तान इलाकों को बहुत बीहड़ माना जाता है। ये क्षेत्र हत्याओं, लड़कियों के स्कूलों को जलाने और शिया मुसलमानों की हत्याओं के कारण कुख्यात रहे हैं। अब ये चीनी नागरिकों को मारने के कारण भी खबरों में रहने लगे हैं। खैबर में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। इधर, सरकार का डर या इकबाल खत्म हो चुका है। यहां पुलिस, सरकारी अफसर या राजनीतिक नेतृत्व आतंकियों के सामने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बात की संभावना न के बराबर है कि इधर चीनियों पर हमले थमेंगे। खैबर पख्तूनख्वा अंधकार युग में जा चुका है। सवाल यह है कि चीनी नागरिकों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? देखा जाए तो वहां पर वे विकास परियोजनाओं को खड़ा कर रहे हैं। दरअसल बलूचिस्तान और खैबर के लोगों का कहना है कि उनके यहां लगने वाली परियोजनाओं का स्थानीय जनता को लाभ नहीं मिलता। सारी मलाई पंजाब खा जाता है। इसका विरोध करने के लिए ही चीनियों पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार का मतलब पंजाब ही है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पंजाबी विरोधी आंदोलन से पाकिस्तान परेशान

बलूचिस्तान में पंजाबी विरोधी आंदोलन से पाकिस्तान सरकार की नींद बुरी तरह उड़ी हुई है। उसका इस बलूचों के आंदोलन के कारण परेशान होना समझ भी आता है। इधर, ही चीन की मदद से 790 किलोमीटर लंबा ग्वादर पोर्ट बन रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि ग्वादर पोर्ट के बन जाने से देश की तकदीर बदल जाएगी। पर बलूचिस्तान के अवाम को यह नहीं लगता है। उसका मानना है कि ग्वादर पोर्ट बनने से सिर्फ पंजाब के हितों को ही लाभ होगा। बलूचिस्तान की जनता को लगता है कि उनके क्षेत्र के संसाधनों से पंजाब और पंजाबियों का ही पेट भरा जाएगा। इसलिए ही बलूचिस्तान में पंजाबियों से घोर नफरत की जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से शुरू से ही अलग होना चाहता है। वह 1947 में ही भारत का अंग बनना चाहता था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने जबर्दस्ती पाकिस्तान की झोली में डाल दिया था। पाकिस्तानी सेना की ताकत ने ही उसे पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर रखा हुआ है। पिछले महीने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बीजिंग गए थे। वे चीन के शिखर नेता शी जिनपिंग से मिले। लेकिन, इस यात्रा का कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि चीन से पाकिस्तान में निवेश करने को लेकर कोई वादा नहीं किया। चीन ने पाकिस्तान में चीनियों पर हमलों पर नाराजगी जताई। यकीन मानिए कि अगर चीन ने पाकिस्तान के कटोरे में भीख डालना बंद कर दिया तो पाकिस्तान तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा।

क्या कमला हैरिस रचेंगी इतिहास?

राष्ट्रपति जो बाइडन के अपने चुनावी अभियान से हटने और उसकी कमान भारतीय मूल की कमला हैरिस को सौंपने के दो दिन बाद ही एक नया सर्वे आया है, जिसमें हैरिस की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बढ़त दिखाई गई है। रॉयटर्स-इप्सोस के पोल में हैरिस ने ट्रंप के ऊपर 2 प्रतिशत की बढ़त हासिल की है। यह पोल बाइडन के राष्ट्रपति चुनावी अभियान से हटने की घोषणा के बाद किया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति जो बाइडन ने सभी को चौंकाते हुए चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। 27 जून को डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस में खराब प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर लगातार चुनाव न लड़ने का दबाव बना हुआ था।

ताजा सर्वे में कमला हैरिस को 44 प्रतिशत समर्थन हासिल है जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 42 प्रतिशत लोगों ने समर्थन किया। हैरिस को बढ़त दिलाने वाला ताजा सर्वे ऐसे समय में आया है, जब उनके अभियान ने कहा है कि उन्होंने डेमोक्रेटिक नामांकन के लिए जरूरी समर्थन हासिल कर लिया है। इसके पहले 15-16 जुलाई के सर्वेक्षण में हैरिस और ट्रंप 44 प्रतिशत पर बराबर थे और 1-2 जुलाई के सर्वेक्षण में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रतिशत अंक से आगे थे। राष्ट्रीय सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि हैरिस के समर्थन में वृद्धि हो रही है। हालांकि, ट्रंप के अभियान ने हैरिस की बढ़त को महत्वपूर्ण नहीं कहा और इसे अस्थायी मीडिया कवरेज का परिणाम बताया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण कर्ता टोनी फैब्रीजियों का कहना है कि हैरिस की लोकप्रियता में हो रही वृद्धि संभवत: कुछ समय के लिए होगी। नेशनल सर्वे राजनीतिक उम्मीदवारी के लिए अमेरिकी लोगों के मूड के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। हालिया सर्वे में 56 प्रतिशत मतदाता ये मानते हैं कि 59 वर्षीय हैरिस मानसिक रूप से तेज और चुनौतियों से निपटने में सक्षम हैं, जबकि ट्रंप के बारे में 49 प्रतिशत मतदाताओं की ये राय है। केवल 22 प्रतिशत मतदाता बाइडन के बारे में ऐसा सोचते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने 81 वर्षीय बाइडन की उम्र और उनकी क्षमताओं को लेकर अमेरिकी मतदाता संशय जाहिर कर रहे थे। यही बात अब कमला हैरिस के पक्ष में जाती हैं और उम्र को लेकर दबाव अब ट्रंप के ऊपर होगा।

कमला हैरिस ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन से भी बात की है। हिलेरी ने कमला की तारीफ की और उन्हें अपना समर्थन दिया है। अब 1-7 अगस्त के बीच डेमोक्रेट्स नॉमिनेशन के लिए पहले राउंड की वोटिंग करेंगे। कमला चुनावी रैलियों में विपक्षी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर सीधे हमलावर हैं। हालांकि, ये लड़ाई आसान नहीं मानी जा रही है। यही वजह है कि डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को हराने के लिए नया दांव खेलने से पीछे नहीं हटेगी। दरअसल, डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस दौरान कमला को डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में चुने जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन पार्टी की उपराष्ट्रपति के बारे में क्या रणनीति होगी? क्या बराक ओबामा इसके लिए योग्य हैं? क्या अमेरिकी संविधान दो बार निर्वाचित राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति बनने की अनुमति देता है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी चुनाव में बराक ओबामा एक्टिव देखे जा रहे हैं। उन्होंने जो बाइडेन को चुनावी मैदान से हटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले उन्होंने ही बाइडेन का समर्थन किया था। बराक ने बाइडेन के लिए चंदा एकत्रित वाले कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और उनका समर्थन किया। अब ओबामा को कमला का खुलकर समर्थन करते देखा जा रहा है। अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन के कारण बराक ओबामा दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। 1951 में स्वीकृत इस संशोधन में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर दो बार से ज्यादा नहीं चुना जा सकता। चूंकि ओबामा ने 2009 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में दो कार्यकाल पूरे किए हैं, इसलिए वे संवैधानिक रूप से फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने या चुने जाने के लिए योग्य नहीं हैं। यानी ओबामा तीसरी बार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नहीं बन सकते, लेकिन क्या वे उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतर सकते हैं। अमेरिकी संविधान के 12 संशोधन में उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिक्र किया गया है।

1804 में स्वीकृत 12वां संशोधन कहता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए संवैधानिक रूप से अयोग्य कोई भी व्यक्ति अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्य नहीं होगा। इसलिए विवादास्पद मुद्दा यह है कि क्या दो बार निर्वाचित पूर्व राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से अयोग्य हैं? 22वां संशोधन यह नहीं कहता कि ऐसा व्यक्ति संवैधानिक रूप से अयोग्य है। 22वें संशोधन के तहत तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध राष्ट्रपति पद की शर्त नहीं है। फ्रेंकलिन डी रूजवेल्ट के चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बनने के बाद 1951 में 22वें संशोधन को अनुमोदित किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल से ज्यादा समय के लिए राष्ट्रपति ना चुना जाए, ताकि कार्यकारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित न रहें।

● **कुमार विनोद**

...तो पहली बार किसी यहूदी शख्स का व्हाइट हाउस में दखल

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्रपति पद से हटना और कमला हैरिस को समर्थन देना अमेरिका में इतिहास रच सकता है। अगर कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बनती हैं तो व्हाइट हाउस में पहली बार किसी यहूदी का सीधे तौर पर दखल बढ़ जाएगा। कमला के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पति डग एमहॉफ व्हाइट हाउस में एक पति के रूप में पहले पार्टनर होंगे। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कोई यहूदी इतने बड़े पद पर पहुंचा हो। हैरिस की जीत इतना ही नहीं और कई इतिहास बनाने जा रही है। उन्हें अमेरिका की पहली महिला और भारतीय मूल की राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त होगा। जिसके बाद उनके यहूदी पति एमहॉफ पहले यहूदी राष्ट्रपति पति बन जाएंगे। उनकी हैसियत फर्स्ट जेंटलमैन की होगी। हैरिस के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान एमहॉफ कई बार साथ नजर आए हैं और उन्होंने हैरिस के अभियानों में कई जिम्मेदारी उठाई हैं। बाइडेन के पीछे हटने के बाद भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैरिस के लिए समर्थन की अपील की है।

विधवा की जिंदगी नर्क

मप्र के गुना जिले में पारदी समाज के युवक की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। पुलिस ने जिस समय युवक को हिरासत में लिया वह घोड़ी चढ़ने जा रहा था। दूल्हे के रूप से तैयार होकर वह अपनी दुल्हनिया को लेने जाने वाला था, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस हिरासत में उसकी मौत हो गई। युवक गुना जिले के पारदी समाज के ताल्लुक रखता था। उसकी मौत के बाद समाज से जुड़ी जो परंपराएं सामने आईं वो काफी चौंकाने वाली हैं।

गुना समेत प्रदेश के अन्य जिलों में बसे पारदी समाज में महिलाओं और पुरुषों के लिए कई परंपराएं हैं, जिनका सभी को पालन करना होता है। इस समाज की महिलाएं पति की मौत के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकती हैं। उन्हें विधवाओं की तरह ससुराल या मायके में रहना पड़ता है। वे किसी शुभ कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकती हैं और त्योहार भी नहीं मना सकती हैं। इन महिलाओं को नए कपड़े पहनना, चप्पल पहनना और किसी को अपना चेहरा दिखाना भी वर्जित होता है। विधवा महिलाओं को घर में ही रहना पड़ता है। गुना जिले में रहने वाले पारदी समाज की आसपास के चार-पांच गांव में रिश्तेदारियां हैं। यह लोग इन्हीं गांव में अपने बेटे-बेटियों की शादी करते हैं। पारदी समाज के युवक को शादी के काबिल तभी माना जाता है, जब उस पर केस दर्ज होते हैं। नाबालिग रहते ही इस समाज के लड़के चोरी करना सीख जाते हैं। अपराध की दुनिया में कदम रखने के लिए लड़के छोटी-छोटी चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। इसके बाद इनके अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ जाता है। पारदी समाज की मान्यता के अनुसार जिस लड़के पर सबसे ज्यादा केस दर्ज होते हैं, वह शादी के लिए उतना ही योग्य वर होता है।

पारदी समाज की कुछ परंपराएं अजीब जरूर हैं, लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जैसे, इस समाज की महिलाएं चरित्रहीनता सहन नहीं करती हैं। वे खुद इस तरह के कामों से दूर रहती हैं और पुरुषों को भी ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं होती है। इस समाज के दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसी घटनाएं न के बराबर हैं। इन पाबंदियों के बाद भी अगर कोई पुरुष या महिला ऐसी किसी चीज में शामिल पाई जाती है तो उसे सजा भी दी जाती है। कई मामलों में महिलाएं आत्महत्या तक कर लेती हैं। इस समुदाय के लोग अपराध की दुनिया में काफी सक्रिय रहते हैं। लेकिन, अपराध करने से पहले यह लोग मुहूर्त भी देखते हैं। समाज के ज्यादातर लोग कृष्ण पक्ष में चोरी या डकैती जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कृष्ण पक्ष के दौरान रात में चांद नहीं दिखता है, अंधेरा रहता है। वारदात से पहले यह लोग मौके पर पहुंचकर अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं या फिर शौच भी करते हैं। इसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं। कृष्ण पक्ष में डकैती या चोरी करने को यह लोग अंधेरी खेलना कहते हैं।

बमोरी की पूर्व जनपद अध्यक्ष सुलोचना पारदी का कहना है कि समुदाय में लड़कियों और महिलाओं के लिए सख्त नियम हैं। जैसे- जिस महिला के पति की मौत हो जाती है, फिर दोबारा उसकी शादी नहीं करवाते। यानी वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। समाज में कई महिलाएं हैं, जिनके पतियों की मौत हो गई हैं। वह विधवा की तरह ही जिंदगी जीती हैं। इस दौरान महिला अपने माता-पिता के पास रहती है। चाहे तो ससुराल में भी रह सकती है। ऐसे में उस लड़की की जिंदगी बहुत कठिन हो जाती है। हमारी जिंदगी सबसे बेकार है। पुलिस को सबसे पहले महिलाओं को मारना चाहिए। इसके बाद पुरुषों को मारना चाहिए। सुलोचना पारदी कहती हैं कि पति की मौत के बाद चप्पल पहनना, नए कपड़े पहनना और अच्छे कपड़े पहनना वर्जित होता है। यहां तक कि त्योहार मनाने पर भी पाबंदी रहती है। उसे किसी पूजा और शादी-समारोह समेत किसी भी शुभ कार्यक्रम में शामिल होने पर मनाही होती है। इस दौरान वह दिनभर घर में ही रहती है। वह सुबह किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। उसे सिर ढंक कर घर से निकलना होता है। पारदी समाज की महिलाएं चरित्रहीनता बर्दाश्त नहीं करतीं। न तो वे खुद ऐसे किसी अनैतिक काम में लिप्त रहती हैं और न पुरुषों को इजाजत है कि वह चरित्रहीनता करें। इसी कारण समाज में छेड़खानी, रेप जैसी घटनाएं न के बराबर हैं। अगर कोई पुरुष ऐसे किसी काम में लिप्त होता है, तो उसे सजा दी जाती है या महिला खुद का जीवन तक समाप्त कर लेती है। आसपास के 5 गांव में ही इनकी रिश्तेदारी और शादियां होती हैं।

रविकांत माहेश्वरी का कहना है कि पारदी समुदाय में युवक तभी शादी लायक माना जाता है, जब उस पर केस दर्ज होते हैं। इसीलिए ये लोग आपस में ही शादी करते हैं। लड़का नाबालिग रहते ही चोरी करना सीख जाता है। छोटी-मोटी चोरी से अपराध की दुनिया में कदम रखने की शुरुआत होती है। धीरे-धीरे बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगता है। समुदाय की मान्यता के मुताबिक जिस युवक पर जितने ज्यादा अपराध दर्ज होंगे, वह शादी के लिए उतना ही योग्य माना जाता है।

● **ज्योत्सना**

अपराध में शामिल रहती हैं महिलाएं

पारदी समाज की महिलाएं पुरुषों के साथ अपराध की दुनिया में शामिल रहती हैं। लेकिन, यह खुद किसी वारदात को अंजाम नहीं देती हैं। इनका काम रैकी करना होता है। महिलाएं बड़े शहरों की पॉश कॉलोनियों और चौराहों में रैकी करती हैं। इसके लिए ये महिलाएं चौराहों पर सामान बेचने और गाड़ी साफ करने के बहाने पैसे वाले लोगों को टारगेट करती हैं। इनके इशारे पर एक पुरुष तय टारगेट का पीछा कर कॉलोनी और घर तक पहुंचता है। इसके बाद महिलाएं घर तक पहुंचकर रैकी कर पूरी जानकारी जुटाती हैं, इसके बाद वारदात को अंजाम दिया जाता है। 14 जुलाई को गुना पुलिस ने बीलाखेड़ी में रहने वाले देवा पारदी और उसके चाचा गंगाराम पारदी को हिरासत में लिया था। इसी दिन देवा की बारात जाने वाली थी, वह दूल्हे के रूप में सजा हुआ था। लेकिन, बारात रवाना होने से पहले पुलिस पहुंच गई और उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि चोरी के सामान की बरामदगी के लिए देवा को ले जा रहे थे। इस दौरान उसके सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन, 45 मिनट चले इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। देवा की मौत के बाद उसके परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया था। उसकी होने वाली दुल्हन ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया था।

निष्काम भाव से कर्म करना ही भागवत गीता का मूल सूत्र

निष्काम भाव से कर्म करना ही भागवत गीता का मूल सूत्र है। निष्काम भाव से काम करना ही इस चराचर जगत के प्रत्येक प्राणी का उद्देश्य होना चाहिए।

महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुआ था। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। यह केवल एक पारिवारिक संघर्ष नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन अपने सगे-संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों को युद्धभूमि में देखकर विचलित हो गए। अर्जुन ने अपने परिजनों और गुरुजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इंकार कर दिया और भगवान श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। उनकी मनोदशा को दूर करने के लिए श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान श्रीकृष्ण ने महज 45 मिनट में अर्जुन को जीवन के रहस्यों, कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के बारे में समझाया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल सोचकर कर्म नहीं करना चाहिए, बल्कि निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। एक क्षत्रिय का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना है और अधर्म को समाप्त करना है। जिससे अर्जुन को यह समझ में आया कि श्रीकृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं। इसे मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था, लेकिन अब इसका अनुवाद कई भाषाओं में किया जा चुका है। जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, आदि शामिल हैं।

गीता में लिखा है अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अपनी पीड़ा और दुखों के लिए बाहरी संसार को दोष देना उचित नहीं है, बल्कि व्यक्ति को अपने मन को समझाना चाहिए और आत्म-परिवर्तन के माध्यम से अपने दुखों का समाधान करना चाहिए।

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥

अर्थात्, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को नीचे नहीं गिराना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र होता है और स्वयं ही अपना शत्रु। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का मन ही उसे बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्त करता है। इसलिए अपने दुखों का निवारण अपने मन के परिवर्तन से ही संभव है।

आध्यात्मिक जीवन में एक शब्द अक्सर सुनने में आता है निष्काम। कई लोग इस शब्द का बहुत अलग-अलग अर्थ लगाते हैं। कुछ तो बहुत ही हास्यास्पद होते हैं जो कहते हैं निष्कामता यानी कर्म से हट जाना। कर्म ना करना। जीवन की हकीकत यह है कि हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। कर्म के बिना तो पशु भी नहीं रह सकते। सिर्फ मनुष्य में ही यह संभावना है कि वह अपने कर्मों को अपने हिसाब से परिभाषित कर सकता है।

अधिकांश कर्म हम अपने हित और स्वार्थ के लिए करते हैं। इनका फल भी उतना ही होता है। इस तरह के कर्म को सकाम कर्म कहते हैं। यहीं से निष्काम कर्म की परिभाषा शुरू होती है। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसके पीछे हमारा कोई निजी हित, निजी स्वार्थ ना जुड़ा हो। कभी-कभी कुछ काम ऐसे भी किए जाएं, जिसका हमारे लिए कोई फायदा ना हो। हमेशा याद रखिए दूर तक वे ही कर्म फायदा देते हैं।

कर्म में निष्कामता का भाव होगा तो हमारी संवेदनाएं प्रबल होंगी। हम संवेदनशील बनेंगे। कभी अनजान की मदद, कभी प्रकृति की सेवा, कभी परमात्मा के ध्यान में बैठना, भगवान की पूजा करना लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं, किसी गरीब की सहायता ऐसे कई कर्म हैं जिनसे आप अपने भीतर निष्कामता का भाव लाने की शुरुआत कर सकते हैं।

कभी-कभी ये भी सोचिए कि आप सिर्फ निमित्त हैं, सारा काम कोई और ही करवा रहा है। थोड़ा समय ऐसा निकालें, जिसमें अपेक्षा रहित हो जाएं। जो हो रहा है उसे होने दें। अपने आप को सिर्फ एक माध्यम समझें। किसी भी कर्म में खुद को शामिल ना करें, मतलब खुद के स्वार्थ को ना देखें, फायदा हो रहा है या नुकसान इसका विचार मन में ना लाएं।

कर्म में निष्कामता जड़ भरत से सीखिए। भागवत में कथा है जड़ भरत की। वे कोई भी कर्म हो उसे परमात्मा की इच्छा समझकर करते थे। चिड़िया खेत का दाना चुग जाए तो परमात्मा की इच्छा, बाढ़ आ जाए तो परमात्मा की इच्छा। एक बार तो किसी ने उनकी बलि चढ़ाने के लिए उनकी गर्दन पर तलवार भी रख दी, तो भी वे निष्काम रहे। विचलित नहीं हुए। उसे भी परमात्मा की मर्जी ही माना। तो भगवान खुद आ गए उनकी जान बचाने। हमेशा ना सही लेकिन कभी-कभी हमारे मन में, कर्म में निष्कामता का भाव आएगा तो जीवन में कई उलझनों का जवाब मिल जाएगा। हल मिल जाएगा।

भगवान जब सृष्टि-रचना के समय मनुष्यों का निर्माण करते हैं, तब उनमें सत्व, रज और तमोगुण व कर्मों के अनुसार उन्हें ब्राह्मणादी वर्णों में उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार रचे हुए वर्णों के लिए उनके स्वभाव के अनुसार पृथक-पृथक कर्मों का विधान भगवान ही कर देते हैं। संसार का निर्माण हुआ तो यह चार प्रकार के लोग निर्मित होते गए। सत्व, रज और तम तीन गुणों का कार्य कैसे चलता है। हमने सत्रहवें अध्याय में देखा है फिर अठारहवें अध्याय में भी वर्णित है। यह सारा संसार इन तीनों गुणों से बना हुआ है। इन तीन गुणों का प्रमाण थोड़ा न्यूनाधिक हो जाने से मनुष्य अलग-अलग स्वभाव के बन जाते हैं। जैसे भोजन बनाया जाता है, थोड़ा सा नमक कम-ज्यादा हो जाता है तो स्वाद बदल जाता है। थोड़ी सी चीनी भी प्रमाण से अधिक हो जाती है तो भी स्वाद बदल जाता है। उसी प्रकार से तीन गुणों का प्रमाण परिवर्तन हो जाने से अलग-अलग प्रकार के लोगों का निर्माण हो जाता हैं।

उसी प्रकार गुण शब्द का अर्थ गुण सूत्र से भी है। पाश्चात्य संस्कृति में दो बातों को माना गया है। माता-पिता के जैसे अनुवांशिक गुण हैं वैसे गुण बालक में आ जाते हैं और दूसरा है जिस प्रकार का वातावरण आसपास में हमारे है, जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं उसके अनुसार हमारा स्वभाव बनता जाता है। उस प्रकार के कर्म हमें अच्छे लगने लगते हैं। उस प्रकार के कर्म ही हम अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, हम हमारे कर्म संस्कृति के अनुसार करते हैं। आसपास का वातावरण व वायुमंडल जैसा होता है हमारा वैसा स्वभाव बनता जाता है।

● **ओम**

पहली मुलाकात

आभासी संवाद का सिलसिला पहली मुलाकात तक आ पहुंचा। जब रितेश और करुणा पहली बार मिले थे। यूं तो दोनों के बीच दूर-दूर तक कोई रिश्ता न था। बस एक आत्मीय भावना के वशीभूत जब दोनों मिले भी तो खुली सड़क पर एक विद्यालय के सामने। पहली बार देखते ही दोनों ने एक-दूसरे को पहचान लिया, जैसे कब से एक-दूसरे को जानते हों। करुणा ने आगे बढ़कर रितेश के पैर छुए और फिर उसे अपने साथ अपने घर ले गई। जहां उसके परिवार ने खुले मन से रितेश का स्वागत किया। वैसे तो रितेश के लिए यह अप्रत्याशित नहीं था क्योंकि करुणा के अलावा उसके परिवार के सदस्यों से भी उसकी बातचीत होती रही। फिर भी इतनी आत्मीयता की उसे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। करुणा ने अपने पति सुदेश को फोन पर रितेश के आने की सूचना दी, तब उसने रितेश से सीधे बात कर मजाकिया लहजे में कहा- साले साहब! अपने जीजा से मिलकर ही जाइएगा।

रितेश ने हामी भर दी और शाम को जब सुदेश घर आया, तो माहौल और खुशनुमा हो गया। रितेश ने जब सुदेश से वापस जाने की बात की, तब सुदेश ने कहा- अरे यार! कुछ तो शर्म करो, पहली बार बहन के घर आए हो और इतनी जल्दी वापस जाने की बात करने लगे। क्या करुणा ने सिर्फ मिलने के लिए ही बुलाया था? अरे नहीं! ऐसी बात नहीं है, आप सबसे मिलने की इच्छा थी। ईश्वर की कृपा से वो पूरी हो गई। रितेश ने धीरे से कहा, तब सुदेश ने अधिकार से कहा- इच्छा अनिच्छा मुझे नहीं पता, बस आज आप नहीं जा रहे हैं बस। माना कि आप उम्र में थोड़ा बड़े होंगे, लेकिन करुणा को बहन कहते हैं तो रिश्ते में तो मैं ही बड़ा हो गया। फिर सुदेश ने करुणा से कहा- तुम अपने भाई को जाने देना चाहो तो जाने दो, मगर मैं अपने साले को तो नहीं जाने दूंगा। वैसे भी मां का तो तुम्हें पता ही है। पहले तो मां इजाजत नहीं देंगी और ज्यादा कुछ कहेंगे तो खोज खबर भी अच्छे से लेंगी। सुदेश की बात सुनकर रितेश हंस पड़ा और जाने का इरादा त्याग दिया।

- सुधीर श्रीवास्तव

प्रचार

गली मोहल्ले का चक्कर लगाती गाड़ियों में लाउडस्पीकर बज रहा था अबके गैस सिलेंडर 400 रुपए का हो जाएगा। गरीबी खत्म करने का हमारा वादा है, देखना हम इसे जरूर पूरा करेंगे। हाथ जोड़कर नेताजी गुजर रहे थे, वहीं पास में बैठे सुरेश ने कहा- चाचा अगर ऐसा हो जाए तो कितनी राहत मिलेगी। हर बार हमें महीनों में 1000 रुपए का फायदा होगा। हमारे लिए ये खबर किसी रामबाण से कम नहीं।

रामवीर चाचा- सच कहते हो सुरेश बेटा, हमारी कमर टूटी जा रही है इस मंहगाई में। इस खबर से कुछ तो राहत मिलेगी। प्रचार झूठा नहीं होना चाहिए। जनता को धोखा नहीं होना चाहिए। वो आप पर विश्वास करते हैं। उनका विश्वास टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर आप सचमुच कुछ करेंगे तो किसी को यकीन नहीं होगा।

- अभिषेक जैन

हे पार्थ! उठो

हे पार्थ! उठो संग्राम करो,
ये अपने नहीं, पराए हैं।
गुरु चक्रव्यूह लेकर गर्वित,
मित्रता-बोझ में कर्ण दबा।
हैं भीष्म प्रतिज्ञा में जकड़े,
अब रहा न मामा शल्य सगा।।
कुछ वचनबद्ध, कुछ स्वार्थबद्ध,
दुश्मन की ध्वजा उठाए हैं।
शांति-संधि का हर प्रयास,
निष्फल एवं बेकार हुआ।
छल-कपट बीच में सत्य-धर्म,
अपमानित व लाचार हुआ।।
सब लोग यहां सौ चेहरे में,
निज असली रूप छुपाए हैं।।
बस धर्मराज से ही कब तक,
सत्-धर्म बचेगा सोच जरा।
सहदेव, नकुल, हे भीमार्जुन!
तुमको पुकारती मातृ धरा।।
खल छली शकुनि के कौशल पर,
पापी कौरव इतराए हैं।
जितनी जल्दी तुम चेतोगे,
उतनी जल्दी हक पाओगे।
वरना रिश्तों के चंगुल में,
फंस, अपनी जान लुटाओगे।।
सबने हाथों में शस्त्र गहे,
सब लड़ने तुमसे आए हैं।
हर महायुद्ध का मूलबीज,
अच्छों की चुप्पी में पलता।
खल छल प्रपंच से पालित शिशु,
आखिर में दुर्योधन बनता।।
भीष्म, द्रोण कृप, विदुर, व्यास सब
मिलकर हर युद्ध रचाए हैं।
धिक्कार तुम्हें है हे पुरुषों,
हर नारी की मर्यादा का।
धिक्कार तुम्हें है हे पुरुषों,
हर सप्तपदी, हर वादा का।।
सक्षम नर की असमय चुप्पी,
से मानुष अधम कहाए हैं।
हे द्रुपद सुता मत वरण करो,
बस मत्स्य चक्षु के भेदन पर।
जिस कुल में लाक्षागृह होता,
सोचो उसके संवेदन पर।।
गांडीव गदाधारी परिजन,
धिक, तुम्हें द्यूत पर लाए हैं।
जब-जब कोई संख्या बल पर,
शोषक-नाशक बन जाता है।
हममें से कोई राम-कृष्ण,
बन करके शस्त्र उठाता है।।
फिर से नवल फूल बगिया के,
पाकर पतझर मुरझाए हैं।

- डॉ. अवधेश कुमार अवध

साकार होगा स्वर्ण का सपना

खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले ओलिंपिक 2024 संस्करण यानी पेरिस ओलिंपिक का आगाज 26 जुलाई को हो गया है, जो 11 अगस्त तक खेला जाएगा। ओलिंपिक में खेलने को तो कई सारे खेल खेले जाते हैं, मगर हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की। भारतीय हॉकी टीम ने अपने पहले तीन मुकाबले में जहां न्यूजीलैंड को हराया, वहीं अर्जेंटीना के साथ मैच बराबरी पर रहा। साथ ही आयरलैंड को 2-0 से मात दी।

खास बात यह कि भारतीय हॉकी टीम ओलिंपिक खेलों में पिछले चार दशक के स्वर्ण पदक के सूखे को खत्म करने की उम्मीदों के बोझ के साथ मैदान में उतरती रही है। इस बार पेरिस ओलिंपिक में उसके पास इसे हासिल करने का सुनहरा मौका है। क्योंकि भारतीय टीम के पास आठ स्वर्ण पदकों की विरासत है। टोक्यो ओलिंपिक खेलों में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीतने के बाद से पुरुष टीम से उम्मीदें कई गुना बढ़ गई हैं। इससे पहले 1980 में भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। 1928 से 1956 तक लगातार छह ओलिंपिक खेलों में स्वर्ण पदक हासिल करके भारतीय हॉकी टीम ने पूरी दुनिया में अपने खेल का लोहा मनवाया था। लेकिन 1980 के बाद चार दशक से अधिक समय हो चुका है, भारतीय हॉकी टीम इस प्रतियोगिता में कोई करिश्मा नहीं कर पाई है। अब देशवासी न केवल भारतीय टीम से एक और पदक जीतने की उम्मीद करते हैं, बल्कि यह भी चाहते हैं कि इस बार स्वर्ण पदक जीतकर इस सूखे को समाप्त किया जाए। इसके लिए चयनकर्ताओं ने भी पांच ओलिंपिक पदार्पण करने वाले खिलाड़ियों के साथ टीम में एक नए जोश भरने का काम किया है। ऐसे में सवाल है कि क्या अबकी बार दशकों से सूखा पड़ा स्वर्ण का सपना साकार हो पाएगा?

हॉकी के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी और समीक्षकों का कहना है कि टीम इंडिया को इसके लिए काफी सुधार और मेहनत करने की जरूरत है। टीम का पहला लक्ष्य शीर्ष चार यानी सेमीफाइनल में जगह बनानी होगी। पेरिस में भारत एक चुनौतीपूर्ण ग्रुप में है, जिसमें गत चैम्पियन बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड और आयरलैंड जैसी टीमें हैं। इसलिए टीम का पहला लक्ष्य शीर्ष चार में रहना और क्वार्टर फाइनल में जगह बनाना होगा। दूसरा हॉकी का इतना विकास हो चुका है कि ओलिंपिक में भाग लेने वाली सभी टीमों के पास स्वर्ण पदक हासिल करने का मौका है। मगर दावेदार हमेशा की तरह बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जर्मनी और हॉलैंड होंगे। हालांकि स्पेन और फ्रांस भी कम नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में इन टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसलिए वो इस महाकुंभ में खिताबी दावेदार हैं। भारत ने भी वो सारी तैयारियां की हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। पेरिस ओलिंपिक के लिए टीम की कप्तानी हरमनप्रीत संभाल रहे हैं। भारतीय हॉकी टीम में पांच नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। टीम की कमान जहां हरमनप्रीत के हाथ में है तो उनका डिप्टी मिडफील्डर हार्दिक सिंह को बनाया गया है। हरमनप्रीत यंग टीम के साथ अपना तीसरा ओलिंपिक खेलेंगे। हरमनप्रीत ने रियो ओलिंपिक 2016 में युवा खिलाड़ी के रूप में अपना पदार्पण किया था। भारत ने टोक्यो ओलिंपिक 2020 में ब्रांज मेडल जीता था। टीम में अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी हैं। दोनों खिलाड़ी अपना चौथा ओलिंपिक खेलेंगे। इसके साथ ही गोलकीपर के रूप में कृष्ण बहादुर पाठक, मिडफील्डर नीकंठ शर्मा और डिफेंडर के रूप में जुगराज सिंह को अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में पेरिस गए हैं। वहीं जिन पांच खिलाड़ियों ने अपना ओलिंपिक डेब्यू किया है उनमें जर्मनप्रीत सिंह, संजय, राजकुमार पाल, अभिषेक और सुखजीत सिंह शामिल हैं।

गौरतलब है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आजादी के बाद 1948, 1952 और 1956 में लगातार तीन बार खिताब जीतकर हैट्रिक बनाई थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 1960 के ओलिंपिक फाइनल में उस स्वर्णिम लक्ष्य को तोड़ा था। हालांकि भारत ने 1964 में अपने पड़ोसी को एक बार फिर धूल चटाई थी, वहीं 1968 और 1972 के ओलिंपिक में कांस्य पदक के साथ संतोष करना पड़ा था। 1976 के संस्करण में वो तब तक के अपने सबसे निचले स्तर, सातवें पायदान पर पहुंच गई थी। इसके बाद 1980 के ओलिंपिक खेलों में टीम से उतनी अपेक्षाएं नहीं थीं लेकिन 29 जुलाई 1980 को मॉस्को में भारतीय टीम ने फिर से खिताबी मुकाबले में परचम लहराया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये भारतीय हॉकी टीम का आठवां और आखिरी ओलिंपिक स्वर्ण पदक भी है। मॉस्को ओलिंपिक 1980 में भारत की जीत का एक बड़ा कारण कई देशों का खेलों में हिस्सा न लेना भी रहा। इस संस्करण में सिर्फ छह टीमों ने भाग लिया था। इसमें 1976 ओलिंपिक की स्वर्ण पदक विजेता न्यूजीलैंड, रजत पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया और कांस्य पदक विजेता पाकिस्तान भी शामिल नहीं था। जर्मनी, नीदरलैंड्स और ग्रेट ब्रिटेन ने भी इन खेलों में हिस्सा नहीं लिया था। इन सभी देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में खेलों का बहिष्कार करने का फैसला किया था जिसका कारण सोवियत संघ का अफगानिस्तान में दखल था।

● आशीष नेमा

ओलिंपिक में भारत का पहला कदम

भारतीय हॉकी टीम ने ओलिंपिक में पहली बार 1928 में कदम रखा। भारत को 1928 के ओलिंपिक खेलों में ग्रुप-ए में रखा गया था जिसमें बेल्जियम, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की टीम थी। भारत ने यहां स्वर्ण पदक जीता। यहीं से भारतीय हॉकी टीम के सुनहरे अतीत की शुरुआत हुई थी और फिर भारत ने अब तक रिकॉर्ड 8 ओलिंपिक स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। भारत में हॉकी की बात करें तो इसे ब्रिटिश सेना के रेजिमेंट में सबसे पहले शामिल किया गया था। भारत में सबसे पहले ये खेल छावनियों और सैनिकों द्वारा खेला गया। भारत में झांसी, जबलपुर, जालंधर, लखनऊ, लाहौर आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से हॉकी खेला जाता था। लोकप्रियता बढ़ने के चलते भारत में पहला हॉकी क्लब 1855 में कोलकाता में गठित किया गया था। इसके बाद मुंबई और पंजाब में भी हॉकी क्लब का गठन किया गया। 1928 से 1956 का दौर भारत के लिए स्वर्णिम काल रहा है। 1925 में भारतीय हॉकी संघ की स्थापना हुई थी। इंडियन हॉकी फेडरेशन ने पहला अंतरराष्ट्रीय टूर 1926 में किया था, जब टीम न्यूजीलैंड दौरे पर गई थी। इस दौरान भारतीय हॉकी टीम ने 21 मैच खेले और उनमें से 18 में जीत हासिल की। इसी टूर्नामेंट में ध्यानचंद जैसी दिग्गज शख्सियत को दुनिया ने पहली बार देखा था, जो आगे चलकर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने।

ट्रेन के शौचालय के सामने लेटकर पहुंचा मुंबई... इंजीनियरिंग छोड़ बना एक्टर

22 साल पहले साल 2002 में आई फिल्म शहीद-ए-आजम फिल्म को हर किसी ने बेहद प्यार दिया था। यह फिल्म महान क्रांतिकारी भगत सिंह की जिंदगी पर बनी थी। इस फिल्म से सोनू सूद ने हिंदी फिल्मों में अपना कदम रखा था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म में उनकी एक्टिंग देख हर कोई काफी खुश था। यहां तक फिल्म के प्रोड्यूसर ने सोनू की खूब पीठ थपथपाई थी।

हिंदी के अलावा साउथ फिल्मों में भी सोनू सूद का बड़ा नाम है। वे वहां के महंगे एक्टर्स में से एक हैं। साउथ में उनके नाम की तूती बोलती है। पर्दे पर वे सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहिद कपूर, जॉन इब्राहिम, संजय दत्त, रणवीर सिंह, जूनियर एनटीआर, धनुष, चिरंजीवी, महेश बाबू, आदि सुपरस्टार्स को पंगा ले चुके हैं। उनकी खलनायिकी के आगे हीरो की भी हल्के लगने लगते हैं।

एक इंटरव्यू में सोनू की सबसे छोटी बहन मालविका सूद सच्चर ने कहा कि मुबंई जैसे शहर में मेरे भाई ने काफी संघर्ष किया है। पैसे बचाने के लिए जनरल डिब्बों में ट्रेलर की। जब मेरा भाई नागपुर में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वह ट्रेन के डिब्बों में शौचालयों के पास खाली छोटी जगहों पर फर्श पर सोकर घर लौटता था। हमारे पिता उसे पैसे भेजते थे, लेकिन वह जितना हो सके उतना बचाने की कोशिश करता था। वह हमेशा हमारे पिता की कड़ी मेहनत को महत्व दिया। जब वह मुंबई में अपने मॉडलिंग करियर को शुरू करने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वह ऐसे कमरों में रहता था जहां सोते समय करवट बदलने के लिए एक इंच भी जगह नहीं थी। उसे करवट बदलने के लिए खड़ा होना पड़ता था।

सलमान खान से महेश बाबू तक के छुड़ाए छक्के

जैसा अब्बा ने कह दिया वैसा ही होगा... कहकर जब फंस गई थीं मधुबाला, मांगनी पड़ी माफी

मधुबाला हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन खूबसूरत और लोकप्रिय अदाकारा थीं। उनका हंसमुख चेहरा और चुलबुलाहट लोगों की पहली पसंद हुआ करती थी। लेकिन, रुपहले पर्दे की लेकिन रूपहले पर्दे की चमकती दुनिया के पीछे उनकी एक दर्द भरी दुनिया भी थी। फिल्म निराला मधुबाला के हीरो देवानंद थे और मजहर खान साथी कलाकार थे। मजहर खान एक दिन फिल्म की शूटिंग दिखाने के लिए उन्होंने कुछ मेहमानों को आमंत्रित किया। सेट पर मेहमान पहुंचे तो अताउल्ला गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर देवेन्द्र मुखर्जी को वो शर्त याद दिलाई, जिसके बारे में मजहर खान नहीं जानते थे। उन्होंने मेहमानों को अंदर नहीं आने दिया और शूटिंग भी रुकवा दी। मजहर ने तब मधुबाला के पास जाकर अनुमति चाहिए तो उन्होंने भी अपने पिता के सुर में सुर मिलाते हुए कठोरता से कहां- जैसा अब्बा कहते हैं वैसा ही होगा वरना मैं आज शूटिंग इसी समय छोड़कर चली जाऊंगी। मधुबाला ने मजहर की प्रतिष्ठा और उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया। ये बात अब आग की तरह चारों तरफ फैल गई थी। पत्रकारों ने इस बात की जानकारी के लिए सीधे मधुबाला से बात करने की कोशिश की तो अताउल्ला ने उनकी बेज्जती कर वहां से भगा दिया। बाद में इंडो-पाक जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष के घर जाकर संगठन के उपस्थित सदस्यों से मधुबाला और उनके पिता दोनों को माफी मांगनी पड़ी थी।

सायरा बानो ने किया शॉकिंग खुलासा, कहा- मुझसे शादी करना चाहते थे संजय दत्त

बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो ने संजय दत्त को उनके 65वें जन्मदिन पर एक इमोशनल पोस्ट के लिख कर उन्हें बधाई दी। सायरा ने दिलीप कुमार के साथ संजय की एक अनदेखी तस्वीर साझा की और लिखा, संजय दत्त हमेशा मेरे लिए एक परिवार की तरह रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, अम्माजी से लेकर आपाजी, साहब और मैं, हमने उन्हें एक छोटे बच्चे से लेकर आज के एक शानदार व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखा है। सायरा बानो आगे लिखती हैं, मुझे अभी भी याद है जब नरगिस आपा हमारे घर किसी समारोह में आती थीं,

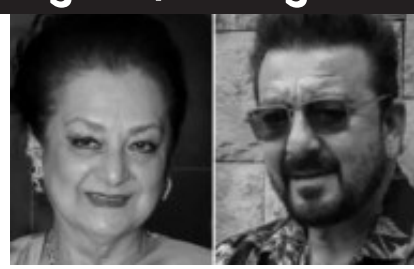

और वह उनके साथ जाता था- यह प्यारा, अच्छा दिखने वाला बच्चा, तब नरगिस जी उससे हाथ मिलाती थीं और कहती थीं, चलो, सायरा जी को बोलो तुम क्या बोलते हो मुझे? और फिर संजू मेरी तरफ देखते और प्यारी सी आवाज में कहते, मैं शैला बानो से शादी करूंगा। हाहाहा, कितना प्यारा! मुझे लगता है कि शर्मिला टैगोर और मैं संजू की सबसे पसंदीदा थे।

वह फिर आगे बताते हुए लिखती हैं, कई हाथों से मिलकर काम आसान हो जाता है और हम सभी को उनकी यात्रा का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला है। मेरे दिल में उनके लिए एक विशेष स्थान है। अपने प्यार और आशीर्वाद के साथ, मैं उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।

मूषक स्तोत्र

हे बगुलाभगत! लोग तो बगुला को ही बहुत बदनाम करते हैं, पर मेरी बुद्धि में आप उसके भी गुरु हैं, जैसा आप ध्यान लगाना, निगाह चूकने पर माल उड़ाना, देखते-देखते लोप हो जाना जानते हैं, बगुला के सहस्त्र पुरुष भी नहीं जानते। इस कर्तव्य में तो आप तांतिया भील हैं। हे गोपाल! दिन में तो आप बिल रुपी वृज में बैठे-बैठे गोचारणा करते, पर जहां रात्रि हुई कि आप अपनी गोपियों को लेकर गृहस्थियों में घरों में रासलीला करते, अतएव हे रासबिहारी! हम आपकी नई रास-पंचाध्यायी बनाएंगे!

हे गणेशजी के वाहन महागणेशमूषक! छोटा-सा रूप धारण करके कई मन के मोटे ताजे गणेशजी को उठा ले जाना या तो आपका ही काम है या इष्टीम ऐन जीन का ही काम है। यदि गणेशजी हजारों विघ्न नाश करते हैं तो आप करोड़ों अवश्य नाश करेंगे, तिसमें अपने ही स्त्रोत में। इसी से हम आप ही के स्त्रोत में आप ही का मंगलाचरण करते हैं! ओं श्री मन्महा महा गणाधिपतये मूषकेशाय नमः।। हे मूसे राम मामा! बालक जब उनके दुग्ध के दांत गिरते हैं, तब आपके बिल में रख देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने से दंत दो, पर आप न उनके लेते न अपने देते, इसी से न आप उघो के लेने में न माधो के देने में, अतएव आपको राम-राम!

हे मूसासिंह महाराज! आप दान करने में तो राजा कर्ण हैं। बहुधा बड़े आदमियों कि परम सुकुमारी कुमारी भूषण के भार से इधर-उधर अपने आभूषण रख देती, आप चट उन्हें डोरा काटने के लोभ से बिल में खींच ले जाते। जब कोई भाग्यवान आपके बिल स्पर्श का मार्जन करता तो उसे सुवर्ण के दाने, मोतियों के गुच्छे, हीरे की कनी मिलती हैं, अतएव आपकी बिल्ली पर विजय हो, मुझ दरिद्र ब्राह्मण को भी भिक्षान्देहि कृपावलम्बन करो हे मूषकाधीश्वरी! हे मूसामल भगत! हमने पुराणों से सुना है कि एक दिन आप किसी दीपक की जलती बत्ती मुंह में दाबकर कहीं भगवान मंदिर में चले गए, भगवान ने आपको दीपक दिखलाने वाला जान कर बैकुंठ दिया, अतएव जय श्रीकृष्ण! जय श्रीकृष्ण! हे मूषक महा मति! हमने रुक्मिणी मंडल में सुना है कि जब श्रीकृष्ण ने अपनी बरात में गणेशजी को बहुत मोटे, अतएव हास्यास्पद होने के कारण निमंत्रण नहीं दिया, तो तुमने बरात का सारा रास्ता पोला कर दिया। ज्योंही बरात चली कि धमाधम गड्ढों में गिर पड़ी, लाचार श्रीकृष्ण को गणेश बुलाने पड़े। हम अभी से अपने पड़पोते के विवाह का निमंत्रण दिए देते हैं, जरूर पधारिएगा।

मूसा पैगम्बर! दुनियां के आधे लोग तुम्हें परमेश्वर का दूत मानकर पूजा करते हैं, अतएव हमारा भी आदाब अर्ज। हे मिस्टर रैट्! एक दफा पूना के निकटस्थ जिलों में आपने हजारों खेतों का नाश कर दिया, तब लाचार सरकार ने रैट कमीशन बिठलाया, पर आप ऐसे बेशरम कि अब तक जीते हैं, अतएव गुड् मॉर्निंग।

हे चतुर्भुज! आपकी चारों भुजा धर्म अर्थ काम मोक्ष देती हैं, और दूसरे पक्ष में आपके वह पांव भी हैं, इससे आप चतुर्भुज और चतुष्पाद भी हैं, केवल शंख, चक्र या फिटन की देर है। हे बगुलाभगत! लोग तो बगुला को ही बहुत बदनाम करते हैं, पर मेरी बुद्धि में आप उसके भी गुरु हैं, जैसा आप ध्यान लगाना, निगाह चूकने पर माल उड़ाना, देखते-देखते लोप हो जाना जानते हैं, बगुला के सहस्त्र पुरुष भी नहीं जानते। इस कर्तव्य में तो आप तांतिया भील हैं। हे गोपाल! दिन में तो आप बिल रूपी वृज में बैठे-बैठे गोचारणा करते, पर जहां रात्रि हुई कि आप अपनी गोपियों को लेकर गृहस्थियों में घरों में रासलीला करते, अतएव हे रासबिहारी! हम आपकी नई रास-पंचाध्यायी बनाएंगे!

हे राजस की कतरनी, यदि चलुकमान हकीम ने आपके पकड़ने के लिए पिंजड़े बनवाए, पर आप उनको भी काट कर निकल जाते, अतएव आप बंबई-कलकत्ते की पिंजरापोल में भी न रहेंगे, हां इसी से हम भी मरे, और आप भी मरे! हे इतिश्री इतिश्री! शास्त्र में खेतों के नाश करने के लिए छः इति लिखी है, उनमें एक नंबर आप का भी है। हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर साहब को परामर्श देते हैं कि आपके लिए कोई जल्दी तजबीज करें। हे अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवै! आपके अनेक रूप हैं! कोई छोटे बालखिल्य के समान, कोई मोटे भीमसेन के प्रमान, कोई खोटे रावन की संतान, कोई उपद्रव करने में शैतान के शैतान, बस हम आपकी स्तुति गान करते हैं।

हे गुरु गोविंद! सब जातियों में गुरु, पुरोहित, पादरी होते हैं। आपकी जाति में भी पहाड़ी मूसा कुछ गौरवास्पद है, उसे देखकर आप कुछ डरते पर जहां वह आपके साथ घड़ी दो घड़ी किसी गृहस्थ के घर में रहे कि आपने उनका अदब कायदा सब छोड़ा। इससे यह दृष्टांत सच हुआ कि गुरु गुड़ ही रहे और चेला चीनी हो गए। हे शिक्षा गुरु वा परीक्षा गुरु! सबका कोई ना कोई गुरु अवश्य है, आपने भी यह चीरहरण माखन चोरी अवश्य किसी से सीखी होगी, कृपापूर्वक अपनी भगवद्गीता तो सिखाइए। हे प्रवाद प्रतिवाद! संसार का यह प्रवाद भी आप ही में घटता है कि जिस हंड़िया में खाय, उसी में छेद करै। बस आपसे बढ़कर कौन परच्छिद्रान्वेषी है?

हे मुक्तिदाता! जब बिल्ली ने नौ सौ मूसे खा लिए, तब उसे ज्ञान हुआ, वह मक्के को हज करने गई, और उसे मोक्ष हुआ, पर यदि वह सौ मूसे और खा लेती, तो फिर सदेह स्वर्ग को ही चली जाती। हे सिद्धि श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुणनिधांन! आपकी कहां तक स्तुति करें। आपके गुण गाते-गाते हम तो क्या शेष शारदा भी थक गए, बस आपकी प्रशंसा यहीं समाप्त करते हैं, और यह वर मांगते हैं कि और सब कुछ चाहे काट डालिए, पर इस मूषकस्त्रोत को न काटिए। यह आपका उन्नीसवीं शताब्दी का सर्टिफिकेट है, इसे यत्न से अपने बिल में रखिए, और इसे गले में तगमे की तरह लटका कर निकलिए।

● **राधाचरण गोस्वामी**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

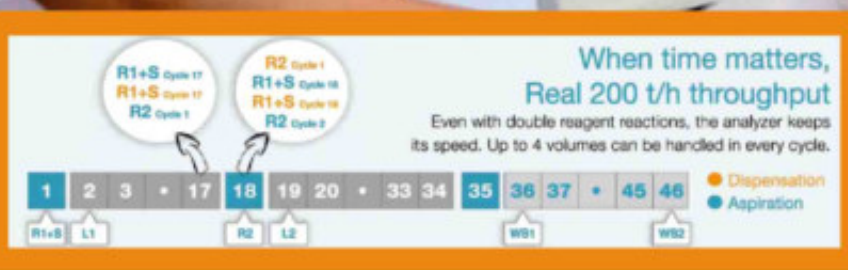

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन
प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in